राष्ट्रीय संस्करण

मोदी सरकार ने किया जम्मू-कश्मीर का पुनर्निर्माण

>> 5

वर्ष 7 अंक 234

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, गुरुवार, 1 फरवरी, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

मंदिर पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में मिला नियमित पूजा का अधिकार

अदालती आदेश ▸ 30 साल बाद व्यासजी के तहखाने में होगी नियमित पूजा-अर्चना

ज्ञानवापी का सच

अमरेंद्र तिवारी, वाराणसी

ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने में नियमित पूजा-अर्चना एक सप्ताह में शुरू होगी। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने यह आदेश बुधवार को व्यासजी का तहखाना जिलाधिकारी को सौंपने व उसमें पूजा-पाठ का अधिकार देने की मांग को लेकर पं. सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने वादी पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए तहखाने में स्थित मूर्तियों का नियमित पूजा-पाठ, राग-भोग कराने का भी निर्देश दिया है। अदालत के आदेश पर ही व्यासजी का तहखाना जिला प्रशासन ने अपनी अभिरक्षा में लिया है।

कोर्ट ने माना, तहखाने में होती थी पूजा : जिला जज ने अपने आदेश में वादी के प्रार्थनापत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। दिसंबर, 1993 के बाद पुजारी व्यासजी को उक्त प्रांगण के बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इस कारण तहखाने में होने वाला राग-भोग आदि रुक गया था।

सरकार और जिला प्रशासन ने बिना अधिकार के रोकी पूजा पेज>>5

- **दिसंबर, 1993 के बाद पुजारी व्यासजी को प्रांगण के बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश से रोक दिया गया था**
- **पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी व्यासजी ब्रिटिश शासन काल में भी वहां थे काबिज**

अब क्या

- **डीएम सात दिन में करेंगे नियमित पूजा की व्यवस्था**
- **काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड तय करेगा पुजारी का नाम**

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर। जागरण आर्काइव

अदालत के निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं। उक्त मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए थी। जिला जज के फैसले के खिलाफ हम उच्च न्यायालय जाएंगे।
– सैयद मोहम्मद यासीन, संयुक्त सचिव, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद (मस्जिद पक्ष)

जिला प्रशासन जैसी व्यवस्था करेगा उसके अनुरूप पूजा-पाठ शुरू होगा। यहां अब भक्तों और पुजारियों को जाने की अनुमति होगी। जो राम मंदिर में ताला खोलने का आदेश दिया गया था, आज का यह आदेश उसी प्रकार का है और टर्निंग प्वाइंट है।
– विष्णु शंकर जैन, अधिवक्ता, मंदिर पक्ष

न्यायालय का आदेश संज्ञान में है। आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने सात दिन का समय दिया है। –एस राजलिंगम, डीएम, वाराणसी

वुजूखाना सर्वे की याचिका विचारणीय : हाई कोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना क्षेत्र (शिवलिंग छोड़) का एएसआइ से सर्वे कराने की याचिका को विचारणीय माना है। सर्वे से इन्कार करने संबंधी जिला अदालत वाराणसी के आदेश को चुनौती दी गई है। (पेज-5)

हेमंत को ईडी ने किया गिरफ्तार, नए सीएम के लिए चम्पाई का दावा

राज्य ब्यूरो, रांची

- **गिरफ्तार किए जाने से पूर्व हेमंत ने राजभवन जाकर दिया इस्तीफा, राज्यपाल ने किया स्वीकार**
- **चम्पाई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा, अब राजभवन पर निगाहें**

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने रांची जमीन घोटाला मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले रांची स्थित सीएम आवास में ईडी ने उनसे दोपहर से रात आठ बजे तक लंबी पूछताछ की। रात लगभग साढ़े आठ बजे हेमंत ने राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपा, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। इस बीच महागठबंधन (झामुमो-कांग्रेस-राजद) ने झारखंड सरकार के मंत्री चम्पाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुनकर सीएम के रूप में उनका नाम आगे किया है। चम्पाई सोरेन ने महागठबंधन के 47 विधायकों के समर्थन का पत्र भी रात में ही राज्यपाल को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल अभी निर्णय लेने में एक-दो दिन का समय ले सकते हैं।

चम्पाई तीन बसों से सत्ता पक्ष के विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे थे। हेमंत की गिरफ्तारी की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, जिसे देखते हुए सत्ताधारी गठबंधन ने इसकी पुख्ता तैयारी कर नए सीएम के रूप में चम्पाई का चुनाव कर लिया था। हेमंत द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद ईडी अधिकारी उन्हें रांची स्थित जोनल कार्यालय ले गए। हेमंत को अब गुरुवार को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

बुधवार को ईडी के हाथों गिरफ्तार किए जाने के पूर्व हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। हेमंत की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी मूलवासी संगठनों ने गुरुवार को झारखंड बंद का एलान किया है।

हेमंत की गिरफ्तारी की खबरें बाहर आने के बीच रात आठ बजे तक राजभवन के बाहर विधायकों का जमावड़ा लग चुका था। सरकार में झामुमो की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने घोषणा की कि चम्पाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। राज्यपाल से आज ही चम्पाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर शपथग्रहण करा दें। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। हालांकि चम्पाई का नाम भी शुरू से विकल्प के तौर पर चर्चा में था। वह झामुमो के वरिष्ठ नेता हैं और वह सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। परिवहन मंत्रालय के साथ उनके पास आदिवासी कल्याण मंत्री का प्रभार भी है।

रांची में बुधवार को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से अपना त्यागपत्र झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा। इस दौरान चम्पाई सोरेन भी उपस्थित रहे। प्रेट्र

यह है जमीन घोटाला

मुख्यमंत्री हेमंत पर ईडी ने जिस मामले में शिकंजा कसा है, वह रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में स्थित कुछ महंगे भूखंडों से संबंधित है, जिनकी डीड में हेराफेरी कर अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि रांची समेत झारखंड में कई जगह भू माफिया का एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है जो सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से दस्तावेज में हेराफेरी कर ऐसे भूखंडों को भी अवैध तरीके से बेच रहा है, जिनकी खरीद-बिक्री नहीं हो सकती। जांच आगे बढ़ी तो ईडी ने रांची के उपायुक्त रहे छवि रंजन समेत कई अधिकारियों, दलालों और व्यवसायियों को गिरफ्तार किया। रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के आवास से बड़े पैमाने पर बरामद दस्तावेज के आधार पर हेमंत के करीबी पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की भूमिका सामने आई और बाद में पूर्व सीएम के इस मामले से तार जुड़े।

ईडी ने पूर्व में 41 ठिकानों पर की थी छापेमारी पेज>>6

जागरण विशेष

विद्यार्थियों को तनाव से दूर रखने के लिए अनूठी पहल

कुरुक्षेत्र : विद्यार्थी पढ़ाई संग तनावमुक्त वातावरण में उल्लास और ऊर्जा से देश की विरासत को जानें, समझें और सहेजें, इसके लिए एनआइटी कुरुक्षेत्र ने बड़ी पहल की है। ● पेज-7

संपादकीय

गणतांत्रिक मूल्यों से भटकता भारत : एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री की सहभागिता से हमारे गणतंत्र के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है। **कपिल सिब्बल** का दृष्टिकोण।

तीसरी बड़ी आर्थिकी का आसान लक्ष्य : वैश्विक स्तर पर गिरावट के बीच भी भारत सर्वाधिक एफडीआइ प्राप्त करने वाले देशों की सूची में बना हुआ है। डा. **जयंतीलाल भंडारी** का आलेख। ● पेज -8

दैनिक जागरण सप्तरंग
तकनीक की दुनिया का

आभासी दुनिया में सुरक्षा का सवाल

स्मार्ट रिंग स्मार्टवाच का विकल्प! ● पेज - 13

फास्टैग के लिए केवाईसी की समय सीमा बढ़ा सकती है एनएचएआइ पेज>>10

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से सच हुई सदियों की आकांक्षा : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का अभिभाषण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र**
- **मजबूत सरकार से बनी राम मंदिर व अनुच्छेद 370 हटाने जैसे बड़े फैसलों की राह**
- **मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों की दिखाई झलक**
- **अगले पांच साल के साथ भविष्य के 25 साल का बताया रोडमैप**
- **लोकसभा चुनाव से पूर्व मजबूत और स्थिर सरकार के फायदे बता दिया सियासी संदेश**

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के दौरान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों की नजीर में शामिल करते हुए कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण की सदियों की आकांक्षा अब सच हो गई है। राम मंदिर निर्माण के साथ जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक को गैरकानूनी बनाने से लेकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने जैसी उपलब्धियों का जिक्र कर राष्ट्रपति ने साफ संदेश दिया कि मोदी सरकार चुनावी वादों को हकीकत में बदलने के इरादों में विश्वास करती है। इन बड़े फैसलों का श्रेय पूर्ण बहुमत की सरकार को देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्थिर और मजबूत सरकार के लिए भारतीयों का संकल्प भी दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में राष्ट्रपति के स्थिर और मजबूत सरकार की बात के सियासी संदेश का आशय साफ है। राष्ट्रपति ने सरकार के अगले पांच साल के विकास का रोडमैप रखते हुए कहा कि सरकार का मानना है कि विकसित भारत की भव्य इमारत युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसानों और गरीबों के चार मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी।

संसद के नए भवन में अंतरिम बजट सत्र के पहले दिन संयुक्त अधिवेशन को लोकसभा चैंबर में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उल्लेख किया तब सत्तापक्ष ने जोरदार तालियों और नारेबाजी से उसका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने कहा- 'पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्य पूरे होते देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी। आज यह सच हो चुकी है।'

संसद के बजट सत्र के आरंभ अवसर पर बुधवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की अगवानी सेंगोल के साथ की गई। एएनआइ

भारत के लिए यह समय आने वाली सदियों का भविष्य लिखने का पेज>>3

नीतीश बोले-हमारे काम का झूठा श्रेय ले रहे लोग

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर एक साथ निशाना साधा है। कहा कि हमारे काम का लोग झूठा श्रेय ले रहे हैं। जातिवार गणना हमने नौ दलों को साथ लेकर कराई। (पेज-4)

एएमयू : ...तो वह अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता

नई दिल्ली : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले एक छात्र के वकील ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो समुदाय चुनाव पर असर डाल सकता है, वह अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। (पेज-7)

विमर्श

जिम्मेदार पहल से सुधरेगी व्यवस्था : निजी और सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बीच की खाई चौड़ी हो रही है। हाल ही में एक जिलाधिकारी ने अपने बच्चे का नामांकन आंगनबाड़ी में करवाया है। सभी को इससे सीख लेना चाहिए। **डा. अमरजीत कुमार** का दृष्टिकोण।

चुनावी मौसम में कांग्रेस के विक्षोभ : हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए आवश्यक है कि वह अपने भीतरी गणित और रसायन पर ध्यान दे। चुनावी मौसम के संदर्भ में इसे विश्लेषित कर रही है, **नवनीत शर्मा** की डायरी। ● पेज-9

वित्त मंत्री सीतारमण आज पेश करेंगी अंतरिम बजट

अंतरिम बजट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बुधवार को नई दिल्ली में अधिकारियों की अपनी टीम के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी तथा भागवत कराड़। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **पीएम ने दिए संकेत, देश के विकास का दिशा-निर्देशक होगा यह बजट**
- **हुड़दंग करने वाले सांसदों को दी आत्मनिरीक्षण की सलाह**

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के तौर पर उनका यह छठा और मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। यह बजट देश के विकास का दिशा-निर्देशक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को बजट सत्र आरंभ होने से पहले इसके साफ संकेत दिए। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरिम बजट ऐसे विकास का दिशा-निर्देशक होगा जो देश को अगले तीन वर्षों से भी कम समय में पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम होगा।

17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर आएंगे। इस बार दिशा-निर्देशक बातें लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मुझे दृढ़ विश्वास है कि देश आगे बढ़ रहा है और प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश समग्र और समावेशी विकास का अनुभव कर रहा है। लोगों के आशीर्वाद से यह यात्रा लगातार जारी रहेगी।'

मोदी ने मीडिया से वार्ता में 'राम राम' से शुरू की बात पेज>>5

मौसम का मिजाज

उत्तराखंड में पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर, लंबे समय बाद वर्षा, हिमाचल के मनाली और डलहौजी में इन सर्दियों की पहली हिमपात, जम्मू-कश्मीर में हिमपात से चमक उठे पर्यटन स्थल, त्रिकुटा पर्वत भी गिरी बर्फ

हिमपात ने पर्वतीय राज्यों को दी राहत

जागरण टीम/एएनआइ, नई दिल्ली

शीतकाल में लंबे सूखे के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बर्फबारी ने पर्वतीय राज्यों को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड में मंगलवार रात से चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी बुधवार को भी जारी रही। हिमाचल प्रदेश के मनाली, डलहौजी व कुफरी में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जम्मू-कश्मीर में ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश हुई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा, जहां हल्की बारिश हो सकती है। आइएमडी ने आगामी 4 फरवरी तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा व बर्फबारी होने की संभावना जताई है।

उत्तराखंड में गंगोत्री-यमुनोत्री सहित हर्षिल घाटी, खरसाली, हरकीदून में बर्फबारी हुई। बदरीनाथ धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब, गोरसो, औली की चोटियों पर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में तीन हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है। कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई। अनंतनाग जिले के कोकरनाग, कुपवाड़ा के हंदवाड़ा और बांडीपोरा के गुरेज में भी हिमपात हुआ। (दिल्ली का मौसम। पेज 2 पर)

हिमपात से अटल टनल बंद

हिमाचल में लगभग ढाई महीने बाद वर्षा व हिमपात से लोगों ने राहत महसूस की है। रोहतांग स्थित अटल टनल में दो फीट हिमपात हुई, जिसकी वजह से उसे पर्यटकों के लिए बंद करना पड़ा। लाहुल-स्पीति जिले के दयपुर में सवा फीट, तिंदी में एक फीट व पांगी में आधा फीट हिमपात हुई। मनाली, डलहौजी और नारकंडा में इन सर्दियों में पहली बार हिमपात हुआ। मनाली में पर्यटक बर्फ के फाहों का आनंद लेते रहे।

कोहरे के कारण 50 से अधिक उड़ानें और कई ट्रेनें विलंबित

कोहरे के कारण यातायात सेवाओं पर असर पड़ा। दिल्ली में आइजीआइ एयरपोर्ट पर 51 उड़ानें विलंबित हुईं और 11 अन्य रद कर दी गईं। कोहरे के कारण ट्रेनों को विलंब से चलना जारी है। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें घंटों देर से दिल्ली पहुंचीं।

मंगलवार की रात से गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हुई जो बुधवार को भी जारी रही। साभार : सतोष सेमवाल, तीर्थ पुरोहित >>

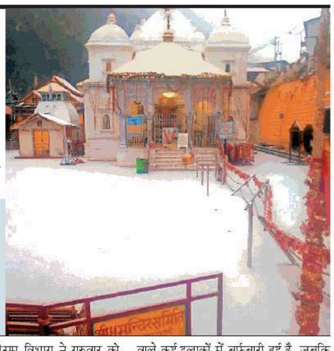

अब ममता ने दिए आइएनडीआइए से अलग होने के साफ संकेत

जागरण टीम, मालदा / मुर्शिदाबाद

- **तृणमूल सुप्रीमो की घोषणा, बंगाल में कांग्रेस को नहीं देंगे एक भी सीट**

आइएनडीआइ गठबंधन को एक और झटका देते हुए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि तृणमूल बंगाल में कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ेगी। ममता ने कहा कि भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी माकपा के साथ गठबंधन की जिद पर अड़ी है। मैंने वामदलों की बहुत मार सही है। उनके साथ रहने वालों को भी मंजूर नहीं करूंगी। तृणमूल अकेले चलने की राजनीति में विश्वास करती है और पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी।

मालदा और मुर्शिदाबाद में सभाओं को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि पहले हमने सोचा था कि कांग्रेस को दो सीट देंगे, लेकिन उन्हें और अधिक चाहिए। विधानसभा में उनका एक भी विधायक नहीं है तो क्या हम उन्हें कुल 42 सीट ही दे दें ? पहले वह सोच रही थीं कि कांग्रेस से चुनावी गठबंधन करेंगी, लेकिन अब कोई गठबंधन नहीं होगा। मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में एक सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि कांग्रेस के साथ मेरे अच्छे संबंध थे, लेकिन माकपा के चलते हमारा संपर्क खराब हुआ है।

माकपा ने किया पलटवार

माकपा नेता शमिक लाहिड़ी ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी आरएसएस के निर्देश पर विपक्षी आइएनडीआइए को तोड़ने के लिए इसमें शामिल हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और भाजपा के बीच गुप्त समझौता है।

****

21 कोर्स की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल आफ ओपन लर्निंग (एसओएल) ने कौशल आधारित शिक्षा के लिए सेंटर फार इनोवेटिव स्किल्स-बेस्ड कोर्सेस (सीआइएसबीसी) के तहत की है। बुधवार को डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने इसकी शुरुआत की।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 1 फरवरी, 2024

आज का मौसम

सामान्यतया बादल छाए रहेंगे।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
1 फरवरी	19.0	08.0
2 फरवरी	20.0	07.0
नोएडा		
1 फरवरी	20.0	13.0
2 फरवरी	20.0	12.0
गुरुग्राम		
1 फरवरी	18.0	10.0
2 फरवरी	17.0	12.0

डिग्री सेल्सियस में

वर्षा से बदला मौसम का मिजाज, चार डिग्री गिरा तापमान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- बुधवार को दिनभर दिल्ली में छाए रहे बादल, तेज हवा के साथ कहीं हल्की तो कहीं हुई तेज बारिश
- सुबह कोहरे ने किया परेशान, आइजीआइ एयरपोर्ट पर घंटों तक शून्य रहा दृश्यता स्तर

नई दिल्ली में बुधवार को वर्षा और ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर कुछ तरह का नजारा दिखा। ध्रुव कुमार

तेज हवा के साथ हुई वर्षा ने बुधवार को एक बार फिर राजधानी के मौसम का मिजाज बदल दिया। तापमान में चार डिग्री की गिरावट आई। दिनभर बादल छाए रहने और वर्षा होने से ठिठुरन का एहसास भी बढ़ गया। गुरुवार को भी हल्की वर्षा का यह दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने दो दिन के लिए वर्षा और कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।

मंगलवार की तरह बुधवार को भी दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। आइजीआइ एयरपोर्ट पर सुबह साढ़े पांच बजे से कई घंटों तक दृश्यता का स्तर शून्य बना रहा। इसका असर विमान सेवा और ट्रेनों पर भी पड़ा। 52 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों समेत 287 उड़ानों में विलंब देखा गया। वहीं 100 से अधिक ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंची और 20 के प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ा।

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार बादल तो दिन भर छाए ही रहे। बहुत थोड़े समय के लिए हल्की धूप निकली। एक बजे के बाद फिर बादल घने होने लगे। दोपहर डेढ़ बजे के आसपास तेज हवा के साथ हल्की वर्षा शुरू हो गई। वर्षा का यह दौर रुक रुककर देर शाम तक जारी रहा। कहीं हल्की तो कहीं तेज वर्षा हुई। शाम साढ़े पांच बजे तक दिल्ली में 8.5 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिसंबर के बाद जनवरी का पूरा महीना भी अभी तक सूखा ही बीता था। पश्चिमी विक्षोभ के असर से माह के अंतिम दिन वर्षा हुई लेकिन तब भी यह सामान्य से काफी कम है। मालूम हो कि माह की सामान्य वर्षा 19.5 मिमी है।

दिल्ली का अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से चार डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से एक डिग्री कम है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार की सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। दिन में हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम आठ डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की गति 18 से 24 किमी प्रति घंटे तक की हो सकती है। शुक्रवार की सुबह भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसी के चलते मौसम विभाग ने दो दिनों का यलो अलर्ट जारी किया है।

ऐसा रहा है मौसम का मिजाज

- 2023-24 में दिल्ली में दिसंबर और जनवरी में कुल 20 दिन में 128 घंटे रहा अति घना कोहरा रहा
- यह पिछले 10 साल के दौरान तीसरा सबसे अधिक कोहरा था। इस दौरान सबसे अधिक कोहरा 2014-15 में छाया था
- जनवरी 2024 के दौरान 14 दिन में 88 घंटे कोहरा रहा। यह जनवरी महीने में पिछले दस सालों का दूसरा सबसे लंबा कोहरे का स्पैल है। इससे पहले 2014-15 में जनवरी में सबसे घना कोहरा देखने को मिला था
- 1951-2024 के दौरान एक से 30 जनवरी तक दिल्ली का औसत तापमान 17.7 डिग्री रहा। यह पिछले 74 सालों में दूसरा सबसे ठंडी जनवरी है। इससे पूर्व इस दौरान जनवरी 2003 का औसत अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री रहा था।

एक्यूआइ फिर 'गंभीर' श्रेणी की दहलीज पर, आज से सुधार के आसार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से 'गंभीर' श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गया है। बुधवार को यहां के 20 इलाकों का एक्यूआइ 400 के पार यानी 'गंभीर' श्रेणी में रहा। राहत की बात यह है कि दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। इससे अगले दो दिनों में प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 रहा। इस स्तर की हवा को 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन, यह 'गंभीर' श्रेणी से सिर्फ नौ अंक कम है। एक दिन पहले मंगलवार को यह 357 रहा था। चौबीस घंटे के भीतर इसमें 35 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। सीपीसीबी के मुताबिक बुधवार को शाम चार बजे दिल्ली की हवा में पीएम 10 का स्तर 308 और पीएम 2.5 का स्तर 184 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। यानी दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों का औसत स्तर मानकों से तीन गुना ज्यादा है।

न्यूज गैलरी

संजय सिंह की जमानत पर हाई कोर्ट का निर्णय सुरक्षित

नई दिल्ली : आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने बुधवार को संजय सिंह और ईडी का पक्ष सुना। संजय सिंह ने कहा कि वह पिछले तीन महीने से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। संजय सिंह को ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। (जासं)

सुपरटेक चेयरमैन की याचिका पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा की उस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा, जिसमें मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इन्कार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए 21 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। ग्रुप पर 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। (जासं)

खालिस्तान समर्थक नारे लिखने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली : द्वारका और पश्चिमी जिले की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में खालिस्तान समर्थक नारे लिखने तथा ग्रैफिटी बनाने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान तिलक नगर के जसविंदर उर्फ लकी के रूप में हुई है। उसे अमेरिका में रहने वाले उसके दोस्त ने नारे लिखने के लिए कहा था। इसके लिए उसे 15 हजार रुपये देने की बात कही गई थी, लेकिन उसे रुपये नहीं दिए गए। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 26 जनवरी को तिलक नगर थाना क्षेत्र के एमसीडी पार्क की दीवार पर खालिस्तान समर्थक आपत्तिजनक नारे लिखे गए थे। (जासं)

केजरीवाल को पांचवां समन

ईडी ने आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में जारी किया समन

पिछले चार समन पर नहीं हुए पेश, समन को बता चुके हैं अवैध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- एजेंसी नए पूरक आरोपपत्र में आप को नामित कर सकती है 'लाभार्थी'
- आप ने आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों का बार-बार किया है खंडन

अरविंद केजरीवाल। सौजन्य : आप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को पांचवां समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें दो फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल पिछले चार महीने में ईडी द्वारा जारी किए गए चार पूर्व समन पर पेश नहीं हुए हैं।

केजरीवाल को गत 21 दिसंबर, दो नवंबर, तीन जनवरी और 18 जनवरी को बुलाया गया था। उन्होंने समन का विरोध करते हुए इसे अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था। केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने समन पर कानूनी आपत्तियों का हवाला दिया था और एजेंसी पर 'न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद' की भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। इस बार भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, इसकी संभावना कम है।

ताजा नोटिस जारी करके ईडी ने केजरीवाल की इस दलील को फिर से खारिज कर दिया है कि उन्हें जारी किए गए समन कानून के अनुरूप नहीं थे। मामले में ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि आरोपित अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की तैयारी के संबंध में उनके संपर्क में थे। इस मामले में अब तक आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा आप नेता विजय नायर और कुछ कारोबारियों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि आप ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपये की 'अपराध की आय' का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है कि एजेंसी मामले में एक नया पूरक आरोपपत्र दाखिल कर सकती है और आप को आबकारी नीति के माध्यम से उत्पन्न कथित रिश्वत के 'लाभार्थी' के रूप में नामित कर सकती है। यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। उधर आप ने इस आरोप का बार-बार खंडन किया है।

कानूनी टीम समन का अध्ययन कर रही है : आप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को कहा कि उसकी कानूनी टीम नोटिस का अध्ययन कर रही है और समन पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। आप की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हमें पांचवें समन के बारे में खबर मिली है। हमारी कानूनी टीम इसका अध्ययन कर रही है और हम तय करेंगे कि कानून के अनुसार क्या करना है। पहले के समन अवैध थे और हमने प्रवर्तन निदेशालय से उन पर जवाब मांगा था मगर ईडी की ओर से जवाब नहीं आया था।

दिल्ली सरकार ने जारी की एमसीडी को 803 करोड़ की तीसरी किस्त

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एमसीडी के लिए 803.69 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी की है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर तीसरी किश्त जारी करने को मंजूरी दी गई है। इससे एमसीडी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता रहेगा।

दिल्ली सरकार का कहना है कि एमसीडी को दी जाने वाली राशि प्रतिवर्ष बढ़ रही है। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2023-24 में 309 प्रतिशत राशि बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में 854.5 करोड़ की तुलना में 2023-24 में 2642.47 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सरकार इसके अतिरिक्त कई अन्य मदों में भी एमसीडी को राशि मुहैया कराती रही है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि एमसीडी के सफाई कर्मचारियों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, डाक्टरों आदि को समय से वेतन का भुगतान होगा। सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में एमसीडी को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा शासित एमसीडी में हमेशा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा की गई और उन्हें महीनों तक वेतन नहीं मिलता था। बता दें कि भाजपा पहले आरोप लगाती रही है कि आप एमसीडी को सहयोग नहीं करती है।

शराब कारोबारियों से वसूली मामले में आइएएस से होगी पूछताछ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- एलजी के निर्देश पर पिछले सप्ताह भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दर्ज किया था केस
- दो दिन के अंदर अमरनाथ तलवड़े को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजेगी एसीबी

दिल्ली के शराब विक्रेताओं से अधिक पैसा वसूलने के लिए दबाव बनाने वाले आइएएस अधिकारी अमरनाथ तलवड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते सप्ताह उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर केस दर्ज करने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) अब तलवड़े से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नोटिस तैयार कर लिया गया है। दो दिन के अंदर एसीबी उन्हें दिल्ली आकर जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज देगी। तलवड़े इस समय अरुणाचल प्रदेश में तैनात हैं। एसीबी के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा का कहना है कि गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन व अन्य व्यस्तता के कारण जांच शुरू नहीं की गई थी। एसीपी स्तर के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे।

बता दें कि एक आडियो क्लिप में आइएएस अधिकारी को अपने अधीनस्थ अधिकारी पर शराब विक्रेताओं से अधिक पैसा इकट्ठा करने के लिए दबाव डालते और इस रकम में अधिक हिस्सा मांगते पाया गया था। एफएसएल जांच में उनकी आवाज की पुष्टि हो जाने के बाद एलजी ने तलवड़े के खिलाफ केस दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने गृह मंत्रालय से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की है। मामला वर्ष 2015-16 का है। उस दौरान तलवड़े दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड (डीएससीएससी) में वरिष्ठ महाप्रबंधक के पद पर तैनात थे।

आरोप है कि उन्होंने डीएससीएससी के प्रबंधक पीके शाही (अब सेवानिवृत्त) पर शराब कारोबारियों से पैसे एकत्र करने का दबाव बनाया था और उन्हें स्थानांतरित कर देने की धमकी दी थी। दोनों अधिकारियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत की आडियो क्लिप सामने आई थी। एफएसएल की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि काल रिकार्डिंग सही है। बातचीत में तलवड़े ने यह भी कबूल किया था कि उन्हें डीएससीएससी का चार्ज संभालने के तुरंत बाद शाही से पांच लाख रुपए मिले थे। तलवड़े डीएससीएससी में 12 जनवरी 2015 से 29 अप्रैल 2016 तक दिल्ली में तैनात थे। नोएडा के एक व्यक्ति ने 21 मार्च 2023 को सतर्कता निदेशालय को शिकायत दी थी। आडियो क्लिप का पेन ड्राइव भी सौंपा था। आरोप लगाया था कि बातचीत एक आइएएस अधिकारी और एक इंस्पेक्टर में हो रही है जो किसी आबकारी मामले में रिश्वत की बात कर रहे हैं।

चिकित्सा उपकरणों के संबंध में भ्रामक जानकारी पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- अस्पतालों में बुनियादी ढांचे से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है दिल्ली हाई कोर्ट
- कहा, सही तथ्य पेश करें तो आरोप-प्रत्यारोपण में पड़ने के बजाय अदालत करना चाहती है मदद

दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में भ्रामक जानकारी पेश करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अहम टिप्पणी की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि अदालत आरोप-प्रत्यारोपण में पड़ने के बजाय अस्पतालों की स्थिति ठीक करने में मदद करना चाहती है, लेकिन इसके लिए सरकार को जमीनी हकीकत के संबंध में उसके सामने सही तथ्य रखने चाहिए। अदालत अस्पतालों में आइसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित वर्ष 2017 में शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

पीठ ने कहा कि अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि संरचनात्मक सुधार हो। अस्पतालों में रिक्तियों और जनशक्ति की कमी के मामले पर अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और दिल्ली सरकार (सेवा) विभाग को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया। सभी को समाधान निकालने के लिए डाक्टरों की एक समिति गठित करने का भी सुझाव दिया। कोर्ट ने चिकित्सा ढांचे की जांच के लिए समिति गठित करने पर सरकार से रुख पूछा है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सत्यकाम ने पीठ को सूचित किया कि सरकार सिरसपुर, मादीपुर, ज्वालापुरी और हस्तसाल में कुल 3237 बिस्तरों वाले चार नए अस्पताल शुरू करने की योजना बना रही है और इसे अगले दो से तीन वर्षों में चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार सरकारी अस्पतालों के मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे में 5000 बिस्तर बढ़ाने की योजना बना रही है। सत्यकाम ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए पैसा कभी कोई समस्या नहीं है और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, लेकिन असली समस्या यह है कि उसके पास इन अस्पतालों में काम करने के लिए लोग नहीं हैं। इस पर पीठ ने सवाल उठाते हुए टिप्पणी की कि अदालत में सरकार हमसे कहती रहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। आज ही आप कह रहे हैं कि पैसा है, कल तक आप कह रहे थे कि पैसा नहीं है। पीठ ने कहा कि कोर्ट सरकारी अस्पतालों में मौजूदा चिकित्सकीय बुनियादी ढांचे को ठीक करने में सरकार की मदद करना चाहती है लेकिन अगर तस्वीर पेश नहीं की गई तो वह ऐसा नहीं कर पाएगी।

जवाब नहीं देने पर दिल्ली सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली के वनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त वन अधिकारियों की तैनाती की मांग वाली याचिका पर बार-बार निर्देशों के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि मामले में जवाब दाखिल नहीं करने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई वैध कारण नहीं बताया गया है और अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करना अदालत की गरिमा के विरुद्ध है।

अदालत ने कहा कि दो अगस्त 2023 और 21 सितंबर 2023 को दिए गए आदेशों के बावजूद सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इसकी सिर्फ यह वजह बताई कि कुछ जानकारी दूसरे राज्यों से मंगाई जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल नहीं करने का यह कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने यह आदेश वन एवं वन्यजीव विभाग में पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की तैनाती करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिया।

राज्यसभा में स्वाति समेत तीन नए सदस्यों ने ली शपथ

आप नेता स्वाति मालिवाल ने बुधवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा में बुधवार को तीन नए सदस्यों सतनाम सिंह संधू, नारायण दास गुप्ता और स्वाति मालीवाल ने शपथ ली। बाद में सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने संधू से कहा कि आपने इतिहास रचा है क्योंकि आप संसद के नए भवन में शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस बीच, मालीवाल को दोबारा शपथ लेनी पड़ी क्योंकि पहली बार उनके शपथ लेने पर सभापति ने विचार नहीं किया। इसलिए दोबारा उनका नाम पुकारा। उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जो शपथ का हिस्सा नहीं थे। संधू जहां मनोनीत सदस्य हैं, वहीं गुप्ता और मालीवाल दिल्ली से निर्विरोध चुने गए। गुप्ता को आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्यसभा सदस्य के रूप में फिर से नामित किया है, जबकि मालीवाल को पार्टी ने सुशील गुप्ता के स्थान पर नामित किया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति संधू को मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया।

दिल्ली सरकार बनाएगी यातायात का हीट मैप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार कैब के स्थान निर्देशांक का उपयोग करके शहर के यातायात और वाहनों की आवाजाही वाले इलाकों, पसंदीदा पिक एंड ड्राप क्षेत्रों और उच्च यात्रा घनत्व वाले क्षेत्रों का हीट मैप बनाने की योजना बना रही है। इस जानकारी का उपयोग नीति बनाने और भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ावा देने में भी लाभ मिलेगा।

परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने नई कैब एग्रीगेटर नीति के तहत शहर में कैब आपरेटरों को अपने वाहनों के स्थान का डेटा साझा करने की आवश्यकता का लाभ उठाते हुए यह कदम उठाया है। सरकार का लक्ष्य इस हीट मैप का उपयोग भविष्य की नीतियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के इंस्टालेशन और ड्राप-आफ प्वाइंट विकसित करने का है। अधिकारी ने कहा कि कैब नीति के तहत एग्रीगेटर्स को अपनी सेवाओं में एक ऐसी सुविधा शामिल करनी होगी, जिससे एप के माध्यम से बुक की गई सवारी लाइव लोकेशन और स्थिति साझा कर सके।

सख्ती

चालान की कार्रवाई के लिए 25 पेट्रोल पंपों पर लगाए गए विशेष कैमरे, पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाने को वाहन मालिकों को मिलेगा तीन घंटे का समय, परिवहन विभाग ने ट्रायल के तौर पर ई-चालान की शुरू की है प्रक्रिया

बिना पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों का पेट्रोल पंपों पर कटेगा चालान

वी के शुक्ला, नई दिल्ली

बगैर प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र वाले वाहन अब कार्रवाई से बच नहीं सकेंगे। अब पेट्रोल पंपों से इन वाहनों का चालान काटा जाएगा। परिवहन विभाग ने चालान की कार्रवाई के लिए दिल्ली के 25 पेट्रोप पंपों पर विशेष कैमरे लगाए हैं। कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पढ़कर पता लगा लेंगे कि पीयूसी प्रमाणपत्र है या नहीं। अगर पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है तो वाहन के मालिक के मोबाइल नंबर पर संदेश आएगा कि इसे तुरंत बनवा लें। इसके बाद तीन घंटे समय में प्रमाणपत्र नहीं बनवाते हैं, तो ई-चालान काट दिया जाएगा। ट्रायल के तौर पर यह व्यवस्था पिछले सोमवार से शुरू की गई है।

दिल्ली में 950 स्थानों पर पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा उपलब्ध है। राजधानी के हर जिले में कम से कम दो पेट्रोल पंपों पर विशेष कैमरे लगाए गए हैं। कुछ जिलों में तीन पेट्रोल पंपों पर यह व्यवस्था की गई है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन 25 पेट्रोल पंपों की लोकेशन को उजागर नहीं किया जाएगा। इसका पता लगने से लोग इन पेट्रोल पंपों पर नहीं जाएंगे। पेट्रोल पंप मालिकों को विश्वास में लिया गया है कि उनके पंप की लोकेशन नहीं बताई जाएगी। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विभाग ने माडल टाउन, शास्त्री नगर, माल रोड और शाहदरा के चार पेट्रोल पंपों पर पीयूसी प्रमाणपत्र वैधता सत्यापन प्रणाली स्थापित की थी। इस दौरान करीब 20 प्रतिशत वाहन बगैर पीयूसी प्रमाणपत्र के पाए गए। वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होने पर 10 हजार रुपये का चालान काटा जाता है।

गौरतलब है कि कैमरा नंबर प्लेट को स्कैन करके पता लगा सकता हैं कि वाहन का वैध पीयूसी प्रमाणपत्र है या नहीं। वाहनों का कार्बन मोनोआक्साइड (सीओ) और कार्बन डाइआक्साइड (सीओ2) जैसे विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन मानकों के लिए समय-समय पर परीक्षण किया जाता है, जिसके बाद उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र दिया जाता है। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बहुत सारे लोग अपने वाहनों का उपयोग स्थानीय स्तर पर करते हैं और पकड़े जाने से बच जाते हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों पर तकनीक स्थापित होने से ऐसा नहीं कर पाएंगे।

पीयूसी जांच की मौजूदा दरें

60 रुपये	दोपहिया वाहन
80 रुपये	पेट्रोल एवं सीएनजी कार
100 रुपये	डीजल वाहन

(नोट : 18 % जीएसटी अलग से वसूला जाता है)

पेट्रोल पंप पर स्थित प्रदूषण जांच बूथ। जागरण

राजधानी नई दिल्ली स्थित एक पेट्रोल पंप। जागरण

अमृत उद्यान में सुंदर फूलों के साथ दिखेंगे बोनसाई के 300 पौधे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी अमृत उद्यान उत्सव 2024 का उद्घाटन
- दो फरवरी से आमजन के लिए खुल जाएगा उद्यान

खूबसूरती और रंगबिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 225 साल पुराने शीशम के पेड़ की कहानी भी सुनने को मिलेगी। इसके अलावा बोनसाई के 300 पौधे भी आकर्षण का केंद्र होंगे। गुरुवार को द्रौपदी मुर्मु अमृत उद्यान उत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद शुक्रवार यानि दो फरवरी से अमृत उद्यान को आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। खास बात यह है कि मेट्रो से आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए मुफ्त शटल सेवा की केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से राष्ट्रपति भवन तक चलाई जाएगी।

लोग अमृत उद्यान देखने के लिए आनलाइन टिकट पहले से भी बुक कर सकेंगे। राष्ट्रपति भवन की उप प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने बताया कि 50 हजार से ज्यादा लोगों ने अमृत उद्यान घूमने के लिए पहले ही टिकट बुक कर लिया है। इस बार उद्यान में पर्यटक 'डबल डिलाइट', 'सेंटीमेंटल' और 'कृष्णा' नाम के गुलाबों को देख सकते हैं।

आनलाइन अग्रिम टिकट बुकिंग की सुविधा: नागरिक अपनी सहूलियत और लंबी लाइन से बचने के लिए अमृत उद्यान की टिकट आनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। राष्ट्रपति भवन के अनुसार https://rashtrapatisachivalaya.gov.in या https://rb.nic.in/rbvisit/visit_plan.aspx आनलाइन अग्रिम टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान की गई है।

****

84 लाख से अधिक लोग विश्वकर्मा योजना से जुड़ चुके हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि मदद के अभाव में विश्वकर्मा साथी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। अब सरकार ने उनकी सुध ली है।

इन्फ्रा विकास में भारत का लोहा दुनिया ने माना : मुर्मु

कामकाज का ब्योरा ▶ भारत जैसा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं, धांधली रुकी और जीवन सुगम हुआ

सड़क, रेल और हवाई सेवाओं के बुनियादी ढांचे में हुई रिकार्ड प्रगति

मनीष तिवारी, नई दिल्ली

मोदी सरकार के कार्यकाल में दस वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर सबसे अधिक जोर रहा है और इसकी झलक बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण में भी दिखाई दी। उन्होंने डिजिटल और फिजिकल, दोनों तरह के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों का ब्योरा दिया और यह घोषणा भी की कि आज पूरी दुनिया भारत की इस उपलब्धि को मान-समझ रही है। मुर्मु ने कहा कि विकसित देशों में भी भारत जैसा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में रिकार्ड निवेश हुआ है, जिसके कारण सड़क, रेल और हवाई सेवाओं का एक ऐसा बुनियादी ढांचा बन गया है जिसका सपना हर भारतीय देखता था।

मोदी सरकार इन क्षेत्रों में हुए कार्यों का श्रेय लेती है और एक के बाद एक उसकी चुनावी सफलताओं का इसे एक बड़ा कारण भी माना जाता है। मुर्मु ने कहा कि मोदी सरकार का एक बड़ा सुधार डिजिटल भारत का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस, दोनों को आसान बना दिया है। गांवों में भी सामान्य खरीद बिक्री डिजिटल तरीके से होगी, यह लोगों की कल्पना से भी परे था। राष्ट्रपति ने अपनी बातों के समर्थन में यह आंकड़ा भी रखा कि आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन-देन का 46 प्रतिशत भारत में होता है। यह किस ऊंचाई तक पहुंच चुका है, इसका प्रमाण यह है कि पिछले महीने यूपीआइ से रिकार्ड 1200 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। दूसरे देश भी यूपीआइ से लेन-देन की सुविधा दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया के कारण बैंकिंग आसान हुई। उन्होंने सरकार की इस कामयाबी को भी रेखांकित किया कि जनधन आधार मोबाइल यानी जेएएम की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिली है। इस जेएएम के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं, जबकि 34 लाख करोड़ रुपये डीबीटी के जरिये ट्रांसफर हुए हैं। फर्जी लाभार्थियों के सिस्टम से बाहर होने के कारण करीब तीन लाख करोड़ रुपये गलत हाथों यानी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचे हैं।

नई दिल्ली में बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु। एएनआइ

इस तरह बढ़ा इन्फ्रा का ढांचा

- दो लाख ग्राम पंचायतें आप्टिकल फाइबर से जुड़ीं
- चार लाख से अधिक काम सर्विस सेंटर खुले
- दस हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई
- वन नेशन, वन पावर ग्रिड से बिजली की व्यवस्था सुधरी
- पांच शहरों तक सीमित मेट्रो अब 20 शहरों में।

दस सालों में गांवों में पौने चार लाख किलोमीटर नई सड़क बनीं

राष्ट्रपति ने भौतिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले दस सालों में गांवों में पौने चार लाख किलोमीटर नई सड़क बनी हैं, नेशनल हाईवे की लंबाई 90 हजार से बढ़कर डेढ़ लाख किलोमीटर हो गई और फोर लेन नेशनल हाईवे की लंबाई ढाई गुना बढ़ गई। भारत किस तरह आधुनिक दुनिया से कदमताल मिल रहा है, इसका उदाहरण है हाईस्पीड कारिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर से बढ़कर 4,000 किलोमीटर हो जाना। मुर्मु ने इस दौरान रेलवे के कायाकल्प का भी जिक्र किया और कहा कि पिछले दस सालों में 25 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं जो कई विकसित देशों के कुल रेलवे ट्रैक से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत रेलवे के शत प्रतिशत विद्युतीकरण के बहुत निकट है। देश में पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हुई है। आज 39 से ज्यादा रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि दस सालों में एयरपोर्टों की संख्या 74 से बढ़कर 149 हो चुकी है। देश के बड़े बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी दोगुनी हो गई। ब्राडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या 14 गुना बढ़ गई।

नई परंपरा के तहत सेंगोल के साथ राष्ट्रपति का स्वागत

- राज्य व्यवस्था के नए सांस्कृतिक प्रतीक को पहली बार स्वागत और विदाई के लिए किया गया इस्तेमाल
- अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति के सामने किया गया स्थापित, सबसे वरिष्ठ मार्शल ने शुरू की परंपरा

राष्ट्रपति का सेंगोल से स्वागत करते संसद के मार्शल। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नया संसद भवन बुधवार को एक अनोखी, आकर्षक और नई परंपरा का भी गवाह बना। भारतीय राज्य व्यवस्था के नए सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उभरे सेंगोल को बजट सत्र की शुरुआत के अवसर पर जिस तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की अगवानी और उन्हें विदा करने के क्रम में प्रयोग किया गया, वह अभिभाषण से इतर दिन के सबसे बड़े आकर्षण के रूप में नोट किया गया।

नए संसद भवन में यह दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक थी, राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण और लोकसभा के मौजूदा सदस्यों के लिए मेल-मिलाप का आखिरी सत्र। राष्ट्रपति मुर्मु के संसद परिसर में आगमन से पहले ही सेंगोल को उसके लिए निर्धारित स्थान स्पीकर के आसन के दायें कोने में से निकालकर पूरे सम्मान के साथ गज द्वार तक ले जाया गया, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

संयुक्त सत्र की बैठक के लिए लोकसभा हाल तक आने के क्रम में सेंगोल को उनसे पांच-छह कदम की दूरी पर लोकसभा के वरिष्ठ मार्शल राजील शर्मा आगे-आगे लेकर चले। इस दौरान संगीतकारों के एक दल ने परंपरागत स्वागत ध्वनि बजाई। जब राष्ट्रपति अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गईं तो सेंगोल को राष्ट्रपति के सामने लोकसभा महासचिव की मेज के आगे स्थापित किया गया। इस नई परंपरा में सदन में तैनात मार्शल पीले रंग की कुर्ते-पाजामे की परंपरागत पोशाक, स्कार्फ और पगड़ी पहने हुए थे। सेंगोल के प्रति अद्भुत श्रद्धा और सम्मान का प्रदर्शन करते हुए मार्शल ने उसे मूल स्थान से हटाने और अस्थाई रूप से नई जगह स्थापित करने के दौरान प्रणाम भी किया और इस पूरे प्रसंग के दौरान नंगे पैर भी रहे। मुर्मु छह घोड़ों वाली अपनी बग्घी पर सवार होकर अपने सुरक्षाकर्मियों के दस्ते के साथ संसद भवन पहुंचीं थीं। दोनों सदनों के सदस्यों ने मेजें थपथपा कर उनका स्वागत किया तो सत्ताधारी भाजपा के सांसदों ने भारत माता की जय, जय श्रीराम और जय सियाराम जैसे नारों के साथ मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया।

राष्ट्रपति की विदाई के समय भी सेंगोल को उसी तरह गज द्वार तक ले जाया गया और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी उपस्थिति में उसे मूल स्थान यानी अपने आसन के बगल में स्थापित करा दिया। छड़ी जैसे सेंगोल को गत मई में प्रयागराज के संग्रहालय से मंगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में स्थापित किया था।

मंदिर का जिक्र होते ही सबसे तेज और देर तक थपथपाई गईं मेजें

लगभग 75 मिनट तक चले राष्ट्रपति के संबोधन में सत्तापक्ष की ओर से सौ से अधिक बार मेजें थपथपाई गईं, क्योंकि उपलब्धियों की श्रृंखला भी लंबी थी और इस खेमे के सदस्यों का उत्साह भी अधिक था। सबसे तेज और सबसे देर तक मेजें तब थपथपाई गईं जब राष्ट्रपति ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा- ...सदियों पुरानी आकांक्षा पूरी हुई। इस दौरान लगभग 10 सेकेंड तक जय श्रीराम के नारे गूंजते रहे, पीएम भी मेज थपथपाते रहे और राष्ट्रपति शांति होने के लिए इंतजार करती रहीं। राष्ट्रपति मुर्मु ने अपने संबोधन के दौरान तीन बार अलग-अलग तरीके से श्रीराम मंदिर का उल्लेख किया। एक बार यह सूचना देने के लिए भी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले पांच दिनों में 13 लाख लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। पूर्व के कुछ अनुभवों के विपरीत विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रपति ने संबोधन को पूरी शांति से सुना। केवल एक बार विरोध की हल्की आवाज तब उठी जब पूर्वोत्तर में हुए विकास के उल्लेख के दौरान एक सदस्य ने मणिपुर का नाम लिया। अभिभाषण के दौरान सदस्यों की अनेक खाली कुर्सियों ने कम उपस्थिति की अनुभूति कराई। वहीं राजनयिक गैलरी में ब्राजील, मिस्र, मालदीव, नेपाल समेत कई देशों के राजदूत भी उपस्थित थे।

अर्थव्यवस्था को विश्व की शीर्ष पांच में से एक बनाया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रपति अभिभाषण : अर्थव्यवस्था

- **कहा- महंगाई पर पाया काबू, जनता पर नहीं बढ़ने दिया बोझ**
- **आर्थिक मोर्चे पर पेश किया सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा**

अंतरिम बजट 2024-25 पेश होने से एक दिन पहले नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पीएम नरेन्द्र मोदी की सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आर्थिक उपलब्धियों का लेखा-जोखा तो पेश किया ही, साथ ही यह भी संकेत दे दिया कि यह सरकार आगे भी आर्थिक सुधारों को लेकर डटी रहेगी। राष्ट्रपति ने वर्ष 2014 की तुलना वर्तमान समय से करते हुए कहा कि पहले भारत दुनिया की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, लेकिन आज यह दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। राष्ट्रपति ने रिन्युएबल ऊर्जा से लेकर विदेशी मुद्रा भंडार तक और महंगाई की दर से लेकर बैंकों के एनपीए के स्तर तक का आंकड़ा पेश किया, जिसका लब्बोलुआब यही था कि मोदी सरकार की नीतियां हर क्षेत्र की तस्वीर बदल रही हैं। दो महीने बाद ही आम चुनाव हैं और ऐसे में राष्ट्रपति मुर्मु का यह कहना कि उनकी सरकार ने महंगाई को काबू में रखा है और सामान्य जनता पर बोझ नहीं बढ़ने दिया, के व्यापक मायने हैं।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा- 'बीते वर्षों में विश्व ने दो बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया। ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को नियंत्रण में रखते हुए आम भारतीय पर बोझ नहीं बढ़ने दिया। 2014 से पहले के 10 वर्षों में औसत महंगाई दर आठ प्रतिशत से अधिक थी। पिछले दशक में औसत महंगाई दर पांच प्रतिशत रही। मेरी सरकार का प्रयास रहा है कि सामान्य देशवासी की जेब में अधिक से अधिक बचत कैसे हो। पहले भारत में दो लाख रुपए की आय पर टैक्स लग जाता था। आज भारत में सात लाख रुपए तक की आय पर भी टैक्स नहीं लगता। टैक्स छूट और सुधारों के कारण भारत के टैक्सपेयर्स को 10 साल में करीब ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है।'

उन्होंने कहा- 'मेरी सरकार, वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करती है तथा भारत के निजी सेक्टर के सामर्थ्य पर विश्वास करती है। भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। वन और पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे, वहीं आज 75 दिन से भी कम समय लगता है।' बीते दशक में बड़े आर्थिक सुधारों को लेकर उठाए गए कदमों में राष्ट्रपति ने दिवालिया कानून (आइबीसी), जीएसटी का खास तौर पर जिक्र किया। पूंजीगत खर्चे को दस वर्षों में पांच गुना बढ़ा कर 10 लाख करोड़ करने का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा है।

राष्ट्रपति ने देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का जिक्र किया। कहा कि आज ग्रीन एनर्जी पर हमारा बहुत फोकस है। सौर ऊर्जा की क्षमता 26 गुना बढ़ी है। पवन ऊर्जा की क्षमता दो गुनी बढ़ी है। रिन्युएबल ऊर्जा में भारत दुनिया में छठे स्थान पर है। सौर उर्जा क्षमता स्थापित करने में पांचवें स्थान पर है।

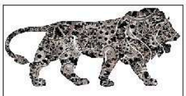

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुके

राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा भंडार के 600 अरब डालर के पार हो जाने, भारतीय बैंकिंग सेक्टर में फंसे कर्ज (एनपीए) घटकर चार प्रतिशत पर आने को भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाया और कहा कि भारत का जो बैंकिंग सेक्टर पहले बुरी तरह से चरमराया हुआ था, वह आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बन गया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुके हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है। पहले देश खिलौनों का आयात करता था मगर आज निर्यात कर रहा है।

मोदी सरकार में पहली बार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मोदी सरकार की दस वर्ष की उपलब्धियां विस्तार से गिनाईं। इनमें ऐसे भी कुछ निर्णयों को उल्लेखित किया जो पहली बार हुए। राष्ट्रपति ने इन बिंदुओं को सरकार की अभिनव पहल के रूप में प्रस्तुत किया।

- भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना।
- भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लांच किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सेटेलाइट पहुंचाई।
- भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पैरा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते।
- भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला।
- भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली।
- भारतीय सेना में पहली बार चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई।
- पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई गई।
- देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है।
- ऐसे हजारों आदिवासी गांव हैं जहां बीते 10 वर्षों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची है। लाखों आदिवासी परिवारों को अब जाकर पाइप से शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ।
- पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की सुध ली गई है। उनके लिए लगभग 24 हजार करोड़ रुपये की पीएम जनमन योजना बनाई है।
- आदिवासी परिवारों की अनेक पीढ़ियां सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित रही हैं। पहली बार इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है।
- पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई।

10 वर्षों में 25 करोड़ को गरीबी से निकाला

अरविंद शर्मा, नई दिल्ली

- **मुर्मु ने कहा- बचपन से सुन रहे गरीबी हटाओ का नारा, पहली बार साकार होते देखा**

मुफ्त राशन की स्कीम रहेगी जारी।

वर्तमान लोकसभा के आखिरी बजट सत्र से पहले दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि दस वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालकर वर्तमान पीढ़ी की विरासत को समृद्ध करने का प्रयास किया गया है। यह दस वर्षों की साधना का विस्तार है जो शेष बचे गरीबों में विश्वास जगाएगा। उन्हें भी लगेगा कि उनके दिन भी फिर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुन रहे थे, किंतु पहली बार इसे साकार होते देख रहे हैं।

राष्ट्रपति ने युवा, नारी, किसान और गरीब विकसित भारत की भव्य इमारत के चार मजबूत स्तंभ बताए और कहा कि समाज में इन सबकी स्थिति और सपने एक जैसे हैं। इसलिए सरकार इन्हें सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। दस वर्ष में छह लाख करोड़ खर्च कर चार करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर मिला। चार लाख करोड़ रुपये से 11 करोड़ घरों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा। दस करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए हैं। कोरोना काल से ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो अगले पांच वर्ष तक जारी रहेगा। सस्ते राशन के लिए सरकार ने दस वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

गरीबों को राहत वाली आयुष्मान योजना की दस वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मुफ्त इलाज की सुविधा से नागरिकों के साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये खर्च होने से बचे हैं। इसी तरह जन-औषधि केंद्रों के चलते भी करीब 28 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। केंद्र सरकार ने कैंसर एवं घुटने के इम्प्लांट जैसे गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती की हैं। इससे भी हर वर्ष करीब 27 हजार करोड़ रुपये की बचत हो रही है। किडनी के मरीजों के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये खर्च कर मुफ्त डायलिसिस का अभियान भी चलाया जा रहा है। जीवन ज्योति बीमा एवं सुरक्षा बीमा योजना के जरिये गरीबों को 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की क्लेम राशि मिली है।

विकासधारा से दूर रहे लोगों की ली सुध : सरकार ने उनकी भी सुध ली है, जो विकास की धारा से दूर हैं। हजारों आदिवासी गांवों में पहली बार बिजली-सड़क पहुंची है। 90 से ज्यादा वनोपज पर एमएसपी मिलने से आदिवासियों को लाभ हुआ है। आदिवासी परिवारों की अनेक पीढ़ियां एनीमिया से पीड़ित रही हैं। राष्ट्रीय मिशन शुरू कर एक करोड़ 40 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित देश भर में 10 संग्रहालय बनाए जा रहे हैं।

परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने को सरकार लाएगी नया कानून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। सरकार इसे सख्ती से रोकने के लिए जल्द ही एक नया कानून लाने की तैयारी में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी और कहा कि ऐसे गलत तरीकों पर सख्ती के लिए सरकार ने नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही बताया है कि परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से सरकार अवगत है। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 सोमवार को सदन में पेश किया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के सरकार के इस कदम को हाल ही में राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसके बाद इन राज्यों में युवाओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था।

भारत के लिए यह समय आने वाली सदियों का भविष्य लिखने का

प्रथम पृष्ठ से आगे

अभिभाषण की शुरूआत में जिक्र करने के बाद राष्ट्रपति ने संबोधन के आखिरी हिस्से में भी अयोध्या समारोह को इतिहास की बड़ी लकीर के रूप में सामने रखने से गुरेज नहीं किया और कहा कि सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए हैं। 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। राम मंदिर करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लिए यह समय आने वाली सदियों का भविष्य लिखने का है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे लिए छोड़ी है जिन्हें आज भी हम बड़े गौरव के साथ याद करते हैं। आज की पीढ़ी को भी ऐसी विरासत बनानी है जो सदियों तक याद रखी जाए।

17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति ने राम मंदिर के अलावा पिछले 10 वर्षों में सरकार के अन्य बड़े फैसलों गिनाते हुए कहा कि हमने ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिसका दशकों से इंतजार था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने को लेकर शंकाएं थीं। आज वे इतिहास हो चुकी हैं। तीन तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया। पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून बनाया। वन रैंक वन पेंशन व पहली बार चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से लेकर गुलामी के दौर की न्याय प्रक्रिया को खत्म कर भारतीय न्याय संहिता का निर्माण किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिला आरक्षण की राह बनाने जैसे इन बड़े फैसलों का जिक्र कर संदेश दिया कि मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ता और प्रतिबद्धता दिखाई। इसी क्रम में उन्होंने मजबूत और पूर्ण बहुमत की सरकार का जिक्र किया। वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि से लेकर दुनिया में भारत के ग्लोबाल साउथ की एक मजबूत आवाज बनने का श्रेय भी राष्ट्रपति ने देश की राजनीतिक स्थिरता को दिया। साथ ही कहा कि भारत की विदेश नीति का दायरा आज अतीत की बंदिशों से कहीं आगे बढ़ चुका है और हम अनेक वैश्विक संगठनों के सम्मानित सदस्य है। आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया की एक प्रमुख आवाज है।

सरकार के भविष्य के वादों-इरादों की झलक पेश करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार आज एक बड़े विजन पर काम कर रही है। इस विजन में आने वाले पांच साल का कार्यक्रम भी है और अगले 25 साल का रोडमैप भी है। हमारे लिए विकसित भारत सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। हम सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक ताकत को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं। इनके बिना विकास और आर्थिक समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के तेज विकास को लेकर आज दुनिया की हर एजेंसी आश्वस्त है। सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत चार मजबूत स्तंभों- युवाशक्ति, नारीशक्ति, किसान और गरीब पर खड़ी होगी। देश के हर हिस्से में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं। इसीलिए सरकार का फोकस इन चार स्तंभों पर है।

आरोप

यह भाजपा है जो संसद के चीरहरण में शामिल रही और लोकतंत्र लिए खतरा पैदा किया, मोदी सरकार ने 146 सांसदों को निलंबित कर सिर्फ तीन दिनों में पारित कराए गए 14 विधेयक

भाजपा के विपक्ष में रहते सबसे ज्यादा बाधित हुई संसद : खरगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद के कामकाज में बाधा के लिए विपक्ष पर आरोप लगाने के लिए कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पलटवार किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पिछले दो दशक के आंकड़े बताते हैं कि संसद के कामकाज में सबसे ज्यादा बाधा 15वीं लोकसभा (2009-2014) के दौरान डाली गई जब भाजपा प्रमुख विपक्षी दल थी। उन्होंने कहा कि यह भाजपा है जो संसद के चीरहरण में शामिल रही है और देश के लोकतंत्र लिए खतरा पैदा किया।

खरगे ने आरोप लगाया कि निरंकुश भाजपा सरकार संसदीय लोकतंत्र का क्षरण कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है और विपक्ष की आवाज का गला घोंट रही है। दोनों सदनों के 146 सदस्यों के निलंबन का अभूतपूर्व कदम उठाने के बाद सिर्फ तीन दिनों के भीतर 14 विधेयकों को पारित करा लिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि वर्तमान लोकसभा में पारित किए गए 172 विधेयकों में से 64 को एक घंटे से भी कम की चर्चा में पारित कराया गया है और इसी दौरान राज्यसभा से 61 विधेयकों को भी एक घंटे से कम की चर्चा में पारित कराया गया। खरगे ने एक बयान में कहा, 'प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर एक बयान दिया। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे उनकी सरकार संसदीय लोकतंत्र के क्षरण के लिए जिम्मेदार है।'

खरगे ने कहा कि 17वीं लोकसभा सबसे कम बैठकों वाली ऐसी लोकसभा होगी जिसने अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में दोनों सदनों से 179 विधेयक पारित किए गए थे और दूसरे कार्यकाल में 213 विधेयक पारित किए गए, जो भाजपा द्वारा डाली गई बाधा के बावजूद संप्रग-1 के कार्यकाल में 297 विधेयकों और संप्रग-2 के कार्यकाल में पारित 248 विधेयकों से कम हैं।

संसद के संयुक्त सत्र में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उपस्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और अन्य। प्रेट्र

राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताया सरकार का विज्ञापन

राष्ट्रपति मुर्मु के अभिभाषण को खारिज करते हुए खरगे ने कहा कि उन्हें खुशी है कि राष्ट्रपति पहली बार नई संसद में आईं और दोनों सदनों को संबोधित किया, हालांकि उन्हें यह सम्मान देर से दिया गया। सभी जानते हैं कि सरकार ने उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन पर आमंत्रित नहीं किया था, जबकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, चूंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार ने तैयार किया था। लिहाजा यह मोदी सरकार का प्रचार और विज्ञापन था। इसमें न तो विजन था और न ही गरीबों की समस्याओं या उनकी चिंताओं का कोई समाधान था। रोजगार और नौकरियों का भी इसमें कोई जिक्र नहीं था। यह गरीबों को गुमराह करने का प्रयास है।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

****

3 वादे किए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों से। भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करेंगे, उसमें भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य से काफी अधिक मिलने की व्यवस्था है। किसानों के कर्ज को माफ करेंगे व बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 1 फरवरी, 2024

जातिवार गणना को लेकर बोले नीतीश– हमारे काम का श्रेय ले रहे लोग

बिहार के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल और राजद नेता तेजस्वी पर साधा निशाना

कहा– जातिवार गणना हमने नौ दलों को साथ लेकर कराई

▸ 10 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसी दिन बहुमत भी सिद्ध किया जाएगा

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर एक साथ निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे काम का लोग झूठा श्रेय ले रहे हैं। जातिवार गणना हमने नौ दलों को साथ लेकर कराई। सात निश्चय-2 (योजनाएं) के तहत बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गईं। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके दबाव से ही नीतीश ने जातिवार गणना कराई।

पटना के सरदार पटेल भवन में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में नीतीश ने कहा कि 2019 और 2020 में हमने बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भी जातिवार गणना की बात कही थी। इसके बाद 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने गए थे। बाद में अपने स्तर पर हमने इसे करवाया। यह सब कुछ मेरा किया हुआ है, बेकार में इसका श्रेय कोई ले रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस दावे पर कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार उनकी (नीतीश) 17 साल की सरकार पर भारी है, को लेकर नीतीश ने कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं। कुछ लोगों को केवल प्रचार चाहिए। सवाल किया कि पहले कितने लोगों को रोजगार मिलता था? पढ़ाई का स्तर क्या था? 2005 से पहले के हालात को आप लोग भूल गए, शाम के वक्त घर से कोई निकलता था? खराब सड़कों का भी हवाला दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसी दिन बहुमत सिद्ध किया जाएगा।

बताया, क्यों छोड़ा आइएनडीआइए : आइएनडीआइए के बारे में पूछे गए सवाल पर नीतीश ने कहा कि हम तो नाम भी कुछ दूसरा कह रहे थे, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। मेरे कहने पर कोई काम नहीं हो रहा था। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों पर फैसला नहीं हो पाया, तब गठबंधन छोड़ने का फैसला लिया।

हेमंत के खिलाफ जांच स्वाभाविक: नीतीश : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत पर ईडी का शिकंजा कसने संबंधी पत्रकारों के सवाल पर नीतीश ने कहा कि उन पर चार्जेज तो बहुत दिन पहले से है, इस पर जांच स्वाभाविक है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पटना में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 'नियंत्रण कक्ष' के उद्घाटन के दौरान। प्रेट्र

ललन सिंह ने राहुल को कहा–आप पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे

जदयू के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को कहा कि आप पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। अपनी चुटकुलेबाजी से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। जाति आधारित गणना, नीतीश का निश्चय था और यह मुद्दा उन्होंने वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में भी उठाया था, जब आपका राजनीतिक उदय भी नहीं हुआ था। उधर, जदयू से गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी लगातार बिहार में दी गई नौकरियों का श्रेय खुद ले रहे हैं। इसे 17 साल बनाम 17 महीने का काम कहकर प्रचारित किया जा रहा है। राजद प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि इसकी पहल लालू प्रसाद व तेजस्वी ने की थी। कांग्रेस और डीएमके ने समर्थन देकर आगे बढ़ाया।

ललन सिंह। फाइल

मनोज झा। फाइल

गठबंधन से ही चुनाव लड़कर भाजपा का सफाया करेंगे : अखिलेश

जागरण संवाददाता, मैनपुरी : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन से ही चुनाव लड़कर भाजपा का सफाया करेंगे। हमारे गठबंधन में सीटों का बंटवारा अच्छी तरह से होगा। भाजपा को हराने वाले प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में भू-माफिया की सरकार चल रही है। शायद ही कोई जिला बचा हो, जहां भाजपा के भू-माफिया जमीनों पर कब्जा न कर रहे हों। केंद्र सरकार ईडी, सीबीआइ और इनकम टैक्स का डर दिखाकर दबा रही है। भाजपा सभी चुनावों में बेईमानी करके जीती है।

अखिलेश यादव। फाइल

बुधवार को करहल क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा सबसे भ्रष्ट राजनीतिक दल है। यह बेईमानों की पार्टी है। इसे जनता की कोई परवाह नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव देश का संविधान बचाने के लिए लड़ा जाएगा। भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस और सभी दलों के साथ आइएनडीआइ तथा पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) महत्वपूर्ण काम करेगा। भाजपा के लोगों ने बेईमानी करके चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जीता है। गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है और उन्होंने 11 सीटें छोड़ दी हैं।

हरियाणा विस नीरज शर्मा से वापस लेगी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार!

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

फरीदाबाद एनआइटी से कांग्रेस विधायक पंडित नीरज शर्मा की वेशभूषा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीरज शर्मा ने अपनी विधानसभा के विकास कार्यों के लिए मंजूर धनराशि जारी नहीं होने के विरोध में सामान्य वस्त्रों का त्यागकर चोगा रूपी सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं, जिन पर रामायण की चौपाई और कबीर के दोहों के साथ ही भगवान श्रीराम का नाम लिखा है। विधानसभा स्पीकर ने इस वेशभूषा में विधायक को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में प्रवेश नहीं देने की बात कही है, जबकि विधायक का दावा है कि उनकी वेशभूषा बिल्कुल भी अमर्यादित या असंसदीय नहीं हैं, इसलिए विधानसभा स्पीकर उन्हें विधानसभा में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते।

विधायक नीरज शर्मा यदि अपनी जिद पर अड़े रहे तो विधानसभा की ओर से उनको दिए गए सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड वापस लिया जा सकता है। नीरज शर्मा को दो मार्च 2022 को हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया था, जिसे उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता और पूर्व मंत्री पंडित शिवचरण लाल शर्मा को समर्पित किया था। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुरस्कार राशि, शाल और प्रशस्ति पत्र दर्शक दीर्घा में उपस्थित अपने पिता तुल्य बुजुर्ग एडवोकेट कन्हैया लाल वशिष्ठ और तुलाराम शास्त्री को देकर उनका आशीर्वाद लिया था। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने बुधवार को विधानसभा स्पीकर डा. ज्ञानचंद गुप्ता से फोन पर बात करने के बाद उन्हें एक आधिकारिक पत्र लिखा है तथा सात फरवरी को मिलने का समय मांगा है। इस दिन चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें शामिल होने के लिए नीरज शर्मा को चंडीगढ़ पहुंचना है। विधायक ने स्पीकर को लिखे पत्र में कहा है कि उनकी वेशभूषा में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने न तो काले कपड़े पहन रखे हैं और न ही उनके चोगे पर कोई काला निशान है। सात फरवरी को स्पीकर विस के विशेषज्ञों की कमेटी को बुला लें और वेशभूषा पर चर्चा कर लें।

नीरज शर्मा। फाइल

कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा की वेशभूषा के विवाद में आया नया मोड़

नीरज शर्मा अपनी असामान्य वेशभूषा में सदन में आने का जो अनावश्यक प्रयास कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। नीरज शर्मा को सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड मिल चुका है। यदि वे अपनी जिद पर अड़े रहे तो उनके सर्वश्रेष्ठ विधायक के अवार्ड पर पुनर्विचार किया जा सकता है। – डा. ज्ञानचंद गुप्ता, स्पीकर, हरियाणा विधानसभा

अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू किया जय जवान अभियान

नई दिल्ली, प्रेट्र: कांग्रेस ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ जागरुकता पैदा करने के लिए से बुधवार को जय जवान अभियान शुरू किया। पार्टी का यह आग्रह भी है कि वर्ष 2019-22 के दौरान थलसेना, नौसेना और वायुसेना में चयनित करीब डेढ़ लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उनकी भर्ती सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि जंग तो हथियारों से लड़ी जाती है, लेकिन जीती हौसलों से जाती है। अग्निपथ योजना सेना के मनोबल को गिरा रही है, लाखों जवानों के सपनों पर हमला कर रही है। आप घर-गाड़ी किराए पर ले सकते हैं, लेकिन फौजी को किराए पर नहीं ले सकते। उन्होंने सवाल किया कि अगर सीमा पर खड़े जवान को ये विश्वास नहीं होगा कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा फिर वो कैसे लड़ेगा? अग्निपथ ऐसी योजना है जो सेना की 70 वर्षों में बनी संरचना को छिन्न-भिन्न कर रही है। पूर्व-सैनिक विभाग के प्रमुख कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने कहा कि जवानों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया गया है।

आप-कांग्रेस को झटका, हाई कोर्ट का चुनाव परिणाम पर रोक से इन्कार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▸ चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर यूटी प्रशासन को नोटिस

▸ हाई कोर्ट ने प्रशासन को तीन सप्ताह के भीतर पक्ष रखने का दिया आदेश

मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कुलदीप कुमार ने पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और चुनाव परिणाम पर रोक लगाते हुए इसे रद करने की मांग की। हाई कोर्ट ने याची पक्ष को झटका देते हुए मामले में कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने व चुनाव परिणाम पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने मामले पर यूटी प्रशासन व अन्य को नोटिस जारी करते हुए प्रशासन से तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

याचिका में कुलदीप कुमार ने कहा कि आप-कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत होते हुए भी मतों की गिनती के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने मतों की गिनती के दौरान मतपत्रों से छेड़छाड़ की और भाजपा प्रत्याशी को जिता दिया। याचिका में बताया गया कि हाई कोर्ट में चंडीगढ़ के डीजीपी ने पारदर्शी चुनाव करवाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। बावजूद इसके चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए आप-कांग्रेस गठबंधन के मतों के साथ छेड़छाड़ हुई। याचिका में मेयर चुनाव की प्रक्रिया को रद करने, चुनाव से जुड़ा पूरा रिकार्ड सील करने, मेयर के पदभार संभालने पर रोक लगाने, धांधली की जांच करवाने और नए सिरे से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में चुनाव करवाने का निर्देश जारी करने की मांग की गई। बता दें, मंगलवार को हुए मेयर चुनाव में भाजपा के पक्ष में 16 मत पड़े, जबकि आप-कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी को 12 मत पड़े। कुल आठ मत रद हुए। आरोप है कि गठबंधन प्रत्याशी को पड़े मत रद किए गए।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी की कार का शीशा टूटा

जागरण टीम, मालदा/कोलकाता

▸ अधीर का दावा बंगाल में हुआ पथराव, कांग्रेस को देनी पड़ी सफाई, सुरक्षा रस्सी से हादसा

▸ हड़बड़ी में ममता ने लगाए आरोप, राहुल की गाड़ी पर हमला बंगाल नहीं, बिहार में हुआ

कटिहार में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी। प्रेट्र

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनकी कार का शीशा टूट गया जिसको लेकर कांग्रेस और तृणमूल के बीच दोपहर से शाम तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि बंगाल में राहुल की कार पर पथराव हुआ है। उनका इशारा तृणमूल कार्यकर्ताओं की तरफ था। बाद में कांग्रेस की ओर से स्पष्टीकरण आया कि एक महिला के सामने आने पर अचानक ब्रेक मारे जाने से सुरक्षा घेरे की रस्सी की रगड़ और दबाव से पीछे का शीशा टूट गया। राहुल सुरक्षित रहे।

हड़बड़ी में ममता कूद पड़ीं विवाद में : यात्रा के दौरान पथराव की खबरें मीडिया में आईं तो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हड़बड़ी में दावा कर दिया कि गाड़ी पर बंगाल में नहीं, बल्कि बिहार के कटिहार में हमला किया गया है। ममता ने इस घटना की निंदा की और कहा कि जब राहुल की गाड़ी ने बंगाल में प्रवेश किया तब उनकी गाड़ी का पिछला शीशा पहले से टूटा हुआ था। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अधीर और ममता के बीच पहले से विवाद चल रहा है। अधीर ने यात्रा के लिए ममता सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि ममता सरकार ने मालदा और मुर्शिदाबाद के लिए राहुल गांधी के कई कार्यक्रमों को अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। उधर, मुर्शिदाबाद में सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम के दौरान हुए ममता ने कहा कि मैं इस घटना की निंदा करती हूं। यह कुछ नहीं बल्कि ड्रामा है। ममता ने यह संदेह भी व्यक्त किया कि यह घटना बिहार में लोगों के गुस्से की अभिव्यक्ति भी हो सकती है, जहां नीतीश का जनता दल यूनाइटेड विपक्षी आइएनडीआइए से नाता तोड़कर भाजपा नीत राजग में लौट गए हैं।

कांग्रेस की ओर से आई सफाई : कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया कि राहुल की गाड़ी पर कोई हमला नहीं हुआ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल से मिलने अपार जनसमूह आया हुआ था, एक उत्साही महिला उनसे मिलने के लिए जब एकदम से आगे आ गईं, तब कार को अचानक रोकना पड़ा और सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से से कार का पीछे का शीशा टूट गया। उन्होंने कहा कि राहुल न्याय की लड़ाई मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और यह देश ना सर्फ उनके साथ खड़ा है।

भाजपा राज में 30 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करने को मजबूर : राहुल

नई दिल्ली, एएनआइ: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा के शासन में प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बिहार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गुजरने के दौरान मंगलवार को राहुल गांधी ने पूर्णिया में किसानों से बातचीत की थी। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट कर कहा कि 2014 की तुलना में वर्तमान में देश के किसानों पर 60 प्रतिशत अधिक कर्ज है और मोदी सरकार ने गत दस वर्ष में उद्यमियों का 7.5 लाख करोड़ का ऋण माफ कर दिया। फसल बीमा योजना में किसानों के हिस्से के 2700 करोड़ रुपये रोकने वाली निजी बीमा कंपनियां खुद 40,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रही हैं। महंगी बिजली, मंहगे उर्वरक व बीज के कारण आसमान छूती लागत के बीच किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए संघर्ष कर रहा है।

केरल के पीसी जार्ज ने भाजपा में अपनी पार्टी का किया विलय

केरल जनपक्षम (सेक्युलर) का बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा में विलय हो गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन, सांसद प्रकाश जावड़ेकर मौजूद थे। इस मौके पर हाथ मिलाते हुए पीसी जार्ज से हाथ मिलाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा चुनाव से पहले केरल जनपक्षम (सेक्युलर) के प्रमुख पीसी जार्ज ने बुधवार को अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। केरल के भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जार्ज अपने बेटे शान और केरल जनपक्षम (सेक्युलर) के अन्य नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पीसी जार्ज के नेतृत्व वाला केरल जनपक्षम (सेक्युलर) भाजपा में विलय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने के दृष्टिकोण में पूरा भरोसा दिखा रहा है। भाजपा में जार्ज का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि जनपक्षम का विलय केरल में एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी। भाजपा इस राज्य में तेजी से बढ़ेगी।

वोट न देने पर कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने गारंटी योजनाएं रोकने की वकालत की

बेंगलुरु, प्रेट्र: कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक एचसी बालकृष्ण ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के अधिकतम सीट जीतने में विफल रहने की स्थिति में गारंटी योजनाओं को बंद करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि आम चुनाव में कांग्रेस को यदि अधिकतम सीट नहीं मिलती है तो यह माना जायेगा कि लोगों ने योजनाओं को खारिज कर दिया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सभा में विधायक बालकृष्ण ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बात की है और कहा कि यह लोगों को तय करना है कि वे अक्षत चाहते हैं या पांच गारंटी योजनाएं। गारंटी योजनाओं के फायदे गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इतना सब करने के बावजूद अगर लोग हमें वोट नहीं देते हैं, तो हम क्या फैसला करें? इन गारंटियों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अक्षत का मूल्य है। तो हम गारंटी रद कर देंगे और हम भी मंदिर बनाएंगे, वहां पूजा करेंगे, अक्षत देंगे और वोट लेंगे। इस बीच विपक्षी दल भाजपा ने विधायक बालकृष्णन और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।

राज्यपाल ने साइनबोर्ड पर 60 प्रतिशत कन्नड़ का अध्यादेश लौटाया

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक सरकार में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया कि राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने साइनबोर्ड पर 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा वाला अध्यादेश लौटा दिया है। राज्य सरकार ने कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने की नीति के तहत अध्यादेश जारी किया जिसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था।

मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की सरकार ने यह अध्यादेश इसी साल पांच जनवरी को जारी किया था। कांग्रेस सरकार ने कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल प्रोत्साहित करने की नीति के तहत साइनबोर्ड से जुड़ा अध्यादेश जारी किया था। राज्यपाल ने सरकार के अध्यादेश को वापस करते हुए कहा कि इसे विधानसभा से पारित कराया जाए। कर्नाटक विधानमंडल का बजट सत्र 12 से 23 फरवरी तक है। ऐसा कहा जा रहा है कि सत्र करीब होने के चलते राज्यपाल ने अध्यादेश सरकार को वापस भेजा होगा। कैबिनेट बैठक के बाद 'कन्नड़ भाषा व्यापक विकास कानून' में संशोधन का फैसला लिया था। कैबिनेट ने पांच जनवरी को अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसमें साइनबोर्ड पर लिखी भाषा में 60 प्रतिशत कन्नड़ का अनिवार्य करने का फैसला लिया। मौजूदा कानून के अनुसार बोर्ड के ऊपरी आधे हिस्से में कन्नड़ का इस्तेमाल करना है।

▸ शिवकुमार बोले- कर्नाटक सरकार कन्नड़ को सम्मान दिलाने को प्रतिबद्ध

थावर चंद गहलोत।

डी के शिवकुमार। फाइल

भाजपा का आरोप, ममता सरकार ने किया दो लाख करोड़ रुपये का घोटाला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ बंगाल के भाजपा अध्यक्ष का दावा, सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई हैं वित्तीय अनियमितताएं

▸ 2018 से 2021 के बीच सरकारी परियोजनाओं पर खर्च बजट का नहीं दिया उपयोगिता प्रमाण पत्र

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए भाजपा ने बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि ममता सरकार ने 2018 से 2021 के बीच सरकारी परियोजनाओं पर जो पैसा खर्च हुआ बताया है, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। नए खाते खोलकर भी जनता का पैसा लूटने का प्रयास हुआ है। इस तरह कैग की रिपोर्ट में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं।

भाजपा मुख्यालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में मजूमदार ने कहा कि सीएजी ने बंगाल की वर्ष 2021 की रिपोर्ट संसद में पेश की है। इसमें दो लाख करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता और संभावित घोटाले पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे से होने वाले काम का नियम है कि कोई भी प्रोजेक्ट पूरा होने के एक साल के अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है। ऐसे दो लाख 40 हजार प्रमाण पत्र टीएमसी सरकार ने नहीं दिए हैं। इस तरह 1.95 लाख करोड़ रुपये खर्च हो गए, लेकिन हिसाब नहीं है। दावा किया कि ये मामले ग्रामीण विकास, शहरी विकास और स्कूली शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। इनमें से दो विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री अभी जेल में हैं। इसी कारण से मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार को रोकना पड़ा है। मजूमदार के अनुसार, बंगाल का वित्तीय नियम कहता है कि कांटिजेंसी फंड में कोषागार से एडवांस में पैसा लेकर काम करें, लेकिन एक माह के अंदर बिल देना होता है। आश्चर्य है कि जो ममता बनर्जी वेतन का एक भी पैसा नहीं लेने का दावा करती हैं, उन्होंने 2018 से 2021 तक एक भी बिल जमा नहीं किया, जबकि 3400 करोड़ रुपये इमरजेंसी फंड से लिए गए। यह पैसा कहां गया, किसी को पता नहीं है। इसमें भी इमरजेंसी फंड का 1169 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय से खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं राज्य की गृह मंत्री हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस पैसे का उपयोग करने के लिए अनूठे किस्म का खाता बनाया गया है। उनको नाम दिया पर्सनल लेजर और पर्सनल अकाउंट्स। ऐसे 160 खाते बनाए गए, जिनमें 3465 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है।

सुकांत मजूमदार।

ममता बनर्जी। फाइल

टूजी घोटाले से भी बड़ा

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आइएनडीआइए ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार रहते जो टू जी घोटाला हुआ, उसकी राशि तो एक लाख 76 हजार करोड़ के आसपास थी, जबकि बंगाल जैसे एक प्रदेश से ही दो लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया। उन्होंने प्रश्न उठाया कि यह पैसा रोहिंग्या को दिया, अपने परिवार को दिया या दंगे फैलाने के लिए दिए हैं।

गौरव भाटिया।

रणनीति

पीएम नरेन्द्र मोदी के गांव के समग्र विकास के सपने को पार्टी कार्यकर्ता करेंगे साकार, नौ से 11 फरवरी तक गांव और नगरीय बूथों पर वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बिताएंगे 24 घंटे

चुनाव से पहले कई लक्ष्यों को साधेगा भाजपा का 'गांव चलो' अभियान

राज्य ब्यूरो, भोपाल

शहर के साथ ही गांवों तक अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए अब भाजपा 'गांव चलो' अभियान चलाएगी। अब तक भाजपा ने जितने अभियान चलाए वे बूथ सशक्तीकरण या 'बूथ चलो' के नाम से थे लेकिन पहली बार भाजपा 'गांव चलो' अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तकभेजना चाहती है। अभियान में नौ से 11 फरवरी तक केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे बिताएंगे। पूरे प्रदेश के गांवों और नगरीय बूथों पर भाजपा की रीति-नीति, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे।

पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों का मानना है कि बूथ को मजबूत करने के लिए पार्टी जो कार्यक्रम बनाती है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में ध्यान अधिक केंद्रित रहता था। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के तहत गांवों पर फोकस अधिक होगा। पार्टी के अध्ययन में भी यह बात सामने आई है कि शहर और गांव के वोट प्रतिशत में भी काफी अंतर रहता है, इसलिए इस बार भाजपा का ध्यान गांवों पर अधिक है। इस हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का 'गांव चलो' अभियान कई लक्ष्य साधेगा। इसमें पीएम मोदी के गांव के समग्र विकास के संकल्प को लेकर सभी गांवों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। अभियान की तैयारी तीन फरवरी तक की जाएगी। कार्यकर्ताओं का प्रवास नौ से 11 फरवरी तक रहेगा। अंतिम चरण में समीक्षा बैठक 14 फरवरी तक होगी। मध्य प्रदेश में तीन फरवरी से पहले जिला और मंडल स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा संभाग और जिलेवार बैठकें कर रहे हैं।

58 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य : केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को 'गांव चलो' अभियान के माध्यम से उतारकर 58 प्रतिशत वोट प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। पार्टी का मानना है कि इसके बाद लोकसभा चुनाव में जब कार्यकर्ता लोगों से अपनी बात कहेंगे तो उन पर विश्वास ज्यादा होगा क्योंकि चाहे केंद्र की योजनाएं हो या फिर राज्य की, सभी का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है। पार्टी का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ पहुंचे। विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर पार्टी को हार मिली है उसको जीतना और जीते हुए बूथों पर 10 प्रतिशत वोट शेयर बढ़ाने का भी लक्ष्य है।

भाजपा। फाइल

पीएम मोदी के गांव के समग्र विकास के सपने को साकार करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता गांवों में जाएंगे। वे वहां ग्रामीणों से संपर्क कर भाजपा की रीति-नीति और सरकार के कार्यों को लेकर प्रत्येक बूथ पर संपर्क और संवाद करेंगे। – आशीष अग्रवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी, मध्य प्रदेश भाजपा

****

सात पीढ़ियों से नातियों को हस्तांतरित होती आ रही व्यास गद्दी

हक की लड़ाई ▶ नाना पं. रघुनंदन व्यास से मिली गद्दी पं. बैजनाथ ने सौंपी नाती पं. सोमनाथ व्यास को

अब लंबी लड़ाई के बाद उत्तराधिकारी नाती शैलेंद्र व्यास को मिला पूजा का अधिकार

शैलेश अस्थाना, वाराणसी

ज्ञानवापी की व्यास पीठ ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक भी है। इसके साथ ही यह पीठ बेटियों के अधिकार की गौरवशाली सनातन परंपरा का वाहक भी रही है। ज्ञात इतिहास की बात करें तो सात पीढ़ियों से इस व्यास पीठ का उत्तराधिकार बेटियों के पुत्र यानी नाती ही संभालते आए हैं। एक बार फिर काफी लंबे कानूनी संघर्ष के बाद तीसरी बार यह अधिकार पूर्व व्यास के नाती को ही मिला है।

1993 में ज्ञानवापी परिसर में होने वाली नियमित पूजा पर रोक लगा दी गई तो तत्कालीन पुजारी पं. सोमनाथ व्यास ने न्यायालय की शरण ली। 2000 में दिवंगत होने के पूर्व उन्होंने अपने नाती पं. शैलेंद्र पाठक व्यास के पक्ष में वसीयत करते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।

फिलहाल शिवपुर में रह रहे पं. आसाराम पाठक व्यास ने बताया कि उनके श्वसुर पं. सोमनाथ व्यास व उनके तीन भाइयों को यह पीठ उनके नाना पं. बैजनाथ व्यास ने सौंपी थी। पं. बैजनाथ को भी यह पीठ उनके नाना पं. रघुनंदन व्यास से मिली थी। अब एक बार फिर यह पीठ नाना पं. सोमनाथ व्यास के नाती के हाथों में आई है।

सोमनाथ व्यास। फाइल

शैलेन्द्र पाठक व्यास। फाइल फोटो

ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में नियमित पूजा-अर्चना की अनुमति देने के फैसले का स्वागत योग्य है। ज्ञानवापी के मुख्य मुकदमे का अंतिम निर्णय भी हिंदुओं के पक्ष में होगा। आदि विश्वेश्वर के मंदिर के लिए ज्ञानवापी स्थान भी वापस मिलेगा।
-आलोक कुमार, कार्याध्यक्ष, विहिप

तहखाने में पूजा-पाठ करते थे पं. सोमनाथ व्यास

ज्ञानवापी को लेकर पं. सोमनाथ व्यास की ओर से दाखिल मुकदमे के वादमित्र वकील विजय शंकर रस्तोगी के अनुसार जनता के प्रतिनिधि व स्वयंभू विश्वेश्वर के पुजारी के तौर पर व्यास जी ज्ञानवापी के तहखाने पर काबिज थे। शैलेंद्र कुमार पाठक के नाना पं. सोमनाथ व्यास के पास उसकी चाबी रहती थी। ज्ञानवापी परिसर में उस समय रामायण पाठ होता था। उसके लिए बड़े-बड़े तंबू लगते थे। उसका सारा सामान तहखाने में रखा जाता था। वहां कई मूर्तियां भी थी जिनमें से कई टूटी हुई थीं। पं. सोमनाथ व्यास वहां पूजा-पाठ भी करते थे। छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में ढांचा ध्वंस के बाद ज्ञानवापी की सुरक्षा बढ़ाई गई तो व्यास जी के तहखाने पर व्यास जी के साथ-साथ प्रशासन का ताला भी लग गया। एक ताले की चाबी व्यास जी के पास तो प्रशासन की चाबी चौक थाने पर रहती थी। पं. सोमनाथ व्यास को तहखाना खोलना होता था तो वह इसकी जानकारी चौक थाने पर देते थे। वहां से चाबी आती थी, फिर व्यास जी अपनी चाबी से दूसरे ताले को खोलते थे।

व्यास पीठ सिर्फ एक पुजारी की गद्दी नहीं थी बल्कि मालिकाना हक था व्यास परिवार के पास

ज्ञानवापी की व्यास पीठ सिर्फ एक पुजारी की गद्दी नहीं थी, बल्कि ज्ञानवापी का मालिकाना हक व्यास परिवार के पास सदियों की पीढ़ियों से था। कानूनी दस्तावेज के अनुसार पूरे परिसर और मस्जिद के एक तहखाने का स्वामित्व पं. बैजनाथ व्यास के नाम था। अंत समय में उन्होंने अपनी बेटी के चार पुत्रों यानी चार नातियों पं. सोमनाथ व्यास, पं. चंद्रनाथ व्यास, पं. केदारनाथ व्यास व पं. राजनाथ व्यास समेत तीन नातियों को वसीयत कर दी। इसमें एक तहखाने के साथ ही ज्ञानवापी परिसर, हाता व आवास था। मस्जिद के चारों ओर के परिक्षेत्र और ज्ञानवापी हाते का स्वामित्व इसी परिवार के पास रहा। वर्तमान व्यास परिवार के पास पूर्वजों का 500 प्राचीन वंश वृक्ष है, जो पीढ़ियों से वहां पूजा-पाठ व भगवान आदि विश्वेश्वर को 1993 तक राग-भोग करता आया है।

विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद आज करेगा तहखाने का निरीक्षण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने में पूजन-अर्चन का आदेश आने के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। न्यास गुरुवार को तहखाने का निरीक्षण करेगा। वस्तुस्थिति देखने के बाद राग-भोग-पूजनादि का खाका खींच लिया जाएगा। पुजारी की तैनाती कर शुरुआत भी कर दी जाएगी। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रो. नागेन्द्र पांडेय ने कहा कि तहखाना वर्षों से बंद है। निरीक्षण कर उसकी साफ-सफाई की जाएगी। देखा जाएगा कि अंदर जो वस्तुएं, मूर्ति, शिवलिंग आदि किस स्थिति में हैं।

कार्यकाल के अंतिम दिन जिला जज ने दिया आदेश : जिला जज के तौर पर डा. अजय कृष्ण विश्वेश के कार्यकाल का बुधवार को अंतिम दिन था। अपने विदाई समारोह से पहले दोपहर को उन्होंने मुकदमे में आदेश दिया। बीते साल 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल इस मुकदमे की सुनवाई वादी की मांग पर जिला जज कर रहे थे।

एएसआइ के वैज्ञानिक सर्वे में व्यासजी के तहखाने व आसपास मिले विग्रह और प्रतीक

ज्ञानवापी परिसर में दक्षिण ओर ही मध्य का तहखाना व्यासजी का बताया जाता है। एएसआइ के सर्वे में इस हिस्से का भी सर्वेक्षण किया गया। दक्षिण ओर तीन और उत्तर की ओर पांच तहखाने बताए जाते हैं।

2

3

4

5

6

फोटो संख्या दो : तहखाना का गलियारा।
फोटो संख्या तीन से छह तक : तहखाना संख्या एक और दो में एएसआइ सर्वे के क्रम में मिला विग्रह तथा शिलालेख।

तहखाना एक
7
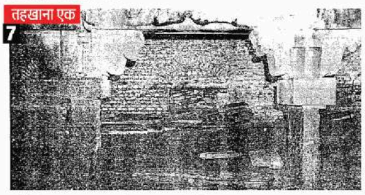
फोटो संख्या 8 : तहखाना संख्या एक का बंद हिस्सा।
सभी चित्र : एएसआइ सर्वे रिपोर्ट से

दो न्यायाधीशों ने ज्ञानवापी मामले में दिये कई अहम आदेश

जागरण संवाददाता, वाराणसी

तत्कालीन सिविल जज सीनियर डिविजन रविकुमार दिवाकर ने 18 अगस्त, 2021 को राखी सिंह सहित पांच महिलाओं की ओर से ज्ञानवापी स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग के मुकदमे में आठ अप्रैल, 2022 को अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर बनाकर ज्ञानवापी परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आदेश दिया।

- अदालत के आदेश पर छह व सात मई, 2022 को शुरू हुई कमीशन की कार्यवाही ज्ञानवापी परिसर में विरोध के चलते रुक गई। इस पर जज ने 12 दिसंबर को आदेश दिया कि ताला खोलकर या तोड़कर एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही पूरी करें।
- पुन: शुरू हुई कमीशन की कार्यवाही के दौरान 16 मई को ज्ञानवापी के पानी टंकी (वुजूखाना) में शिवलिंग मिलने की बात मंदिर पक्ष के कहने पर पानी टंकी को सील करने का आदेश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 मई, 2023 को मां शृंगार गौरी मुकदमा जिला न्यायाधीश डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में स्थानांतरित किया गया। 12 सितंबर को उन्होंने मुकदमा सुनने योग्य है (पोषणीय) यह आदेश दिया था।
- मंदिर पक्ष के शिवलिंग के वैज्ञानिक जांच की मांग को उन्होंने 14 अक्टूबर को खारिज कर दिया था।
- जिला जज ने 21 जुलाई को मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पूरे परिसर के एएसआइ सर्वे की जांच का आदेश दिया।
- इसी मुकदमे में 24 जनवरी, 2024 को जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को देने का आदेश दिया।
- शैलेंद्र कुमार पाठक के मुकदमे में जिला जज ने 17 जनवरी को जिलाधिकारी को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया।
- व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ का आदेश 31 जनवरी को दिया।

व्यासपीठ से उठा था ज्ञानवापी परिसर का मामला

जागरण संवाददाता, वाराणसी

ज्ञानवापी परिसर का मामला परतंत्र भारत में व्यासपीठ से उठा था। उस समय यह मालिकाना हक का मामला हुआ करता था। इसमें व्यास परिवार को सफलता भी मिली, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद 15 अक्टूबर, 1991 को पं. सोमनाथ व्यास ने ज्ञानवापी परिसर में नए मंदिर के निर्माण और पूजा-पाठ को लेकर याचिका दाखिल की थी। सात मार्च, 2000 को उनके निधन के बाद इसे वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने आगे बढ़ाया।

इतिहास पर गौर करें तो 1669 में औरंगजेब ने ज्ञानवापी परिसर स्थित मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया। देश स्वतंत्र होने के बाद पुराने मंदिर के संबंध में लिखा-पढ़ी शुरू हुई। वास्तव में ज्ञानवापी परिसर व्यास परिवार का हुआ करता था। कानूनी दस्तावेज के अनुसार परिसर और एक तहखाने का स्वामित्व पं. बैजनाथ व्यास के नाम था। अंत समय में उन्होंने अपने नाती पं. केदारनाथ व्यास, पं. सोमनाथ व्यास समेत तीन नातियों को वसीयत कर दी। इसमें एक तहखाने के साथ ही ज्ञानवापी हाता व आवास था। मंदिर विस्तारीकरण व सुंदरीकरण परियोजना शुरू हुई तो मंदिर प्रशासन की ओर से व्यास आवास खरीदने की जरूरत महसूस हुई। पं. सोमनाथ व्यास व एक अन्य भाई के उत्तराधिकारी ने इसे बेच दिया, लेकिन आवास का अस्तित्व रहने तक पं. केदारनाथ व्यास इसमें रहे। भवन का कुछ हिस्सा गिरने पर प्रशासन ने नगर निगम, वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) व लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) से इसकी स्थिति का आकलन कराया। इसके जर्जर पाए जाने पर भवन 2017 में ध्वस्त करा दिया। उसके बाद पं. केदारनाथ व्यास मंदिर के समीप स्थित एक किराये के भवन में रहे जहां साल भर के भीतर उनकी मौत हो गई। भवन को लेकर मामला हाई कोर्ट तक गया।

15 अक्टूबर, 1991 को परिसर में नए मंदिर के निर्माण और पूजा-पाठ को लेकर दायर की गई थी याचिका

ढांचा ध्वंस के बाद की गई बैरिकेडिंग

1993 तक भूखंड आराजी संख्या 9130 (ज्ञानवापी) में मौजूद देवी-देवताओं की नियमित पूजा-पाठ की जाती रही है। ज्ञानवापी परिसर के उत्तर दिशा में जिसके सामने वर्तमान में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का प्रवेश द्वार संख्या चार है, वहां दो दुकानें थी। इनमें से एक में कोयला बेचा जाता था और दूसरी सौंदर्य प्रसाधन की दुकान थी। अयोध्या में ढांचा ध्वंस के बाद 1993 में यहां पहले बांस-बल्ली उसके बाद लोहे की ऊंची बैरिकेडिंग करा दी गई। दोनों दुकानों को खाली करा दिया गया।

धरोहर से कम नहीं रहा भवन : ज्ञानवापी हाता स्थित व्यास परिवार का आवास भी कोई सामान्य भवन नहीं था। इसमें आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाले मंडन मिश्र की मूर्ति स्थापित थी और राधाकृष्ण मंदिर भी था। इसमें महात्मा गांधी के साथ ही कई विभूतियां आ चुकी थीं।

आजादी के पहले का है अधिकार का विवाद : ज्ञानवापी परिसर में व्यास परिवार के अधिकार को लेकर विवाद देश की आजादी के पहले से है। अदालत में सबसे पहले इसकी चर्चा 1936 में दाखिल दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी आफ स्टेट के मुकदमे में आई। अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद इमारत को छोड़कर अन्य हिस्से पर व्यास परिवार का हक बताया था। 1936 में दीन मोहम्मद ने याचिका दायर कर मस्जिद होने की बात कहकर जमीनों पर हक बताया था।

सरकार और जिला प्रशासन ने बिना अधिकार के रोकी पूजा

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा रोक दी। बीते 17 जनवरी को अदालत ने जिलाधिकारी को तहखाने का रिसीवर नियुक्त कर दिया लेकिन तहखाना में पूजा-अर्चना संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया। वादी की ओर से व्यास परिवार का वसीयतनामा, श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट व वादी शैलेंद्र कुमार पाठक के बीच सेवायतनामा (सेवा और देखभाल करने का अधिकार) प्रस्तुत किया गया। इनका अवलोकन करने के बाद यह प्रतीत होता है कि रिसीवर जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया जाए कि वह प्लाट संख्या 9130 (ज्ञानवापी) थाना चौक स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने (वादग्रस्त संपत्ति) में वहां स्थित मूर्तियों की पूजा, राग-भोग करवाए। इस उद्देश्य के लिए सात दिन के भीतर प्रशासन लोहे की बाड़ आदि का उचित प्रबंध करे।

अदालत ने नहीं मानी मस्जिद पक्ष की दलील

मुकदमे में अदालत ने प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद (मस्जिद पक्ष) की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। मस्जिद पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि व्यास परिवार के किसी भी व्यक्ति ने कभी उक्त तहखाने में कोई पूजा नहीं की है। दिसंबर, 1993 के बाद पूजा से रोकने का सवाल ही नहीं उठता है। उक्त स्थान पर कभी किसी देवी-देवता की कोई मूर्ति नहीं थी। वादी का यह कहना असत्य है कि खानदानी पुजारी व्यास परिवार के लोग तहखाने पर काबिज थे। तहखाना अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के कब्जे में चला आ रहा है। ऐसे में किसी रिसीवर को तहखाने में प्रबंध व पूजा कराने का निर्देश दिया जाना उचित नहीं है। 1936 के दीन मुहम्मद बनाम सेक्रेटरी आफ स्टेट के मुकदमे में भी व्यास परिवार के ऐसे किसी अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।

मोहम्मद यासीन।

नहीं पता, किसके आदेश पर बंद हुई थी पूजा

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में कई बार सवाल आया कि आखिर किसके आदेश पर ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग की गई और उसकी पश्चिम दीवार पर मौजूद मां शृंगार गौरी की प्रतिमा के दर्शन-पूजन पर रोक लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अयोध्या में ढांचा ध्वंस के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के इस्तीफा देने के बाद 1993 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। उस समय केंद्र में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। बैरिकेडिंग किसके आदेश पर हुई और मां शृंगार गौरी का दर्शन-पूजन किसने आदेश से रोका गया, यह जानकारी किसी को नहीं है। मंदिर पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि हाई कोर्ट में जस्टिस जेजे मुनीर के सामने भी यह सवाल उठा था। उस वक्त उप्र सरकार के अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने अदालत को बताया था कि इस बारे में कोई लिखित आदेश नहीं है।

विष्णु शंकर जैन।

वुजूखाना सर्वे की याचिका विचारणीय : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▶ वाराणसी जिला अदालत के इन्कार संबंधी आदेश को दी गई है चुनौती
▶ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी को नोटिस

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना क्षेत्र (शिवलिंग छोड़) का एएसआइ से साइंटिफिक सर्वे कराने की याचिका को विचारणीय माना है। सर्वे से इन्कार करने संबंधी जिला अदालत वाराणसी के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अन्य पक्षकारों की तरफ से अधिवक्ता हाजिर हुए।

कोर्ट ने यह आदेश बुधवार को शृंगार गौरी केस में वादी नंबर एक राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी की बहस को सुनकर दिया है। याचिका पर विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 की तरफ से राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि, विपक्षी पांच के अधिवक्ता विनीत संकल्प, विपक्षी छह भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एएसजीआइ शशि प्रकाश सिंह, एम के सिंह व विपक्षी सात की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने नोटिस स्वीकार की। पुनरीक्षण याचिका में वुजूखाने का सर्वे कराने की मांग की गई है। वाराणसी जिला जज ने 21 अक्टूबर, 2023 को दिए गए आदेश में वुजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एरिया संरक्षित करने का आदेश दिया है। मांग स्वीकार करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप होगा। याचिका में कहा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में संपत्ति के धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए वुजूखाना ('शिवलिंग' छोड़कर) का सर्वेक्षण आवश्यक है। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने पूछा, परिसर का एएसआइ तो सर्वे कर चुका है। रिपोर्ट भी जमा कर दी गई है। इस पर सौरभ तिवारी ने कहा, 'अभी तक वजूखाने का सर्वे नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण यह मांग पहले नहीं की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आदेश जारी किया है जिसके बाद वुजूखाने (शिवलिंग को छोड़कर) के सर्वे की मांग की गई है।' वैसे, न्यायमूर्ति का यह सवाल भी था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एरिया सील करने का आदेश दिया है, तब कैसे सर्वे हो सकता है? सौरभ तिवारी का कहना था कि ऐसा किया जा सकता है।

राष्ट्रीय फलक

मोदी सरकार ने किया जम्मू-कश्मीर का पुनर्निर्माण : अमित शाह

▶ केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा-आतंकवाद और हिंसा के युग का अंत
▶ कहा-केंद्र शासित प्रदेश में देश की प्राचीनतम व समृद्ध संस्कृति

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर का पुनर्निर्माण किया है। यहां आतंकवाद और हिंसा के युग का अंत हुआ है। बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश में विकास को पंख लग गए हैं।

प्रगतिशील जम्मूकश्मीर# पर हिंदी और अंग्रेजी में एक्स पर कई पोस्ट साझा करते हुए बुधवार को अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू और कश्मीर के युवाओं को नई उम्मीद दी है। शिक्षा और कौशल सुविधाओं को सशक्त करते हुए मोदी सरकार ने युवाओं को प्रेरणा की नई उड़ान देते हुए उनके सपने सुरक्षित किए हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की संस्कृति देश की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है। इसकी सांस्कृतिक विरासत पुनर्जीवित हुई और इसकी संस्कृति का गौरव एक बार फिर से शिरोधार्य है।

अमित शाह।

उन्होंने आरोप लगाया कि वंशवादी राजनीति के कारण जम्मू और कश्मीर के लोग पहले विकास से अछूते थे।

मोदी सरकार ने उन्हें वंशवादी शासन से मुक्त कराया और आधारभूत स्तर पर आम जनता को विकास मुहैया किया। मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली को सशक्त किया है।

पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने राहत की सांस ली है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस पालिसी अपना कर घाटी में उसको कुचल डाला है। एक्स पर पोस्ट करके ही शाह के कार्यालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता स्थापित की है। 2023 में यहां पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई है। पूरे क्षेत्र के लिए यह नया युग है।

राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हिंदुओं के लिए नए युग की शुरुआत

ओटावा, प्रेट्र : भारतीय मूल के कनाडियन सांसद चंद्र आर्या ने अयोध्या में हुए राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए बुधवार को कहा कि यह पूरे विश्व के 1.2 अरब हिंदुओं के लिए नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन कनाडा में रहने वाले 10 लाख के करीब हिंदुओं सहित विश्व भर के लिए यादगार बन गया है।

कनाडा संसद में राम मंदिर पर एक बयान में बुधवार को उन्होंने कहा कि वह भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का ओटावा के एक मंदिर में हो रहे लाइव कवरेज का गवाह बने। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपनी सभ्यता का पुनर्निर्माण कर रहा है। उन्होंने इस दौरान दोनों देशों के संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक अवसर को साझा करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कनाडा और भारत एक दूसरे के प्राकृतिक सहयोगी रहे हैं।

'तमिलनाडु के मंदिरों में गैर-हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं'

मदुराई, प्रेट्र : मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पलानी मंदिर मामले में बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मंदिर में गैर-हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि मंदिर आस्था का केंद्र है न कि पर्यटन स्थल। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश के साथ-साथ मंदिर से जुड़े अधिकारियों को भी आदेश दिया है कि वो सभी नियम का सख्ती से पालन करें और 'ध्वज-स्तंभ से आगे गैर-हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं' लिखा हुआ बोर्ड लगाए। कोर्ट ने कहा कि रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार ही मंदिर का रखरखाव होना चाहिए। मंदिर संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत नहीं आते। ऐसे में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को गलत नहीं माना जा सकता है। मंदिर कोई पिकनिक स्थल नहीं है, जहां कोई भी घूमने-टहलने पहुंच जाए। कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। हाई कोर्ट की मदुराई पीठ की जस्टिस एस श्रीमति ने डी सेंथिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।

कर्नाटक में टीपू सुल्तान की मूर्ति को पहनाई चप्पलों की माला, तनाव

रायचूर, आइएएनएस : कर्नाटक के रायचूर जिला स्थित सिरवार शहर में टीपू सुल्तान की मूर्ति को चप्पलों की माला पहनाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद तनाव पैदा हो गया है। बुधवार तड़के कुछ शरारती तत्वों ने टीपू सुल्तान की प्रतिमा पर चप्पलों की माला पहना दी। लोगों को इसकी जानकारी सुबह हुई। इससे आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और टीपू सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क को अवरुद्ध कर दिया।

मोदी ने मीडिया से वार्ता में 'राम राम' से शुरू की बात

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

संसद परिसर में मीडिया से वार्ता में 'राम राम' से अपनी बात शुरू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी सदन में हुड़दंग करने वाले विपक्षी सांसदों पर जमकर बरसे और ऐसे सांसदों को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष की ओर से तीखी आलोचना स्वाभाविक है और इसका सभी स्वागत करते हैं। विपक्षी सांसदों की विचारपूर्ण आलोचना को आने वाले समय में भी याद किया जाएगा, लेकिन जिन सांसदों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान सिर्फ आदतन हंगामा और हुड़दंग किया, उनकी चर्चा भी नहीं होगी। ऐसे सांसदों के संसद में योगदान को शायद ही कोई याद करे, उनके संसद में काम के बारे में उनके क्षेत्र की जनता भी नहीं जानती। उन्होंने कहा कि संसद के नए भवन में हुई पहली बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर महिला सशक्तीकरण की नई गाथा लिखी गई। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन है, गुरुवार को महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।

****

22 पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नत किया है मुंबई पुलिस ने, इनमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक शामिल हैं। 1995 बैच के पुलिसकर्मी नायक कई अपराधियों का एनकाउंटर करने के बाद चर्चा में आए थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में साढ़े छह साल निलंबित रहने के बाद नायक बहाल हुए थे

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 1 फरवरी, 2024

हेमंत ने ईडी अफसरों पर एससी-एसटी एक्ट में दर्ज कराई प्राथमिकी

सीएम ने आरोप लगाया कि झूठे आरोपों में फंसाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा

आवास से बीएमडब्ल्यू कार व नकद बरामदगी पर दी सफाई, बोले- कार मेरी नहीं

राज्य ब्यूरो, रांची

रांची के जोनल कार्यालय से संबंधित अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल के खिलाफ किया है केस

रांची में बुधवार को आवास से राजभवन के लिए प्रस्थान के दौरान हेमंत सोरेन। प्रेट्र

दिल्ली से रांची तक ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में ईडी के चार अधिकारियों को नामजद करते अन्य के खिलाफ बुधवार को एससी-एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करवा दी। इन अधिकारियों के नाम कपिल राज, देवब्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल है। ये सभी अधिकारी ईडी के जोनल कार्यालय रांची से संबंधित हैं।

हेमंत सोरेन ने रांची के एससी-एसटी थाने में उक्त आवेदन देकर उपरोक्त अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया है। उनके आवेदन पर रांची के एससी-एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उधर, ईडी मुख्यालय के शीर्ष अधिकारी इस मामले में नामजद किए गए अपने अधिकारियों के बचाव के लिए कानूनी परामर्श ले रहे हैं। शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि वह अपने अधिकारियों के साथ खड़े हैं। हेमंत ने लिखा है कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 29 से 31 जनवरी तक पूछताछ के लिए रांची में रहने के लिए कहा था, इसी बीच मेरे दिल्ली स्थित आवास पर मेरी अनुपस्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के छापेमारी कर दी। उन्होंने प्राथमिकी में उल्लेख किया है कि वह अनुसूचित जनजाति से आते हैं और आदिवासी होने की वजह से झूठे आरोपों में फंसाकर मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सीएम ने आरोप लगाया है कि झूठे आरोपों में फंसाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। साथ ही गलत सूचनाएं भी प्रसारित कराई जा रही हैं, जिससे वह आहत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन में लिखा है कि 27 और 28 जनवरी को निजी कार्य निबटाकर जब वह रांची लौटे तो उन्होंने विभिन्न मीडिया माध्यमों में 30 जनवरी को दिल्ली में ईडी द्वारा झारखंड भवन और मेरे आवास में की गई छापेमारी से संबंधित समाचारों को देखा व पढ़ा। दिल्ली स्थित मेरे आवास से एक बीएमडब्ल्यू कार व भारी मात्रा में नकद बरामद किए जाने की खबरें भी मीडिया में प्रसारित हुईं। इस संबंध में हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है, कि उक्त कार उनकी नहीं है। नकदी बरामद किए जाने को लेकर लिखा है कि यह उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर बदनाम करने की कोशिश है।

झारखंड बनने के बाद सिर्फ रघुवर दास ही पूरा कर पाए कार्यकाल

राज्य ब्यूरो, रांची: हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य में बहुमत से सरकार बनने के बावजूद कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले मुख्यमंत्रियों में हेमंत का नाम भी शामिल हो गया है। झारखंड में अब तक एक ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यकाल पूरा किया है।

वर्ष 2020 में हुए चुनाव में झामुमो, राजद व कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला जिसके नेता के तौर पर हेमंत को चुना गया। चार साल तक हिचकोले खाते हुए सरकार आगे बढ़ती रही। बड़े बहुमत के बावजूद हेमंत सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की यह दूसरी पारी थी। इसके पूर्व भी वह लगभग डेढ़ साल तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अलग-अलग टर्म को जोड़कर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल अर्जुन मुंडा का रहा है। वह अलग-अलग समय में तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा शिबू सोरेन भी तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हालांकि उनका कार्यकाल कम ही रहा है।

ईडी ने पूर्व में 41 ठिकानों पर की थी छापेमारी

प्रथम पृष्ठ से आगे

ईडी ने पूर्व में इस मामले में 41 ठिकानों पर छापेमारी और पांच जगहों पर सर्वे किया था। छापेमारी में भूमि राजस्व विभाग की जाली मुहरें, जाली भूमि दस्तावेज, जालसाजों के बीच अपराध की कमाई के बंटवारे के प्रमाण, जालसाजी करने से संबंधित तस्वीरें तथा सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के प्रमाण से जुड़ी जानकारियां सामने आईं। रांची में सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में दर्ज प्राथमिकी से यह जांच शुरू हुई थी। इस मामले को टेकओवर कर ईडी ने जांच आगे बढ़ाई।

पूछताछ के लिए 10 समन : रांची जमीन घोटाला मामले में अगस्त 2023 से लेकर अबतक ईडी हेमंत को पूछताछ के लिए 10 समन भेज चुकी थी। आठवें समन के बाद हेमंत ने पूछताछ के लिए समय दिया था। इसके बाद 20 जनवरी को ईडी ने उनसे सात घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद बुधवार को उनसे इसी मामले में ईडी ने दोबारा पूछताछ की। इस पूछताछ के पहले ईडी ने सोमवार को हेमंत के दिल्ली दौरे के बीच उनके दिल्ली स्थित आवास तथा झारखंड भवन में छापेमारी की थी। उस वक्त हेमंत अपने आवास पर नहीं थे। सोमवार पूरे दिन वह कहां रहे, इस संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई।

सोमवार को भी यह चर्चा तेज रही कि ईडी हेमंत को दिल्ली में ही गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि इन चर्चाओं के बीच वह अचानक रांची पहुंच गए और मंगलवार अपराह्न एक बजे से लेकर देर रात तक सत्ता पक्ष के विधायकों, मंत्रियों तथा सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करते रहे। इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। ईडी के सख्त रुख को देख झामुमो और कांग्रेस ने पहले ही अपना प्लान बी तैयार कर रखा था। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में भी ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत से 17 नवंबर 2022 को नौ घंटे की पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान ईडी ने उनसे उनकी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा भी मांगा था। सीएम ने अपनी संपत्ति का ब्योरा भी सौंपा था।

विधायकों को लिखा पत्र, मेरे माता-पिता का ख्याल रखना

राज्य ब्यूरो, रांची : हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के पूर्व बुधवार को समर्थक विधायकों के नाम मार्मिक अपील जारी की। उन्होंने आग्रह किया है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके माता-पिता का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वह बीमार हैं। साथ ही लिखा है कि मेरे छोटे भाई पर स्नेह बनाए रखें।

नई सरकार का गठन होने तक विधायकों से रांची में रहने का किया आग्रह

विधायकों को संबोधित पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि आप अवगत हैं कि 30 जनवरी को पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसी विपरीत परिस्थिति में अगर मुझे नेता विधायक दल का अपना पद छोड़ना पडा तो उस परिस्थिति में विधायक दल के नए नेता का चयन मेरे द्वारा किया जाएगा, जो सर्वमान्य होगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर सभी गठबंधन दल के विधायकों की बैठक में भी सहमति जताई गई थी। उधर, रात 11.08 बजे हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल से एक कविता भी पोस्ट की गई, जिसमें हमेशा संघर्षरत रहने और हार नहीं मानने की बात कही गई है।

हेमंत ने लिखा है - मैं ईडी के समन के अनुपालन में उपस्थित होने जा रहा हूं। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में सम्यक विचारोपरांत चम्पाई सोरेन को विधायक दल का नया नेता नामित करने का निर्णय लिया है। विधायक दल की बैठक में इन्हें विधिवत रूप से विधायक दल का नेता चुनने के उपरांत सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उनका समर्थन पत्र लेकर नए नेता के नेतृत्व में आप सभी राज्यपाल के समक्ष जाकर नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे एवं अपनी एकता का परिचय देते हुए नई सरकार के गठन तक रांची में उपस्थित रहेंगे।

कोल्हान टाइगर के नाम से लोकप्रिय हैं चम्पाई

जासं, जमशेदपुर : झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद महागठबंधन दल के नेता चुने गए चम्पाई सोरेन कोल्हान टाइगर के नाम से लोकप्रिय हैं। सरायकेला-खरसावां जिला स्थित जिलिंगगोड़ा गांव के निवासी चम्पाई सोरेन को कोल्हान टाइगर की उपाधि 2016 में तब मिली थी, जब इन्होंने 1990 में टाटा स्टील के अस्थायी श्रमिकों के अनिश्चितकालीन गेट जाम आंदोलन कर लगभग 1700 ठेका मजदूरों की कंपनी में स्थायी प्रतिनियुक्ति कराई थी। चम्पाई ने राजनीति के क्षेत्र में मजदूर आंदोलन से ही कदम रखा था। इस आंदोलन के बाद यह धारणा बन गई थी कि चम्पाई जहां भी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, वहां जीत मिलेगी।

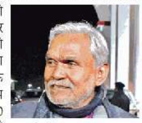

चम्पाई सोरेन। एएनआइ

झामुमो सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री चम्पाई विवादरहित रहे हैं। पार्टी में शिबू सोरेन के बाद सबसे ज्यादा आदर इन्हीं को मिलता है। 11 नवंबर 1956 को जन्मे चम्पाई ने दसवीं तक की पढ़ाई बिष्टुपुर स्थित रामकृष्ण मिशन उच्च विद्यालय से की थी। चम्पाई सोरेन पहला चुनाव सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से 1991 में निर्दलीय लड़े और जीते थे। इसके बाद 1995 में झामुमो का टिकट मिला और जीते थे। 2000 में भाजपा के अनंतराम टुडू से हार गए थे। इसके बाद चम्पाई 2005 से लगातार 2009, 2014 व 2019 में विजयी रहे हैं। चम्पाई के चार पुत्र व तीन पुत्री हैं।

2009 में पहली बार बने थे मंत्री : चम्पाई सोरेन 2009 से 2014 की राज्य सरकार में पहली बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्रम व आवास विभाग के मंत्री बने, फिर उन्हें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया। 2014 और 2019 में भी चम्पाई परिवहन मंत्री बनाए गए।

सोरेन की गिरफ्तारी पर भाजपा ने कसा तंज, कांग्रेस बोली- संघवाद पर आघात

शहजाद पूनावाला मल्लिकार्जुन खरगे राहुल गांधी

- पूनावाला ने कहा, आइएनडीआइए के भ्रष्टाचार में जुड़ी एक और उपलब्धि
- मल्लिकार्जुन खरगे बोले- जो प्रधानमंत्री के साथ नहीं गया, वह जाएगा जेल
- भाजपा का 'विपक्ष मिटाओ प्रकोष्ठ' बन चुकी हैं जांच एजेंसियां : राहुल

नई दिल्ली, प्रेट्र : हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए भाजपा ने बुधवार को इसे विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के भ्रष्टाचार में जुड़ी एक और उपलब्धि बताया। वहीं, कांग्रेस ने कहा,ईडी का इस्तेमाल करके सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना संघवाद पर आघात है।

झारखंड में घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'झारखंड से विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए में भ्रष्टाचार की एक और महान उपलब्धि जुड़ गई है।' पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा, 'एक वक्त था जब केजरीवाल लालू, सोरेन, सोनिया को गिरफ्तार करने की मांग करते थे। इन दिनों वह इन सभी का बचाव करते हैं क्योंकि वह खुद भी शराब घोटाले (आबकारी नीति घोटाला) के मुख्य साजिशकर्ता हैं।' भाजपा के राज्यसभा सदस्य व झारखंड इकाई के पूर्व प्रमुख दीपक प्रकाश ने कहा, 'झारखंड के लोगों को आज न्याय मिल गया। अपने चार वर्ष के कार्यकाल में हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूट-खंड में बदलने की कोशिश की। वह सभी घोटालों- शराब घोटाले, भूमि घोटाले और खनन घोटाले के राजा हैं। उनके समर्थकों ने भी झारखंड को खूब लूटा है।'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'जो मोदी जी के साथ नहीं गया, वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे ईडी लगाकर उन्हें त्यागपत्र देने को मजबूर करना संघवाद पर आघात है।' उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग (पीएमएलए) के प्रविधानों को दमनकारी बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना-धमकाना भाजपा की टूलकिट का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत एक-एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपा का काम जारी है। खरगे ने कहा, 'भाजपा की वाशिंग मशीन में जो चला गया वह सफेदी की चमकार से साफ है, जो नहीं गया वह दागदार है? तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे।' पार्टी नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'ईडी, सीबीआइ और आयकर विभाग आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रहीं, अब यह भाजपा का विपक्ष मिटाओ प्रकोष्ठ बन चुकी हैं।' उन्होंने कहा, 'खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है।' शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि हेमंत सोरेन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह 'पलटी' नहीं मार पाए और इसीलिए उसकी कीमत चुका रहे हैं।

आइएनडीआइए ने बैठक कर की हालात पर चर्चा

सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के घटक दलों के नेताओं ने बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर एक बैठक की और ताजा हालात पर चर्चा की। बैठक में सोनिया गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, राकांपा प्रमुख शरद पवार और द्रमुक नेता टीआर बालू समेत कई नेता उपस्थित थे। गौरतलब है कि सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आइएनडीआइए का एक घटक है।

देश के पांच और वेटलैंड को मिला रामसर साइट का दर्जा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के एक दिन पहले भारत के पांच और वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। इनमें दो वेटलैंट तमिलनाडु के और तीन कर्नाटक के हैं। इसके साथ ही देश के 80 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। रामसर कन्वेंशन के महासचिव डा.मुसोंडा मुंबा से बुधवार को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को इसके प्रमाण पत्र सौंपे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक 2014 से पहले देश के सिर्फ 26 वेटलैंड इसमें शामिल थे। अब 80 वेटलैंड इसमें शामिल हैं। पिछले तीन सालों में 38 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। रामसर साइट में शामिल किए गए पांच नए वेटलैंड में अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुएरी और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में स्थित हैं, जबकि कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लांगवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में हैं। ज्ञात हो, ईरान के रामसर शहर में वेटलैंट संरक्षण को लेकर दो फरवरी 1971 में हुए अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत यह दर्जा दिया जाता है।

आपराधिक मामला विचाराधीन होने पर रेलकर्मियों को पदोन्नति नहीं

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

- पदोन्नति और एमएसीपी का लाभ पाने वाले अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की होगी समीक्षा
- वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी ने बोर्ड के निर्देशों का हवाला देते हुए विभागों को लिखी चिट्ठी

आपराधिक मामलों में मुकदमा या प्रकरण विचाराधीन होने पर रेलकर्मियों की पदोन्नति नहीं होगी। उन्हें माडिफाइड एस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसीपी) का भी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अराजपत्रित रेल कर्मचारी जो आपराधिक मामला होने के बाद भी पदोन्नति व एमएसीपी का लाभ पा रहे हैं, उनकी समीक्षा होगी। उन्हें लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। इस दौरान कर्मी सेवानिवृत्त होता है, तो उसे तब तक प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी, जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता।

पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी गोपाल प्रसाद ने रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए सभी विभागों व कारखानों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे रेल कर्मचारी जिनके खिलाफ 3 आरपीयूपी एक्ट (रेल संपत्ति अधिनियम) या कहीं भी आपराधिक मामला लंबित है। उन्हें पदोन्नति व एमएसीपी का लाभ दिया गया है तो उनके प्रकरण की समीक्षा की जाए। पदोन्नति और एमएसीपी का लाभ पा चुके सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के मामले में भी समीक्षा की जाए।

एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) के महामंत्री केएल गुप्ता ने शील्ड कवर प्रोसीजर (आपराधिक मामलों में पदोन्नति व अन्य आर्थिक लाभ से वंचित होना) के निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यांत्रिक कारखाना और कार्मिक आदि विभागों में कई ऐसे रेलकर्मी हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। इसके बाद भी वह पदोन्नति तथा एमएसीपी का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे मामलों में रेलकर्मियों पर शील्ड कवर प्रोसीजर लागू होना चाहिए। जिन लोगों के चलते रेलवे की छवि धूमिल हो रही है, उनकी समीक्षा अवश्य होनी चाहिए।

लालू, राबड़ी को जमीन के बदले नौकरी मामले में नया समन

राज्य ब्यूरो, पटना : जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। 29 जनवरी को लालू प्रसाद से और इसके अगले दिन तेजस्वी यादव से प्रवर्तन निदेशालय की लंबी पूछताछ को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि लालू, राबड़ी परिवार को एक नया समन मिल गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को कोर्ट में तलब किया है। ईडी की चार्जशीट को आधार बनाकर कोर्ट ने लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बड़ी पुत्री व राज्यसभा सदस्य डा. मीसा भारती और हेमा यादव समेत अन्य को समन देकर नौ फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

बुधवार की शाम करीब साढ़े चार बजे 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पहुंचकर एक अधिकारी ने लालू परिवार को एक नया समन सौंपा। इसके बाद से कयास लगने शुरू हो गए कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से लालू परिवार को पूछताछ के लिए नया समन दिया गया है।

200 करोड़ के बैंक घोटाले में बीपीएल के नौ परिसरों पर ईडी की दबिश

जागरण संवाददाता, लुधियाना

- पेपर बोर्ड और पैकेजिंग मैटीरियल बनाने का काम करती है बीपीएल
- जांच एजेंसी ने जम्मू, पंजाब व उत्तर प्रदेश में नौ जगहों पर की कार्रवाई

भारत पेपर्स लिमिटेड (बीपीएल) से संबंधित 200 करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले और प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के मामले में ईडी बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नौ परिसरों में दबिश दी। जालंधर स्थित ईडी कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, यह कार्रवाई बाहर से आई टीम ने की है। जालंधर से केवल दो अधिकारियों को टीम में रखा गया था।

जानकारी के अनुसार, सितंबर, 2006 में स्थापित बीपीएल जम्मू और लुधियाना स्थित एक पेपर बोर्ड पैकेजिंग उद्योग भारत बाक्स फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीबीएफआइएल) की सहयोगी कंपनी है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, जेएंडके बैंक, पीएनबी और करूर वैश्य बैंक जैसे बैंकों के साथ लगभग 200 करोड़ रुपये के ऋण की धोखाधड़ी की है। आरोप है कि कंपनी के निदेशकों ने फर्जी चालान

जारी करके ऋणदाता बैंकों की अनुमति के बिना आयातित व स्वदेशी मशीनरी की बिक्री की और अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए पैसे को खुर्द-बुर्द किया। ईडी की करीब 20 टीमों ने बुधवार सुबह एक साथ कार्रवाई आरंभ की थी। लुधियाना में भामियां रोड पर बनी भारत बाक्स फैक्ट्री में सुबह 7.30 बजे ईडी की टीम पहुंची। दोपहर में कई कर्मचारियों को फैक्ट्री के पीछे लगे शटर खोलकर निकाला गया।

ममता के मंत्री ने भगोड़े टीएमसी नेता की स्वतंत्रता सेनानी से की तुलना

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के सिंचाई व ऊर्जा मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने पिछले दिनों राज्य में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के साजिशकर्ता फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना की है। वहीं मंत्री के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि चोर, अपराधियों की पार्टी से इससे अधिक और क्या उम्मीद की जा सकती है।

शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने फरार पार्टी नेता के बारे में कहा है कि अंग्रेज भी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढ नहीं पाए थे। कई राज्यों में अभी भी कई अपराधी घूम रहे हैं। हमेशा इनका पता लगा लिया जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। वहीं तृकां महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जहां तक मैंने सुना है घटना के दिन शाहजहां वहां नहीं था। बता दें कि पांच जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में तृकां नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापामारी करने गई ईडी की टीम पर हमला हुआ था। इसमें तीन अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। हमले का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख घटना के दिन से ही फरार है।

आतंकियों की तरह नक्सलियों ने बीजापुर के जंगल में बनाई सुरंग

कार्रवाई

80 मीटर लंबी, 10 फीट गहरी और तीन फीट चौड़ी सुरंग को किया गया नष्ट, वापसी के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ में एसटीएफ के जवान के भाई की मौत

नईदुनिया टीम, रायपुर

हमास और अलकायदा जैसे आतंकियों की तर्ज पर बस्तर के नक्सलियों ने खुद के बचाव के लिए लंबी सुरंग बनाई है। तलाशी अभियान के दौरान जवानों को छत्तीसगढ़ में बीजापुर के बोड़गा के जंगल में ऐसी ही एक सुरंग की जानकारी मिली। जवानों ने इसे नष्ट कर दिया है। 80 मीटर लंबी यह सुरंग 10 फीट गहरी और तीन फीट चौड़ी थी। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि सुरंग में 100 नक्सली आसानी से छुप सकते थे।

पुलिस के अनुसार सुरंग को नष्ट करने के बाद जवान लौट रहे थे तभी नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। जवानों की ओर से की गई कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद तलाशी के दौरान ज्ञात हुआ कि एक एसटीएफ जवान के भाई रमेश ओयाम की मौत क्रास फायरिंग में हुई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मुठभेड़ के बीच में वह कैसे आ गया।

जवानों के खून की एक-एक बूंद का लेंगे हिसाब : साय : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को और तेज किया जाएगा। सुकमा जिले के टेकुलगुड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़ में बलिदान हुए तीन जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि जवानों के खून की एक-एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा।

300 नक्सलियों ने जवानों को घेरकर किया था हमला : सुकमा जिले के टेकुलगुड़ा में मंगलवार को हुए हमले में 300 से अधिक नक्सली शामिल थे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। नक्सलियों ने दोपहर लगभग 12 बजे कैंप के आसपास के क्षेत्र में गश्त पर निकले जवानों को घेरकर फायरिंग की। बचने के लिए जब जवान दूसरी ओर भागने लगे तब दूसरी ओर छिपे नक्सलियों की दूसरी टीम ने फायरिंग शुरू कर दी। साढ़े चार घंटे तक चली मुठभेड़ में तीन जवान बलिदान हो गए थी। 15 जवान घायल हुए थे। जवानों का दावा है कि मुठभेड़ में कम से कम छह नक्सली मारे गए हैं।

बीजापुर के जंगल में नक्सलियों द्वारा बनाई गई सुरंग, जिसे जवानों ने ध्वस्त कर दिया। सौ. पुलिस

छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और उनके करीबियों के यहां आयकर छापे

नईदुनिया, रायपुर

- संपत्ति का जुटाया जा रहा ब्योरा और खंगाले जा रहे लैपटाप

कोयला व चावल घोटाले के आरोपों से घिरे छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और उनके करीबियों के यहां बुधवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर की टीम ने सुबह पूर्व मंत्री भगत के घर, कार्यालय, पाइप फैक्ट्री के साथ ही पैतृक निवास और निज सहायक राजेश वर्मा, डा. एफ टोप्पो, उपनिरीक्षक रूपेश नारंग, वाहन चालक महेंद्र कुमार व व्यावसायिक सहयोगी हरपाल सिंह अरोरा के यहां कार्रवाई की।

सूत्रों के अनुसार, बरामद लैपटाप के साथ दस्तावेज की जांच की जा रही है। सभी के आय के स्रोत जांचे जा रहे हैं। यह कार्रवाई ओडिशा, मप्र और महाराष्ट्र की संयुक्त 150 सदस्यीय टीम द्वारा की जा रही है। पूर्व खाद्य मंत्री भगत, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी रहे थे। आयकर की यह कार्रवाई भिलाई निवासी कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के ठिकानों पर भी की गई। बताया जाता है कि बंसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं।

> परेशान करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। अभी आने वाले दिनों में राहुल गांधी का प्रदेश में दौरा है, इसलिए उसमें रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। - अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री

> यह कार्रवाई गरीब जनता की आह है। प्रतिशोध तो गरीब जनता ने ले लिया है। - विजय शर्मा, गृह मंत्री

31 लाख 40 हजार लोगों को अब हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन देगी हरियाणा सरकार। कैबिनेट ने 14 पेंशन योजनाओं के लिए 250 रुपये मासिक वृद्धि को दी मंजूरी। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को दिव्यांगता की श्रेणी में मिलेगी पेंशन।

न्यूज गैलरी

स्कूल में तलवार लेकर पहुंचे छात्र ने मचाया उत्पात

इंदौर : इंदौर के भारती बाल मंदिर स्कूल में 10वीं कक्षा का 15 वर्षीय एक छात्र पढ़ाई के लिए सख्ती करने पर इतना गुस्सा गया कि तलवार लेकर स्कूल पहुंच गया और तोड़फोड़ कर दी। घटना का वीडियो सामने आने और प्राचार्य अजय पावड़े की शिकायत के बाद पुलिस ने मंगलवार रात छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप यह भी है कि उत्पात मचाने के दौरा छात्र ने स्टाफ और छात्रों के साथ भी अभद्रता की। (नईदुनिया)

चेक बाउंस मामले में पूर्व क्रिकेटर गिरफ्तार

नागपुर : शहर पुलिस ने बुधवार को चेक बाउंस मामले में गैरजमानती वारंट (एनबी डब्ल्यू) जारी होने पर पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर प्रशांत वैद्य को गिरफ्तार कर लिया। भारत के लिए चार अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले वैद्य को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जमानती बांड पर उन्हें रिहा कर दिया। पुलिस ने बताया कि वैद्य ने स्थानीय व्यापारी से स्टील खरीदी थी और चेक से भुगतान किया था। हालांकि चेक बाउंस हो गया। जानकारी के बाद भी भुगतान न करने पर व्यापारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। (प्रेट्र)

मनी लांड्रिंग मामले में केरल के पूर्व मंत्री की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली : ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में केरल के पूर्व मत्स्य पालन व बंदरगाह मंत्री के. बाबू की 25 लाख से अधिक की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। पीएमएलए के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश 25 जनवरी को जारी हुआ था। मामले की जांच आय से अधिक संपत्ति रखने से जुड़ी है। यह मामला 2018 में केरल सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एर्नाकुलम जिले में पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज मामले से उपजा है। (प्रेट्र)

उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। खालिद दिल्ली दंगों की साजिश करने में शामिल होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत जेल में बंद है। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने समय की कमी के कारण यूएपीए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं समेत कई मामलों में सुनवाई नहीं की। (आइएएनएस)

केरल में तिहरे हत्याकांड के दोषी को मौत की सजा

कोच्चि : केरल की एक अदालत ने तिहरे हत्याकांड के दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक बिंदु पीए ने बताया कि अदालत ने अपने सबसे बड़े भाई की 33 वर्षीय बेटी की हत्या में मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने भाई और भाभी की हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने समेत विभिन्न अपराध में 46 साल की सुनाई और 4.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि दोषी की मृत्युदंड की सजा की पुष्टि केरल हाई कोर्ट को करनी होगी। (प्रेट्र)

सौतेली बेटी से दुष्कर्म में दोषी को 82 साल कैद की सजा

कोच्चि : केरल की अदालत ने राज्य में रहने वाले असम के व्यक्ति को दो साल तक सौतेली बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और गर्भवती करने के आरोप में 82 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और दोषी द्वारा जुर्माना जमा करने पर पीड़िता को दिए जाने का निर्देश दिया। विशेष लोक अभियोजक सिंधु ने बताया कि पेरुंबवूर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जस्टिस दिनेश एम. पिल्लई ने पाक्सो के विभिन्न प्रविधानों के तहत चार अपराधों के लिए दोषी को 20-20 साल और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दो साल कुल मिलाकर 82 साल की सजा सुनाई। हालांकि सजाएं एक साथ चलने के कारण दोषी को 20 साल की जेल काटनी होगी। (प्रेट्र)

'जो समुदाय चुनाव पर असर डाल सकता है, वह अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता'

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध करते हुए प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील

कहा, अनुच्छेद-30 में अल्पसंख्यकों का मतलब संख्या से नहीं, चुनाव क्षमता से

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर विवाद। फाइल फोटो

अदालत ने कहा

- किसी अल्पसंख्यक संस्थान के राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने में मौलिक रूप से कुछ भी असंगत नहीं है। यह भी हमें समझना होगा।
- हम व्यापक संदर्भ में न जाएं और संसद की शक्तियों को कमजोर न करें।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में मुसलमानों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले एक छात्र की ओर से पेश वकील यतीन्द्र सिंह ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, संविधान के अनुच्छेद-30 में अल्पसंख्यकों का जो जिक्र है, उसमें अल्पसंख्यकों का अर्थ संख्या में अल्पसंख्यक से नहीं, बल्कि चुनावी क्षमता से है। जो समुदाय चुनाव पर असर डाल सकता है, वह अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। सिंह ने मुसलमानों का वोट बांटने की राजनीति के लिए कुछ दलों व नेताओं का नाम भी लिया जिस पर कोर्ट ने उन्हें रोक दिया और दलीलें संवैधानिक व कानूनी पहलू तक सीमित रखने को कहा।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ आजकल एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई कर रही है। बुधवार को इस मामले में एक छात्र की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील यतीन्द्र सिंह ने बहस की। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यक दर्जा संख्या से नहीं, बल्कि चुनावी क्षमता से तय किया जाना चाहिए। जो समुदाय चुनाव पर असर डाल सकता है, वह अल्पसंख्यक नहीं हो सकता।,अनुच्छेद-30 में दिए गए अल्पसंख्यक का मतलब चुनावी अल्पसंख्यकों से है। उदाहरण के लिए वह वर्ग या समुदाय जो चुनाव पर असर नहीं डाल सकता, जैसे पारसी, बौद्ध, सिख व ईसाई, जिनकी संख्या बहुत कम है। ये समुदाय चुनाव पर असर नहीं डाल सकते। जो समुदाय चुनाव नतीजे पर असर डाल सकते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। 2011 की जनगणना के मुताबिक, मुसलमान 14.2 प्रतिशत थे, जो अब करीब 23 प्रतिशत हैं। मुस्लिम वोट बैंक चुनाव पर असर रखता है। उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। सिंह ने कहा, कोर्ट यह तय करने में सक्षम नहीं है कि मुसलमान चुनाव पर असर डाल सकते हैं या नहीं, इसलिए यह तय करने के लिए मामला एक आयोग को भेजा जाए।

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र में तो असर पड़ेगा ही। चुनाव पर असर पड़ता है या नहीं, ये तो हर निर्वाचन क्षेत्र में भिन्न होगा। ज्ञात हो,अनुच्छेद-30 अल्पसंख्यकों को पसंद के संस्थान स्थापित करने व उन्हें संचालित करने का हक देता है। एएमयू की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने केंद्र के इस आरोप का खंडन किया कि एएमयू ने 1920 में कानून के जरिये विश्वविद्यालय बनाए जाते वक्त अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा छोड़ा था। धवन ने कहा, एएमयू ने कभी भी अल्पसंख्यक दर्जा नहीं छोड़ा था। ऐसी दलीलें देकर प्रतिवादी शब्दों से खेल रहे हैं। धवन ने कहा कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा हमेशा जारी रहा और यह बात एएमयू एक्ट, 1920 के उद्देश्य, प्रस्तावना आदि को समग्रता से देखने पर बात स्पष्ट होती है।

नए आइटी नियमों पर बांबे हाई कोर्ट का खंडित फैसला, नई पीठ करेगी सुनवाई

- महाधिवक्ता ने अदालत को दिए गए पहले के आश्वासन को दस दिनों के लिए बढ़ाने पर जताई सहमति

राज्य ब्यूरो, मुंबई

बांबे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने इंटरनेट मीडिया पर सरकार के खिलाफ फर्जी खबरों से निपटने के लिए संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया है। खंडपीठ के एक न्यायमूर्ति गौतम पटेल याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमत हुए, वहीं दूसरी न्यायमूर्ति नीला गोखले ने सरकार के पक्ष को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति पटेल ने कहा,मैंने याचिकाओं पर विचार कर उनसे सहमति जताई है और न्यायमूर्ति गोखले ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। इसलिए, अब इस मामले की सुनवाई तीसरे न्यायाधीश द्वारा नए सिरे से की जाएगी। अब यह मामला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा, जो इसे तीसरे न्यायाधीश को सौंपेंगे। इसके बाद महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत को दिए गए पहले के आश्वासन को दस दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई। यानी, जब तक फैसला नहीं आ जाता सरकार संशोधित आइटी नियमों के तहत स्थापित की जाने वाली फैक्ट चेकिंग यूनिट (एफसीयू) को इंटरनेट मीडिया पर फर्जी, झूठे व भ्रामक तथ्यों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने के लिए अधिसूचित नहीं करेगी। नियमानुसार, यदि एफसीयू को ऐसे किसी पोस्ट के बारे में पता चलता है या उसके बारे में सूचित किया जाता है, जो फर्जी है या जिसमें सरकार के कामकाज से संबंधित भ्रामक तथ्य हैं तो वह इसे इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों को भेज देगा। एक बार जब ऐसी पोस्ट चिह्नित कर ली जाती है तो मध्यस्थ के पास पोस्ट को हटाने या उस पर अस्वीकरण लगाने का विकल्प होता है।

उल्लेखनीय है कि ये याचिकाएं स्टैंड-अप कमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया और एसोसिएशन आफ इंडियन मैगजींस ने दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित एफसीयू को मनमाना और असंवैधानिक बताया है। दावा किया कि इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि वह सरकार को निशाना बनाने वाली किसी भी तरह की राय, आलोचना, व्यंग्य या हास्य के खिलाफ नहीं है। यह नियम केवल इंटरनेट मीडिया पर नकली, झूठे और भ्रामक तथ्यों को प्रतिबंधित करने के लिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के छह पुलिसकर्मियों पर लगाया 12 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के छह पुलिसकर्मियों पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिसकर्मियों पर न्यायिक आदेश के बिना तीन लोगों को अवैध हिरासत में लेने और उनके किराये के परिसरों को ध्वस्त करने का आरोप है।

जलगांव के छह पुलिसकर्मियों ने विजयकुमार, विश्वनाथ धावले व विनोद देधू चौधरी समेत तीन किरायेदारों को नौ मार्च 2022 को थाने बुलाया और 24 घंटे के लिए हिरासत में रखा। जस्टिस विक्रम नाथ व सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 30 जनवरी को दिए आदेश में कहा, इस बीच बंदियों के किराये के परिसरों को पूर्व मालिक के रिश्तेदारों ने ध्वस्त कर दिया और किरायेदारों को परिसर खाली करने संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। बाद में संपत्ति के खरीदने वालों ने बेदखल किरायेदारों को 10-10 लाख रुपये का भुगतान किया था। इससे किरायेदारों, पूर्व मालिकों के बीच विवाद का निपटारा हुआ। शीर्ष अदालत ने इस मामले में आपराधिक मामलों की सुनवाई तो बंद कर दी पर पुलिस कर्मियों पर दोनों शिकायतकर्ताओं को छह-छह लाख रुपये देने का निर्देश दिया।

आइआइएमसी को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा

- संस्थान को डिग्री प्रदान करने का मिला अधिकार, आइआइएमसी में दिया जाता है पत्रकारिता में प्रशिक्षण

आइआइएमसी की फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय जनसंचार संस्थान (आइआइएमसी) को विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा, डीम्ड विश्वविद्यालय को सिर्फ डिप्लोमा के बजाय डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। यह घोषणा आइआइएमसी नई दिल्ली और जम्मू (जम्मू और कश्मीर), अमरावती (महाराष्ट्र), आइजोल (मिजोरम),कोट्टायम (केरल), और ढेंकनाल (ओडिशा) में स्थित इसके पांच क्षेत्रीय परिसरों के लिए हुई है। इस नई स्थिति के साथ आइआइएमसी अब डाक्टरेट डिग्री सहित अन्य डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत 17 अगस्त 1965 को स्थापित यह संस्थान देश में अपनी तरह के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जो पत्रकारिता में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जाना जाता है तथा मीडिया और जन संचार के क्षेत्र में सार्थक अनुसंधान करता है। आइआइएमसी भारतीय सूचना सेवा के अफसरों के लिए प्रशिक्षण अकादमी भी है। आइआइएमसी ने एक्स पर पोस्ट किया, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली व इसके पांच केंद्रों को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए यूजीसी को धन्यवाद। आइआइएमसी जनसंचार में बड़े पैमाने पर शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान को बढ़ावा देने को लेकर सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। आइआइएमसी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने का विचार नया नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2016 में इस योजना को मंजूरी दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 32 सप्ताह से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति देने से किया इन्कार

- याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया
- कहा- मेडिकल वोर्ड ने माना है कि भ्रूण पूरी तरह से सामान्य

सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में अपने पति को खो चुकी 26 वर्षीय एक महिला को 32 सप्ताह से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति देने से बुधवार को इन्कार कर दिया। कहा-मेडिकल बोर्ड ने यह माना है कि भ्रूण किसी भी तरह से असामान्य नहीं है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वरले की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 जनवरी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। हाई कोर्ट ने इस आदेश में चार जनवरी के अपने पहले के उस फैसले को वापस ले लिया था जिसमें महिला को 29 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा- 'यह 32 सप्ताह का भ्रूण है। इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? मेडिकल बोर्ड ने भी कहा है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। केवल दो सप्ताह की बात है, फिर आप चाहें तो इसे गोद लेने के लिए दे सकते हैं।' महिला की ओर से पेश वकील अमित मिश्रा ने कहा कि अगर वह बच्चे को जन्म देगी तो यह उसकी इच्छा के खिलाफ होगा और उसे जीवन भर यह सदमा झेलना होगा। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने प्रत्येक बिंदु पर विचार किया है, जिसमें मेडिकल बोर्ड की राय भी शामिल है। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि हम मेडिकल बोर्ड की राय से आगे नहीं जा सकते। मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि यह एक सामान्य भ्रूण है। यह भी राय दी गई है कि यदि याचिकाकर्ता गर्भावस्था जारी रखती है तो उसे भी कोई खतरा नहीं है। मिश्रा ने दलील दी कि महिला एक विधवा है और उसे जीवन भर सदमा सहना होगा तथा अदालत को उसके हित पर विचार करना चाहिए। इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि हमें केवल उसके हित पर ही विचार क्यों करना चाहिए? इसके बाद पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने अवसाद से पीड़ित विधवा को चार जनवरी को 29 सप्ताह के भ्रूण को इस आधार पर समाप्त करने की अनुमति दे दी थी कि गर्भावस्था जारी रखने से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। साथ ही कहा था कि प्रजनन विकल्प के अधिकार में प्रजनन न करने का अधिकार भी शामिल है। इसके बाद हाई कोर्ट का 24 जनवरी का आदेश केंद्र द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद आया था, जिसमें गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की अनुमति देने वाले चार जनवरी के आदेश को इस आधार पर वापस लेने का आग्रह किया गया था कि बच्चे के जीवित रहने की उचित संभावना है और अदालत को अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार की सुरक्षा पर विचार करना चाहिए।

उड़ी में सौ फीट गहरी खाई में गिरा वाहन, आठ की मौत

- फिसलन भरी सड़क पर तेज गति से वाहन दौड़ा रहा था चालक
- वाहन में क्षमता से अधिक सवारियों को वैठाया गया था

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के उड़ी इलाके में बुधवार को एक यात्री वाहन गहरी खाई में गिरा। इसमें चार महिलाओं समेत आठ की मौत हो गई और सात घायल हो गए। हादसे का कारण बर्फ से फिसलन भरी सड़क पर वाहन की तेज गति और उसमें क्षमता से दुगने यात्रियों का सवार होना बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

हादसा उड़ी में एलओसी के साथ सटे बुजथालन के पास हुआ। दोपहर को टाटा सूमो वाहन यात्रियों को लेकर बारामुला की तरफ रवाना हुआ। बुजथालन से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी पर मोड़ पर वाहन बेकाबू हो गया और लगभग सौ फीट गहरी खाई में जा गिरा। वाहन जब नीचे खाई में जमीन पर टकराया तो उसके परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार कई यात्री खाई में इधर-उधर गिरे पड़े थे। सूचना मिलते ही स्थानीय, पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सभी ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बोनियार स्थित अस्पताल में पहुंचाया। ब्लाक मेडिकल आफिसर डा. खुर्शीद अहमद खान ने बताया कि अस्पताल में उपचार के लिए लाए गए 15 घायलों में से सात की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। सात घायलों को राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल बारामुला रेफर किया गया है। घायलों में तीन की हालत गंभीर है।

उत्तरी कश्मीर में बारामुला जिले के उड़ी इलाके में सौ फीट गहरी खाई में गिरा वाहन। हादसे में आठ की मौत और सात यात्री घायल हुए हैं। सौजन्य: पुलिस

संदिग्ध जासूस कबूतर को आठ माह बाद किया गया रिहा

मुंबई, प्रेट्र: चीनियों द्वारा जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संदिग्ध कबूतर को आठ माह बाद रिहा कर दिया गया। उसे पकड़े जाने के बाद एक पशु अस्पताल में रखा गया था। आरसीएफ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, परेल इलाके में बाई सकरबाई दिनशा पेटिट हास्पिटल फार एनिमल्स ने सोमवार को पुलिस से पक्षी को छोड़ने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद मंगलवार को उसे मुक्त कर दिया गया।

कबूतर को मई 2023 में आरसीएफ पुलिस ने चेंबूर इलाके के पीर पाउ जेट्टी में पकड़ा था। पक्षी के पैर में दो छल्ले बंधे थे। उसके दोनों पंखों के नीचे चीनी भाषा में कुछ संदेश लिखे हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद जासूसी का आरोप हटा दिया गया। अधिकारी ने कहा, पुलिस को पता चला कि कबूतर ताइवान में खुले पानी में रेसिंग में भाग लेता था। ऐसे ही एक कार्यक्रम के बाद वह उड़कर भारत आ गया। पुलिस द्वारा कबूतर की रिहाई के लिए ''अनापत्ति'' दिए जाने के बाद अस्पताल ने कबूतर को मुक्त कर दिया। पक्षी पूरी तरह से ठीक है।

मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ शावक की मौत

नईदुनिया, उमरिया

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कल्लवाह परिक्षेत्र में एक बाघ शावक की मौत हो गई। रिजर्व में इस साल यह चौथे बाघ की मौत है। वन परिक्षेत्र कल्लवाह में गश्त के दौरान शव मिला। शावक की उम्र दो साल बताई जा रही है। उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी मौत दूसरे बाघ के हमले में हुई है। आसपास दूसरे बाघ के पदचिह्न भी मिले हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डिप्टी फील्ड डायरेक्टर पीके वर्मा ने भी यही कहा कि घटना आपसी संघर्ष का परिणाम है।

बाघिन का साथ पाने के लिए हमले की आशंका : जिस शावक पर बाघ ने हमला किया है, वह अपने कुनबे के साथ था। बाघ ने बाघिन का साथ पाने के लिए उसके शावकों पर हमला किया। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि इस शावक के अलावा भी दो अन्य शावक भी बाघिन के साथ थे। हालांकि, अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि अन्य शावकों और हमलावर बाघ की क्या स्थिति है। जब दो बाघों के बीच झगड़ा होता है तो दोनों चोटिल होते हैं। इस दृष्टिकोण से दूसरे बाघ की वन प्रबंधन तलाश कर रहा है।

फाइल फोटो

कब-कब मौत

- 10 जनवरी को पतोर रेंज चिल्हारी बीट के कुशहा नाल में 15-16 महीना के बाघ शावक का कंकाल पाया गया था।
- 16 जनवरी को धमोखर परिक्षेत्र के ग्राम बरबसपुर से करीब एक किमी दूर नर बाघ शावक का शव मिला।
- 23 जनवरी को मानपुर बफर रेंज के पटपरिया हार में एक बाघिन का शव पाया गया।

गुजरात में फर्जी अंकपत्र से बना डाक्टर, 44 साल बाद मिली सजा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद: 12वीं की फर्जी मार्कशीट बनाकर एमबीबीएस में प्रवेश पाने वाले एक चिकित्सक को लगभग 44 साल बाद जेल की हवा खानी पड़ेगी। न्यायालय ने इसे समाज के खिलाफ अपराध बताते हुए चिकित्सक को तीन साल की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अहमदाबाद के पालडी इलाके में रहने वाले उत्पल पटेल को 1980 में 12वीं की परीक्षा में 800 में से 398 अंक मिले थे। उसने उत्तर पुस्तिका की फिर से जांच कराई, जिसमें परिणाम वही रहा। लेकिन, उसने 800 में से 547 अंक प्राप्त करने की फर्जी मार्कशीट तैयार कराकर अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कालेज में प्रवेश ले लिया। एक शिकायत के बाद मेडिकल कालेज ने जब गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा तो बताया गया कि उत्पल ने 12वीं की उत्तर पुस्तिका की पुर्नजांच के लिए आवेदन किया था पर परिणाम में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद कालेज ने 1991 में शाहीबाग थाने में चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। इसी मामले में उत्पल को सजा सुनाई गई है।

जागरण विशेष

विद्यार्थियों को तनावमुक्त रखने के लिए अनूठी सामाजिक-सांस्कृतिक पहल

एनआइटी कुरुक्षेत्र में बने विद्यार्थियों के 12 क्लब, योग, देश की विरासत से भी हो रहा परिचय

विनोद चौधरी ● कुरुक्षेत्र

विद्यार्थियों के बीच पढ़ाई और सफलता प्राप्त करने के तनाव-दबाव की खबरें प्रायः सामने आती रहती हैं। कई अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं। शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी न केवल पढ़ाई करें बल्कि तनावमुक्त वातावरण में रहते हुए उल्लास और ऊर्जा से देश की विरासत को जानें, समझें और सहेजें, इसके लिए एनआइटी कुरुक्षेत्र ने बड़ी पहल की है। राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान की पहल से पढ़ाई के बाद के खाली समय में विद्यार्थी योग, ध्यान और सांस्कृतिक-सामाजिक गतिविधियों में जुटे रहते हैं। तनाव दूर करने के साथ इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे से दूर रखना है।

श्रीमद्भगवद्गीता से संबंधित कोर्स शुरू, परिणाम में जुड़े अंक

विद्यार्थियों को ध्यान सकारात्मक बातों की तरफ करने के लिए संस्थान में करीब नौ ऐसे आडिट कोर्स शुरू किए गए, जिनमें से कोई भी दो कोर्स सभी के लिए अनिवार्य हैं। हर वर्ष इनके क्रेडिट अंक भी परीक्षा परिणाम में जोड़े जाने लगे। इससे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इन गतिविधियों से जुड़ने लगे। इनमें योग, खेल, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, सांस्कृतिक और तकनीकी गतिविधियां, जीवन के मूल्य और भारतीय ज्ञान प्रणाली और श्रीमद्भगवद्गीता से संबंधित कोर्स शुरू किए गए हैं।

कार्यक्रम में हिस्सा लेते विद्यार्थी व शिक्षक

एनआइटी में पिछले वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते निदेशक प्रो. बीवी रमना रेड्डी ● एनआइटी कुरुक्षेत्र

संस्थान की तरफ से बजट भी: इस पहल के लिए एनआइटी में विद्यार्थियों के 12 क्लब बनाए गए हैं। ये क्लब सभी धर्मों के त्योहार मनाते हैं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को त्योहारों पर होने वाले कार्यक्रमों से जोड़ते हैं। इस प्रकार के आयोजन के लिए एनआइटी प्रशासन की ओर से 25 हजार रुपये का बजट भी आवंटित किया जाता है। इस पहल से संस्थान के विभिन्न विभागाध्यक्ष भी जुड़ रहे हैं। एनआइटी का प्रयास विद्यार्थियों के दिल-दिमाग को सकारात्मक रखना तथा मेल-जोल बढ़ाना है, ताकि वे संस्थान में अकेलापन न लगे।

ऐसे हुई शुरुआत: एनआइटी में लगभग डेढ़ वर्ष पहले तनाव के कारण एक छात्र के साथ अनहोनी हो गई थी। जब निदेशक डा. बीवी रमना रेड्डी ने इस घटना के बारे में सभी विद्यार्थियों से बात की तो पता चला कि छात्र पिछले कई दिनों से गुमसुम रहता था और किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी घटना के बाद निदेशक ने इस तरह की समस्याओं का समाधान का निर्णय लिया। प्राचीन काल में आपसी भाईचारा अधिक होने के चलते युवाओं के सामने इस तरह की समस्या न आने को आधार बनाकर उन्होंने एनआइटी में सद्भाव और मेलजोल के लिए विशेष प्रयास की योजना तैयार की। इसके लिए सभी छात्र क्लबों के प्रतिनिधियों को सक्रिय किया। अब विद्यार्थी ज्यादातर समय मिलजुल कर रहते हैं और प्रयास करते हैं कि कोई विद्यार्थी ज्यादा समय अकेला न रहे, खास तौर पर गुमसुम न रहे।

"कई विद्यार्थियों के तनाव में रहने की जानकारी मिली तो शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ मिलकर यह पहल की है। विद्यार्थियों के लिए ऐसी सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं कि वे अधिक से अधिक समय एक-दूसरे के साथ रहें।

डा. बीवी रमना रेड्डी, निदेशक, एनआइटी कुरुक्षेत्र

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

अब बंगाल विस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : शिक्षा विभाग, नगर पालिकाओं के बाद अब बंगाल विधानसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। विधानसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये ठगने का आरोप है। धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने ईडी कार्यालय पहुंचकर जांच के लिए लिखित शिकायत की है।

एक व्यक्ति ने कहा, प्रदीप बिस्वास नामक व्यक्ति ने विधानसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर मुझसे छह लाख रुपये लिए। मुझे एक आइ कार्ड और नियुक्ति पत्र भी दिया। बाद में पता चला कि कोई भर्ती ही नहीं है। यह सब जाली है। इस फर्जीवाड़े के पीछे मीता मुखर्जी नामक महिला का नाम सामने आ रहा है। ठगे गए लोगों का आरोप है कि मीता ने पूरे राज्य में जाल फैला रखा था। उसने नौकरी दिलाने के नाम पर आठ करोड़ रुपये ठगे है।

****

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 1 फरवरी, 2024

दैनिक जागरण
संतुलन साधना भी एक कला है

पूजा के अधिकार की वापसी

वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति देने का निर्णय देकर केवल न्याय ही प्रदान नहीं किया, बल्कि उस गलती को सुधारने का काम भी किया, जो 1993 में मुलायम सिंह सरकार ने की थी। मुलायम सिंह सरकार ने इस तहखाने में पूजा-पाठ पर प्रतिबंध पूजा स्थल अधिनियम के अस्तित्व में आने के बावजूद लगा दिया था। यह प्रतिबंध मनमाना और अवैध ही नहीं था, बल्कि एक तरह से 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का शर्मनाक उल्लंघन भी था। यह अधिनियम यह कहता है कि किसी धार्मिक स्थल का चरित्र बदला नहीं जाएगा, लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने व्यासजी के तहखाने में पूजा पर प्रतिबंध लगाकर ठीक यही काम किया। विडंबना यह है कि हिंदू श्रद्धालुओं के पूजा के अधिकार का दमन करने वाले इस प्रतिबंध के हटने में 31 वर्ष लग गए। वाराणसी की जिला अदालत ने सात दिन के अंदर पूजा की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। हैरानी नहीं कि इसके पहले ही उसके फैसले को उच्चतर न्यायालयों में चुनौती दी जाए। जो भी हो, किसी को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि मंदिर पक्ष केवल इससे संतुष्ट होने वाला है कि उसे ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा का वह अधिकार मिल गया, जो करीब तीन दशक पहले उससे छीन लिया गया था। किसी को ऐसी अपेक्षा इसलिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआइ की ओर से ज्ञानवापी परिसर में किए गए सर्वे से यह प्रमाणित हुआ कि यहां मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की गई थी।

वैसे तो यह पहले से ही स्पष्ट था कि तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर खड़ी की गई इमारत है, लेकिन एएसआइ के सर्वे ने इसके अकाट्य प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिए। इन्हें किसी के लिए नकारना संभव नहीं है, लेकिन यह देखना दुखद है कि मस्जिद पक्ष और कई मजहबी एवं सियासी मुस्लिम नेता एएसआइ की सर्वे रपट को खारिज करने में जुटे हैं। यह दीवार पर लिखी इबारत को देखने-पढ़ने से जानबूझकर इन्कार करने के अलावा और कुछ नहीं। मस्जिद पक्ष वैसी ही हठधर्मिता दिखा रहा है, जैसी उसने अयोध्या मामले में दिखाई थी। जब यह एक सर्वमान्य और अकाट्य साक्ष्यों से प्रमाणित तथ्य है कि मुगल शासकों समेत अन्य मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को ध्वस्त कर वहां मस्जिदें खड़ी कीं, तब न्याय और नैतिकता का तकाजा यही कहता है कि कम से कम उन पर से तो दावा छोड़ ही दिया जाए, जो हिंदुओं के लिए बहुत अधिक मायने रखते हैं। मस्जिद पक्ष एक ओर तो यह कहता है कि आज के मुसलमानों का औरंगजेब से कोई लेना-देना नहीं, लेकिन इसके साथ ही वह उसके दुष्कृत्यों का बचाव भी करता है। एक त्रासदी यह भी है कि मुस्लिम नेता इस हकीकत से भी मुंह मोड़ रहे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे।

तस्करों पर नकेल

पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस की ओर से सीमावर्ती जिलों में लगातार अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। बठिंडा एवं अमृतसर में जिस तरह से तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और हेरोइन सहित ड्रग मनी बरामद की गई है उससे इनके नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्कर एवं गैंगस्टर चुनौती बनते जा रहे हैं। इनका आतंकियों के साथ गठजोड़ होना ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कई तस्करों के कनाडा, पाकिस्तान एवं अमेरिका में छिपे गैंगस्टरों एवं आतंकियों से संबंध हैं। उनके इशारे पर पंजाब में गतिविधियों को संचालित किया जाता है। हेरोइन ही नहीं, हथियारों की तस्करी भी सुरक्षा बलों के लिए समस्या बनती जा रही है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एसआइटी की जांच में भी गैंगस्टरों, तस्करों एवं आतंकियों के गठजोड़ की बात सामने आ चुकी है। चिंताजनक यह भी है कि जेल में बंद होने के बावजूद गैंगस्टर एवं तस्कर एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं। वहीं से फोन पर रंगदारी मांगते हैं और लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। इस गठजोड़ को खत्म करने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो वह तत्काल किया जाना चाहिए। जेलों में मोबाइल फोन का प्रयोग हर हाल में पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए अत्याधुनिक जैमर लगाने के कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट सरकार को हिदायत भी दे चुका है। पुलिस को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना सूचना तंत्र मजबूत करना होगा जिससे संदिग्ध लोगों की समय रहते जानकारी मिल सके।

पुलिस को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना सूचना तंत्र और ज्यादा मजबूत करना होगा जिससे संदिग्ध लोगों की समय रहते जानकारी मिल सके

गणतांत्रिक मूल्यों से भटकता भारत

कपिल सिब्बल

एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री की सहभागिता से हमारे गणतंत्र के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है

पिछले कुछ समय का घटनाक्रम यही दर्शाता है कि एक राज्य व्यवस्था के रूप में हम गणतंत्र के अपने मूलभूत संवैधानिक सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं। हमारे संविधान में दो प्रकार के विचारों का समावेश है। एक है समानता का विचार, जो हमारे लोकतंत्र के अंतर्निहित पंथनिरपेक्ष स्वरूप में प्रतिबिंबित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने भारत की विविधता को देखते हुए ऐसी व्यवस्था का चयन किया, जहां सभी पंथों को बराबर सम्मान मिले। जहां पाकिस्तान ने इस्लाम को राज्य के पंथ के रूप में चुना तो भारत ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना। दूसरा विचार उस मौलिक अधिकार से जुड़ा है, जो प्रत्येक नागरिक को उपासना पद्धति एवं पंथ के प्रचार-प्रसार एवं उसके अभ्यास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अधिकार व्यक्तियों के साथ ही धार्मिक संप्रदायों को समान रूप से उपलब्ध है। यदि लोक व्यवस्था को कोई खतरा न पहुंचे तो यह अधिकार निर्बाध रूप से प्राप्त होता है। यानी अगर लोग किसी अन्य की शांति में खलल डाले बिना अपनी धार्मिक एवं पंथिक परंपराओं को लेकर आग्रही रहते हैं तो कोई समस्या नहीं। हालांकि राज्य किसी धार्मिक पद्धति से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य सेक्युलर गतिविधि को प्रतिबंधित या उसके विनियमन के लिए कानून बना सकता है। राज्य सामाजिक कल्याण की पहल करने के साथ ही उन्हें हिंदू संस्थाओं पर अधिरोपित कर सकता है कि वे सभी जाति एवं वर्गों के लिए उनकी पहुंच सुनिश्चित करें। चूंकि कुछ जाति एवं वर्गों को हिंदू धार्मिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति को लेकर पारंपरिक बाधाएं रही हैं तो इस कदम के पीछे अंतर्निहित भाव उन अवरोधों को दूर करने से जुड़ा है।

देश में यही संवैधानिक व्यवस्था है जहां नागरिकों एवं धार्मिक समुदाय को अंतःकरण और उपासना पद्धति के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, किंतु राज्य को ऐसी कोई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वतंत्रता नहीं। यह हमारी राज्य व्यवस्था के पंथनिरपेक्ष चरित्र और अंतर्निहित संवैधानिक मूलमंत्र के अनुरूप ही है, जो हमारे गणतंत्र की आधारशिला है। पंथ के प्रचार-प्रसार या किसी अन्य पहलू में राज्य की कोई भूमिका अपेक्षित नहीं। जिस क्षण राज्य ने इसमें सक्रियता दिखाई तो यह संवैधानिक मूल्यों से विचलन होगा। हालिया घटनाक्रम इसी ओर संकेत करता है कि राज्य धार्मिक भावनाओं के साथ गहराई से जुड़ गया है, जो बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भुनाते हुए एक बहुसंख्यकवादी संस्कृति को विकसित करने में लगा है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यह प्रत्यक्ष दिखा। इस दौरान प्रत्येक सरकारी ढांचे को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने के निर्देश मिले। इसने हमारी संवैधानिक संस्कृति को क्षति पहुंचाई।

प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सहभागिता स्वयं राजनीति और पंथ के बीच अंतर को मिटा देती है। इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का ही कार्यक्रम में यजमान बनने से हमारी राजनीति का चरित्र बदल गया। यह एक प्रकार से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ही प्रयास है, जहां राजनीति और पंथ ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक हिंदू के रूप में हम भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाते हैं, लेकिन हम इसकी कतई सराहना नहीं कर सकते कि राज्य और उसके प्रतिनिधि उससे जुड़े समारोह का नेतृत्व करें। सत्तारूढ़ भाजपा ने न केवल सरकारी संस्थानों और राज्य से जुड़े अन्य निकायों को इस आयोजन का उत्सव मनाने के लिए निर्देशित किया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी इस आयोजन के माध्यम से देशभक्ति प्रदर्शन के लिए लामबंद एवं प्रोत्साहित किया। बाजार भी इस लहर से अछूते नहीं रहे और भगवा रंग में रंग गए। किसी भी बाजार समिति ने आयोजन के विरोध का साहस नहीं किया, क्योंकि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। टीवी चैनलों पर कोई और समाचार ही नहीं दिखाया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के प्रत्येक कदम को टेलीविजन पर इस प्रकार दिखाया जा रहा था मानों वह भगवान राम को पुनः वापस ले आए हों और यह राष्ट्र को उनकी अनुपम भेंट है। भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से अधिक महिमामंडन इसका हुआ कि मोदी जी ने उसके लिए कितना संघर्ष किया। जबकि सच्चाई यही है कि उन्होंने इसके लिए लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अदालत ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और नहीं, बल्कि टाइटल सूट पर फैसला सुनाया कि जिस स्थान को लेकर विवाद है, वह रामलला विराजमान का है। मुझे हैरानी इस बात की है कि इसमें प्रधानमंत्री का क्या योगदान रहा। असल में याचिकाकर्ताओं के सफल प्रयासों को दुर्भाग्यवश मोदी जी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए हड़प लिया।

अवधेश राजपूत

एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री की सहभागिता से हमारे गणतंत्र के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इससे एक समावेशी भारत बनाने के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का स्वप्न ध्वस्त हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री के शामिल होने की गांधी जी कभी सराहना नहीं करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक किस्सा बहुत विख्यात है। उन्हें सिंगापुर के चेट्टियार मंदिर में संबोधन के लिए कहा गया। इसके एवज में मंदिर चंदा देने को तैयार था। पहले तो नेताजी ने इन्कार कर दिया कि आजाद हिंद फौज का सैनिक होने के नाते वह इसमें नहीं आ सकते। आखिर में उन्होंने चंदा स्वीकार किया और इसी शर्त पर भाषण दिया कि उनके साथ गैर-हिंदू भी आएंगे, जबकि मंदिर परंपरा के अनुसार गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। मंदिर प्रबंधन सहमत हो गया और नेताजी के साथ आए उनके सहयोगी हबीब-उर-रहमान, एमजेड कियानी और एक ईसाई अय्यर का भी भव्य स्वागत किया गया। जो मंदिर गैर-हिंदुओं के लिए बंद था, उसने उस परंपरा का परित्याग कर उदारतापूर्वक अपने द्वार खोल दिए। डा. भीमराव आंबेडकर भी उपासना पद्धति को राजनीति का नहीं, आध्यात्मिक मुक्ति का साधन मानते थे। गत 22 जनवरी को भारतीय राज्य गांधी, बोस और आंबेडकर के विचारों से भटक गया। यह हमारे गणतंत्र के लिए दुखद दिन रहा।

(लेखक राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं)

response@jagran.com

तीसरी बड़ी आर्थिकी का आसान लक्ष्य

डा. जयंतीलाल भंडारी

वैश्विक स्तर पर गिरावट के बीच भी भारत सर्वाधिक एफडीआइ प्राप्त करने वाले देशों की सूची में बना हुआ है

अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी विस्तृत रिपोर्ट 'द इंडियन इकोनमी-ए रिव्यू' में कहा गया है कि अगले तीन साल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था पांच (ट्रिलियन) लाख करोड़ डालर की हो जाएगी। फिर भारत आर्थिक आकार के लिहाज से अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड महामारी और उसके ठीक बाद भू-राजनीतिक उथल-पुथल से जहां दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दो प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया को चकित करते हुए आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में भी सात प्रतिशत की विकास दर हासिल कर सकती है। रिपोर्ट की मानें तो पिछले एक दशक में सरकार के साहसिक आर्थिक निर्णयों ने देश की आर्थिक बुनियाद को मजबूत बनाया है। लिहाजा कृषि से लेकर मैन्यूफैक्चरिंग और डिजिटल सेवा की बदौलत सेवा क्षेत्र में मजबूती आई है। पिछले दिनों चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत की बढ़ती हुई इस आर्थिक और रणनीतिक ताकत की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत तेज आर्थिक विकास के साथ एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और वैश्विक विकास के इंजन के तौर पर स्थापित हुआ है। भारत की ओर वैश्विक कंपनियों के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं।

दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसियां भी सहमत हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर तेजी से बढ़ रहा है। इस समय भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर हैं। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष अहमियत मिल रही है। अमेरिका और रूस, दोनों महाशक्तियों के साथ भारत की मित्रता है। तेजी से बढ़ते बाजार के कारण दुनिया के अधिकांश देशों में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की ललक दिख रही है। प्रवासी भारतीयों द्वारा वर्ष 2023 में 125 अरब डालर से अधिक धन भारत भेजा गया। दुनिया में चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मकता के मद्देनजर भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरकर सामने आया है। इसके साथ-साथ दुनिया में मजबूत लोकतंत्र और स्थिर सरकार के रूप में भारत की पहचान बनना, भारत के शेयर बाजार का दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ना, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, देश में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, बड़े पैमाने पर पूंजीगत खर्च, गैर जरूरी आयात में कटौती और अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता टिकाऊ विकास की बुनियाद बन सकती है।

वैश्विक विकास का इंजन बनता भारत। प्रतीकात्मक

भारत द्वारा जी-20 की सफल अध्यक्षता से भी नए आर्थिक लाभ की संभावनाएं बनी हैं, जिससे भारत से निर्यात, भारत में विदेशी निवेश, भारत में विदेशी पर्यटन और भारत के डिजिटल विकास का नया क्षितिज सामने दिखाई देगा। जी-20 से दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के मद्देनजर भारत की अहमियत बढ़ेगी। प्राकृतिक संपदा संपन्न अफ्रीकी संघ को जी-20 में शामिल कराकर भारत ने अफ्रीकी देशों से नए आर्थिक लाभ की उम्मीदों को बढ़ाया है। इससे अब भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआइ भी तेजी से बढ़ेगा। ज्ञातव्य है कि वैश्विक स्तर पर गिरावट के रुझान के बीच भारत दुनिया के सर्वाधिक एफडीआइ प्राप्त करने वाले 20 देशों की सूची में आठवें पायदान पर रहा। इस वर्ष भारतीय शेयर बाजार भी तेजी से बढ़ता हुए दिखाई दे रहा है। गत दिनों सेंसेक्स 73,000 तक की ऊंचाई पर पहुंच गया था। अनुमान है कि यह आम चुनाव के पहले 80,000 की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। चुनाव के बाद 2024 के अंत तक 1,00,000 के स्तर पर पहुंच सकता है। इस साल मैन्यूफैक्चरिंग, विनिर्माण, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, होटल, ट्रांसपोर्ट, आटोमोबाइल, फार्मा, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल सेक्टर, ई-कामर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, आइटी, टूरिज्म, रिटेल ट्रेड, हास्पिटैलिटी आदि सेक्टर भी बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। आज भारत विश्व का नया मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है।

यद्यपि दुनियाभर में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली आकर्षक अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में रेखांकित हो रहा है, लेकिन फिर भी इसे कई आर्थिक चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा। देश के सामने डालर की तुलना में रुपये के गिरते हुए मूल्य की चुनौती है। भारत को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उस चेतावनी पर भी ध्यान देना होगा, जिसमें कहा गया है कि भारत में केंद्र और राज्यों का सरकारी कर्ज जीडीपी के 100 प्रतिशत के पार पहुंच सकता है। भारत के रणनीतिकारों को प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर रक्षात्मक रणनीति बनाने के लिए भी तैयार रहना होगा। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ाने होंगे। हमें 2030 तक सात (ट्रिलियन) लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सालाना सात प्रतिशत विकास दर की जरूरत होगी। दुनिया में जो देश गहन संकट से बाहर निकल विकसित और शक्तिशाली बने हैं, उनकी सफलता में अन्य चीजों के साथ उनके राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी अहम रहा है। ऐसे में भारत को भी अब विकसित देश बनने के लिए अपने मूल्यों, संस्कृतियों और अपने नायकों की वीरता की सराहना के साथ विविधता के बीच एकजुटता बढ़ानी होगी और प्रवासी भारतीयों में भी जुड़ाव की भावना पैदा करनी होगी। इससे देश विकास के ऊंचे लक्ष्य और आम आदमी की खुशहाली के साथ टिकाऊ विकास तथा वैश्विक विकास का केंद्र बनने के अवसर का लाभ उठाते हुए दिखाई दे सकेगा।

(लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मदद की भावना

कठिन समय में मददगार व्यक्ति भगवान की तरह लगता है। आभार प्रकट करते हुए बार-बार यही वाक्य निकलता है कि आपने मदद नहीं की होती तो शायद मैं इस कठिनाई को झेल न पाता। वक्त बीतता है। कुछ समय बाद मदद करने वाले का नाम तक स्मृतियों से नहीं रह जाता, तब मदद का स्वरूप कहां तक याद रहेगा? इतनी कमजोर होती है इंसान की स्मृति। यदि मदद का मामला तत्काल का हो और मदद करने वाला सामने पड़ जाए तब ऐसा भी लगने लगता है कि कहीं पूर्व में की गई मदद के बदले वह शख्स मदद मांगने तो नहीं आ गया? यह तो दूर-दराज के किसी व्यक्ति के प्रति किए जाने वाले व्यवहार का मामला है। बहुत सारी ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब परिवार में भी इस तरह की बातें की जाने लगती हैं।

मदद के विपरीत किसी द्वारा किए गए छल और धोखे की बात हमेशा ताजा रहती है और भूलती नहीं। यहां तक कि तारीख, महीना और साल भी वर्षों वर्ष बाद तक स्मृतियों में बने रहते हैं। कभी-कभी तो बुरी बातें स्मृतियों में ऐसी हलचल उत्पन्न करने लगती हैं कि मानसिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल होने लगता है और यही असंतुलन अप्रिय कदम उठाने को बाध्य कर देता है।

यह सोचने की बात है कि हम क्यों किसी की मदद को पल में भूल जाते हैं और किसी के धोखे या अप्रिय बातों को भूल नहीं पाते हैं? कोई हमारी मदद करे तो कोशिश यही होनी चाहिए कि खुद भी मदद के रास्ते पर चलें। ऐसा न हो कि दूसरों की मदद करने के हमारे रास्ते संकरे हो जाएं। परिवार से लेकर समाज तक में कभी-कभी ऐसा वक्त आ जाता है, जब हमें मदद की जरूरत पड़ती है। याद रखें कि मदद विकट परिस्थितियों की दवा होती है। अतः मदद की हमारी भावना मजबूत रहनी चाहिए। मदद करने वाले के लिए कोई न कोई मददगार उसके मुश्किल वक्त पर खड़ा हो ही जाता है।

सलिल पांडेय

भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का सपना

रंजना मिश्रा

केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 30 शहरों की सूची तैयार की है

भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के लोग रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों को आर्थिक तंगी के कारण भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार ने इन लोगों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना बनाई है। इसके तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता से लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। रोजगार के अवसर प्रदान करके लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लोगों को बुढ़ापे, बीमारी और अन्य आपात स्थितियों में आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 30 शहरों की सूची तैयार की है। इनको तीन आधारों पर चुना गया है। एक, जिन शहरों में धार्मिक महत्व के स्थान हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। दूसरे जिन शहरों में ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, जैसे कि किले, महल और संग्रहालय। तीसरे जिन शहरों में पर्यटकों की संख्या अधिक होती है। दरअसल इन शहरों में भिक्षावृत्ति की समस्या अधिक होती है।

भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा जैसे, भिक्षावृत्ति के मूल कारणों को समझना और उन पर प्रभावी तरीके से काम करना, भिक्षावृत्ति के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना और लोगों को भिक्षा देना बंद करने के लिए प्रेरित करना। गरीबी भिक्षावृत्ति का सबसे प्रमुख कारण है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके पास रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। ऐसे लोग भिक्षावृत्ति को एकमात्र आय का स्रोत बना लेते हैं। जो लोग शिक्षित नहीं होते, उनके पास रोजगार के अवसर कम होते हैं। ऐसे लोगों को भी भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, वे समाज में अपना स्थान नहीं बना पाते हैं और भिक्षावृत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। जो बच्चे शोषण का शिकार होते हैं, वे भी आगे चलकर भिक्षावृत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। इसके अलावा एक संगठित गिरोह भी है जो गरीबों से जबरन भिक्षावृत्ति कराता है।

भारत में भिखारियों की कुल संख्या चार लाख 13 हजार 670 है, जिनमें पुरुषों की संख्या दो लाख 21 हजार 673 तथा महिलाओं की संख्या एक लाख 91 हजार 997 है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। बाल भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों की तस्करी के बढ़ते मामले भी बहुत चिंताजनक हैं। भिक्षावृत्ति एक जटिल समस्या है, जिसे हल करने के लिए सरकार को एक समग्र योजना बनानी होगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

कांग्रेस की कठिन राह

'स्याह दिखने लगा कांग्रेस का भविष्य' शीर्षक से लिखे आलेख में राजकुमार सिंह ने सही कहा है कि नीतीश कुमार ने ही पिछले साल जून माह में सभी गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों को इस बात पर सहमत कराया था कि बिना कांग्रेस को साथ में लिए कोई भी विपक्षी मोर्चा भाजपा का मुकाबला करने में नाकाम होगा, तब जाकर सभी आइएनडीआइए में कांग्रेस को स्वीकारने को तैयार हुए थे। राजनीति में ऐसी कोई कोशिश बिना किसी कारण नहीं हो सकती है, मगर जब नीतीश कुमार को आइएनडीआइए का संयोजक बनाने की बारी आई तो कांग्रेस नेतृत्व बहानेबाजी करने लगा। नीतीश कुमार का पत्ता काटने के लिए कभी अरविंद केजरीवाल तो कभी ममता बनर्जी का नाम भुनाने लगी। उसकी असली मंशा तो यह थी कि राहुल गांधी के हाथ से नेतृत्व नहीं जाना चाहिए। अब राहुल गांधी खुश होकर कह रहे हैं कि मुझे नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। जबकि उनके आइएनडीआइए से अलग होने से कांग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नुकसान होना तय है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में नीतीश कुमार का अच्छा-खासा प्रभाव है। शायद अब इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस क्या कर लेगी? मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य देखकर यह स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस बिना अपनी मजबूती के ज्यादा उम्मीद न पाले। पहले वह खुद मजबूत होगी तभी सहयोगी दल भी महत्व देने को तैयार होंगे। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जब खुद दुविधा में फंसा नजर आ रहा है, तब वह दूसरों से क्या ही उम्मीद लगाए। ऐसे में उसके लिए आगे की तस्वीर निराशाजनक तो है ही।

मुकेश कुमार मनन, पटना

विकास का मार्ग दिखाए बजट

'आगे की राह दिखाए अंतरिम बजट' शीर्षक आलेख के तहत तरुण गुप्त ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट में ऐसे फैसले आने की उम्मीद जताई है जिससे लोगों का भला तो हो ही देश के विकास की राह भी दिखाए। बजट तभी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, जब इसमें मुफ्त की योजनाओं की जगह देश के उद्योग-धंधों, कारोबार को और मजबूत बनाने वाले उपाय हों। बजट ऐसा होना चाहिए, जिसमें आमजन की रसोई, स्वास्थ्य, शिक्षा, कमाई और बुढ़ापे का भी पूरा ख्याल रखा जाए। बजट से आयकरदाताओं को आयकर सैलाब में छूट मिलने की आस होती है। सरकार फ्री की आमदनी देने के बजाय देश के हर हाथ को रोजगार मुहैया करवाने, मेहनत करने वालों की आमदनी बढ़ाने, महंगाई कम करने की तरफ ध्यान दे। बजट में कृषि, मत्स्य पालन और लगभग हर गांव में छोटी-बड़ी डेरी खोलने के लिए लोगों को विशेष पैकेज जारी किए जाएं तो देश हित में होगा। अगर खेतीबाड़ी अच्छी होती है, ज्यादा से ज्यादा मत्स्य पालन केंद्र खुलते हैं और डेरियां खोली जाती हैं तो इससे देश में रोजगार बढ़ेगा। जबकि मुफ्तखोरी की योजनाएं दीमक का काम करती हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

देशहित में एक साथ चुनाव

''संभव है एक साथ चुनाव'' शीर्षक से प्रकाशित आलेख पढ़ा। लेखक का यह सुझाव देशहित में है। सबको मालूम है कि देश में होनेवाले चुनावों पर कितना धन खर्च होता है। देश में जनहित के कई कल्याणकारी काम धन की कमी के कारण पूरे नहीं हो पाते हैं। संसद में कानून पारित करके एक साथ चुनाव करने की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले वर्ष एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अगुआई में कमेटी का गठन भी किया गया था। आशा है जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में तो लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। अब इसके बाद भविष्य में जो भी चुनाव होने वाले हों उनको हर हाल में टला जाना चाहिए, जब तक इसका फैसला न हो जाए कि किस साल से देश में एक साथ चुनाव होने वाले हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इसका होना जरूरी है। ऐसा होने से विधायकों एवं सांसदों का भी फायदा है।

अशोक कुमार दुबे, पटना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, [illegible] ... डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) [illegible]
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHI/2017/74721 [illegible]

25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रविधान है सभी निजी स्कूलों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के छात्रों हेतु, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत।

सरकारी स्कूलों की दशा

जिम्मेदार पहल से सुधरेगी व्यवस्था

निजी और सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बीच की खाई चौड़ी हो रही है। सच यह भी है कि अधिकांश अधिकारी व जनप्रतिनिधि अपने बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में नहीं करवाना चाहते। यदि ऐसा किया जाना अनिवार्य हो तो सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार हो सकता है। हाल ही में एक जिलाधिकारी ने अपने बच्चे का नामांकन आंगनबाड़ी में करवाया है। अन्य अधिकारियों को भी इससे सीख लेते हुए इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए

डा. अमरजीत कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, माधव विवि, सिरोही, राजस्थान

अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी यदि सरकारी स्कूलों में पढ़ें, तो स्वाभाविक रूप से व्यवस्थागत सुधार सुनिश्चित हो सकता है। फाइल

शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। इस पर सभी लोगों के विचार भिन्न भिन्न हैं। इन्हीं में से एक सुझाव ऐसा भी है जिसकी चर्चा कई अवसरों पर हुई, लेकिन इस पर अमल किया जाना बाकी है। मसला है सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नामांकन अनिवार्य करना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस की जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने अपने दो साल के बच्चे का नामांकन आंगनबाड़ी में कराया। वहीं बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की प्रशंसा में एक्स (पहले ट्विटर) पर किए गए एक पोस्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बड़े अधिकारियों के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में अनिवार्य रूप से पढ़वाने की बात कही थी। ये दोनों समाचार स्वयं में महत्वपूर्ण हैं।

वस्तुतः यह कोई पहली बार नहीं है, जब सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नामांकन अनिवार्य करने की बात कही गई है। पूर्व में भी यह सुझाव सुर्खियों में रह चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित रिट याचिका में प्राथमिक विद्यालयों की बदहाली पर चिंता जताते हुए राज्य व मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के बच्चों को इन स्कूलों में भेजें। न्यायालय का यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के प्रति सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता जाहिर होती है। वहीं अपने बच्चों के प्रति इनका रवैया निजी विद्यालयों में नामांकन को प्राथमिकता देने का होता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी स्कूलों में प्रभावी शिक्षा, आधारभूत संरचना एवं उचित प्रबंधन व निगरानी के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं।

नीति निर्माताओं का नजरिया : किसी राज्य के नीति निर्माण में विधानसभा की विशेष महत्ता है। लेकिन सवाल यहां यह भी है कि विधानसभा के कितने सदस्य अपने बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में करवाते हैं। वस्तुतः मसला यह है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर मुद्दा तो बनते देखा गया है, लेकिन शिक्षा की प्रभाविकता को लेकर अभी भी बहुत किया जाना शेष है। ऐसे में नेता जब मंच से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों में नामांकन की वकालत करते हैं तो विधायकों एवं सांसदों को भी अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना होगा।

देश की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आया, परंतु मिड डे मील जैसी योजनाएं सरकारी विद्यालयों के बच्चों में कुपोषण को दूर करने का एक माध्यम कब और कैसे बन गई, इसे भी समझने की आवश्यकता है। जबकि मिड डे मील में कुप्रबंधन और घोटाला एवं उसकी निगरानी ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन इसी बीच सरकारी स्कूलों में प्रभावी शिक्षा कहीं पीछे छूट गई। मसलन सरकारी और निजी विद्यालयों के विभेदकारी व्यवस्था को भी समझने की आवश्यकता है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा और उसकी बदहाली पर अक्सर विमर्श तो होता है, परंतु उसके प्रति आज भी लोगों का नजरिया बदलता नहीं दिख रहा है।

आधारभूत संरचना : उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण की दौड़ में शिक्षा भी इससे अछूती कैसे रह सकती थी। ऐसे में सरकारी और निजी स्कूलों के मध्य सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना में खाई दिख जाती है। हो भी क्यों न, जहां सरकारी स्कूलों का उद्देश्य लाभ अर्जन का नहीं है, वहीं निजी स्कूलों को आर्थिक लाभ ही सर्वोपरि प्रतीत होता है। लेकिन क्या सरकारी और निजी स्कूलों के मध्य शिक्षा की गुणवत्ता की खाई को समाप्त किया जा सकता है, तो जवाब है हां। इसके पीछे पक्ष है कि निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक आज भी सरकारी स्कूलों में आना चाहते हैं, इसके पीछे जाब सिक्योरिटी और मिलने वाला वेतन कहीं न कहीं मुख्य कारण है, लेकिन सरकारी स्कूलों के अधिकांश शिक्षकों द्वारा पढ़ाई के प्रति बरती जाने वाली अनियमितता भी लोगों के बीच आम बात है। ऐसे में सरकारी सेवा में कार्यरत तमाम लोगों एवं जनप्रतिनिधियों के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित होने पर ऐसी प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगा सकता है। सामान्य बात है कि एक मध्यम और निम्न आय वाले परिवार भी अपने बच्चों की शिक्षा पर अपनी आय का 25 प्रतिशत तक खर्च करने को तैयार है। ऐसे में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के बच्चे सरकारी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करने लगें तो एक अभिभावक के नाते भी सभी लोग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे रहेंगे।

शिक्षकों से सरकार की अपेक्षा : कई बार यह भी देखा गया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर अनेक प्रकार के अव्यावहारिक आदेश भी जारी होते रहते हैं। इसी प्रकार के एक मामले में बिहार में एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपने क्षेत्र में आने वाले सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सभी कक्षाओं से कुर्सियां हटाने का निर्देश दिया था। लिहाजा ऐसे तरीकों से शिक्षा में सुधार का सोच रखना संवेदनहीनता को दर्शाता है। क्या शिक्षकों को चुनाव, जनगणना, पल्स पोलियो कार्यक्रम, मिड डे मील, बाढ़ एवं सूखा राहत योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी आदि कार्यों में लगाया जाना शिक्षण कार्यों को प्रभावित नहीं करता है इस प्रकार के मुद्दों पर भी कई बार लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई, लेकिन सवाल आज भी वही बना है।

महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सरकार उपरोक्त कार्यों के सही क्रियान्वयन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं ला सकती है। ऐसे में समझना होगा कि सरकारी विद्यालयों की प्रभाविकता इसके उचित और प्रभावी कार्यप्रणाली से हीं हो सकता है जिसमें अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों आदि के बच्चे सरकारी शिक्षण संस्थान में पढ़ें, तो लोगों का भरोसा तो बढ़ेगा ही, साथ ही सरकारी विद्यालयों से जुड़ी समस्याओं को समझने का अवसर भी मिलेगा।

अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकारी आवास, गाड़ी या अन्य सुविधाओं का व्यापक उपयोग किया जाता है, परंतु उनके परिवार के सदस्य सरकारी स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं जाते, जबकि इसके उचित प्रबंधन और संचालन का जिम्मा इन पर ही होता है। ऐसे में आम लोग भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था पर ही भरोसा दिखाते हैं। यह हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्हीं सरकारी संस्थानों में आई भर्तियों का हिस्सा बनने की होड़ में सभी लोग शामिल हैं, जबकि सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सूची लंबी है। महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के सरकारी संस्थाओं के उपयोग की अनिवार्यता पर नीति बनाना और उसे लागू करने का काम उन्हीं पर है, जो संस्थानों को प्रभावी नहीं बना सके हैं और इसे दोयम दर्जे का मानते हैं। इस सूची में सरकारी विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं जिनके परिवार के सदस्यों को निजी संस्थानों पर ज्यादा भरोसा है। ऐसे में सरकारी संस्थाओं के उपयोग की अनिवार्यता के साथ इनके प्रोत्साहन संबंधी नीतियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षा का अधिकार और समान अवसर

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के छात्रों के लिए अपनी 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रविधान किया गया है। जबकि अनेक अभिभावकों की ओर से इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की सीटें आवंटित किए जाने के बावजूद कुछ निजी विद्यालयों द्वारा प्रवेश देने से इन्कार कर दिया जाता है। वहीं कई मामलों में प्रक्रिया पूरी करने के लिए रकम मांगे जाने की घटना भी सामने आई है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिभावकों को नामांकन दिलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी से जुड़े परिवार के बच्चों को आरटीई का यह प्रविधान बतौर एक विकल्प या अवसर ही है, लेकिन यह भी प्रभावी नीतियों के अभाव में पूर्णतः लागू नहीं हो पाई है। ऐसे में शिक्षा के अधिकार को केवल शिक्षा तक सीमित करना उचित नहीं है। इसके साथ शिक्षा के समान अवसर को भी संविधान के उपबंध में शामिल किया जाना चाहिए।

शिक्षा के समान अवसर को लेकर पिछले वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय भी निर्णय सुना चुका है। गौरतलब है कि तीन बच्चों को शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा आयोजित ड्रा में सफल रहने पर एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय में सीटें आवंटित की गईं। जबकि स्कूल द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों के कारण छात्रों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया, जिसमें बच्चों का निवास स्कूल से पांच-छह किमी दूर होना भी शामिल था। तीन छात्रों में से एक के बारे में स्कूल ने दावा किया कि भौतिक सत्यापन के दौरान बच्चे का पता नहीं चल सका। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के छात्रों को स्कूलों में पढ़ने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के समान अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा का अधिकार और शिक्षा के समान अवसर को सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के समान अवसर का संबंध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है। शिक्षा किसी भी मनुष्य के मानसिक और नैतिक मूल्यों के विकास के साथ मानव संसाधन का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समुचित नीति के साथ ही उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी आवश्यक है।

(डा. अमरजीत कुमार)

खरी-खरी

अलादीन का चिराग और चुनाव की बेला

पूरन सरमा

गरीब को थाली में भोजन परोस कर लाने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। नेता गरीबों के घरों पर वोटों के लिए दस्तक दे रहे हैं। विकास की बातें वे ही लोग कर रहे हैं, जिन्होंने गरीब को और अधिक गरीब बनाया। अपना-अपना वोट बैंक सुनिश्चित करने की चालें और जनता की आंखों में धूल झोंकने का तमाशा शुरू हो गया है। चुनावी आगाज हो गया है। उन्हें केवल दिल्ली चाहिए, ताकि वे देश की बागडोर संभालें तथा देश को अपने ढंग से हांक सकें। केंद्र की गद्दी के लिए घमासान एक बार फिर शुरू हो चुका है। सबको दरकिनार करके वे आह्वान करने की मुद्रा में आ गए हैं। उनके आह्वान पर वोट न्यौछावर होंगे या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन वे जनता से कहलवा रहे हैं, 'यस वी कैन, यस वी विल डू।' देशभक्ति उनकी रग-रग में समा गई है। अंदाज उनका अपना मौलिक है। वह बताते हैं कि उनकी नीतियां विकास की हैं। बिना विकास के समस्याओं का समाधान संभव नहीं। मैं खुशी से पगला रहा हूं कि रामराज्य की तस्वीर दिखाने वाले इस बार कहीं इसे साकार ही न कर दें।

यह घड़ी बड़ी अद्भुत है। वोटर की परेशानी यह है कि वह किस ओर जाए। लुभावनी बातें दोनों ओर हैं। मुझे लगता है कि एक बार फिर निर्दलियों की पौ बारह होगी। वैसे इनके नारों में केवल छलावा है।

वैसे कुछ नेता एक पार्टी से मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं। उनका सपना यही है कि केवल उनकी पार्टी सत्ता में हो। सुराज भी तभी आता बताते हैं वे। वे तालियां बजवा रहे हैं, हाथ उठवा रहे हैं और सामने बैठे हजारों-लाखों को बेवकूफ समझने की भूल भी कर रहे हैं।

मन करता है कि नई सरकार तत्काल बन जाए तो मजा आ जाए। उन्हें वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी चीजें तो इसी भरोसे पर वे सब बटोर लेंगे। विकास का उजाला फैला हुआ दिखाई दे रहा है। दिक्कत एक ही दिखाई दे रही है कि उनकी टांग खींचने वालों को रोक लीजिए, वरना वे लड़खड़ा कर गिर जाएंगे और सरकार नहीं बना पाएंगे रामराज्य वाली। अलादीन का चिराग लेकर आए हैं ये लोग।

X पोस्ट

ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 1993 से बंद पूजा की दोबारा अनुमति हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। इसे संभव बनाने के लिए भरसक प्रयास करने वाले विष्णु जैन जी और उनके परिवार एवं साथियों को नमन।
डा. पश्यन्ती शुक्ला@DrPashyantiS

हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में एफआइआर दर्ज कराई। यह खबर चौंकाने वाली नहीं है। ऐसा इसलिए, क्योंकि आजकल इस एक्ट का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
अखिलेश त्रिपाठी@highcourtallad

सीता सोरेन और कल्पना सोरेन में झगड़ा शुरू हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन बने। देवरानी-जेठानी, दोनों इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हेमंत बाबू जेल जाएंगे। उनकी कारस्तानियों पर दोनों को कितना विश्वास है। लग रहा है कि ईडी को सुबूत अंदर से ही दिए गए।
विकास सारस्वत@VikasSaraswat

कोहली और शमी पहले से ही उपलब्ध नहीं। राहुल व जडेजा चोटिल हैं। श्रेयस और गिल का बल्ला शांत है। ऐसे में यही सही लगता है कि रोहित खुद मध्यक्रम में आकर खेलें।
मकरंद वेंगणकर@wmakarand

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या रवींद्र जडेजा और केएल राहुल के दूसरे टेस्ट से बाहर होने से भारतीय टीम कमजोर दिखने लगी है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज कराना इसके दुरुपयोग का उदाहरण है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

घर पाया रघुनाथ ने बड़ी खुशी की बात,
पीछे क्यों रहते भला बाबा भोलेनाथ!
बाबा भोलेनाथ फैसला तुरतहिं आया,
पूजा का अधिकार ज्ञानवापी में पाया।
धीरे-धीरे बंधु उठेगा काला साया,
जल्द सुनेंगे आप कि शिव ने भी घर पाया!!
- ओमप्रकाश तिवारी

संजय मिश्र
स्थानीय संपादक, नवदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश डायरी

दिग्गी ने खड़े किए हाथ, नाथ ने साधी चुप्पी

राहुल गांधी की न्याय यात्रा कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यह कितना असरदार होगी यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के सदमे से कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है। पार्टी ने निराश-हताश कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए कमल नाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है, जबकि उमंग सिंघार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। हेमंत कटारे को उप नेता बना दिया गया है, पर जिस उद्देश्य से ये परिवर्तन किए गए वह अब तक फलीभूत होता नहीं दिख रहा है। राज्य में नया नेतृत्व आने के बाद भी न तो कार्यकर्ता हार की हताशा से बाहर आ पाए हैं और न ही ऐसा कोई कार्यक्रम अब तक पार्टी प्रस्तुत कर पाई है, जिससे यह संदेश जाए कि कांग्रेस की स्थिति बदलने वाली है।

लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन कांग्रेसी अब भी विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा एकदूसरे पर फोड़ने में उलझे हैं। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने तो एक तरह से अपनी हार का ठीकरा अपने भाई पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर फोड़ा है। उन्होंने नाम लिए बगैर मिस्टर बंटाधार होने का अर्थ समझाते हुए बता दिया कि वह कितने नाखुश हैं और हार के लिए दिग्विजय व उनके नजदीकी नेताओं को कितना जिम्मेदार मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस में एक तरह का सन्नाटा है। कई क्षेत्रों में उसके नेता-कार्यकर्ता एक-एक करके पार्टी से किनारा कर रहे हैं। पूर्व विधायक राकेश मावई अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल पलिया, पूर्व महामंत्री प्रमोद गुगालिया सहित कई पदाधिकारियों ने कुछ दिन पूर्व ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। विधानसभा चुनाव के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को छोड़ दें तो अधिकतर वरिष्ठ नेता मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं।

दिग्विजय सिंह। फाइल

कमल नाथ। फाइल

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ लंबे समय से प्रदेश के बाहर हैं। विधानसभा चुनाव के बाद वह कुछ समय के लिए भोपाल और छिंदवाड़ा पहुंचे थे। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्होंने गृहक्षेत्र छिंदवाड़ा में कार्यक्रम आयोजित किए और फिर वापस लौट गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहे कमल नाथ की इन दिनों न पार्टी में चर्चा होती और न ही वे कुछ बोल रहे हैं। कमल नाथ की इस चुप्पी के मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने जिस तरह उन्हें हटाया, उससे वह खुश नहीं हैं। कांग्रेस में कमल नाथ ही अकेले नेता हैं जो छिंदवाड़ा में लंबे समय से भाजपा को उभरने का मौका तक नहीं दे रहे, लेकिन उनकी चुप्पी से निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि क्या इस बार छिंदवाड़ा की राजनीति नई करवट लेने के लिए तैयार तो नहीं हो रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी अब तक वह कहीं नजर नहीं आए। उनका कोई बयान भी नहीं आया, जबकि वर्ष 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में कमल नाथ व दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कमल नाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह भले ही चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी में उनकी अहमियत पहले से भी मजबूत हुई। कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेज दिया।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस की मंशा है कि पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाए, लेकिन अनेक वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। ऐसे नेताओं में दिग्विजय सिंह भी शामिल हो गए हैं। पिछले दिनों राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के खिलचीपुर में पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इन्कार कर दिया। उनका कहना था कि अभी राज्यसभा का कार्यकाल शेष है, इसलिए उनके चुनाव लड़ने का प्रश्न ही नहीं है। उनकी इस घोषणा के अनेक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल, चुनाव लड़ने से कन्नी काटने वाले नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में वातावरण भाजपा के अनुकूल हुआ है। ऐसे में विपक्षी दलों के नेताओं के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा।

हिमाचल प्रदेश डायरी

चुनावी मौसम में कांग्रेस के विक्षोभ

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया। चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो गई। चूंकि सरकार कांग्रेस की है, इसलिए उसे ही किसी न किसी को उच्च सदन में भेजना है। किंतु... उससे पहले एक दृश्य देखिए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बुधवार प्रातः कहा कि वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए। उनका भाव यह था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो संगठन से ही आगे आए हैं, इसलिए उन्हें सोचना चाहिए। कहा यह भी, कि यदि कार्यकर्ता ही घर बैठ गया तो चुनाव में कौन जाएगा। ऐसा कहने के बाद बुधवार सायंकाल वह मुख्यमंत्री से भेंट करने पहुंच गईं। विभिन्न रंगों के पुष्पों का गुच्छ भी था और दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान भी। यह वह क्रिया थी जिसे राजनीति में डैमेज कंट्रोल कहा जाता है। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू संगठन में थे और वीरभद्र सिंह सरकार में थे, तब भी प्रतिदिन कुछ नया होता रहता था। क्योंकि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जिनके लिए सम्मान आवश्यक समझती हैं, उनकी सूची भी मुख्यमंत्री को दे चुकी हैं। क्योंकि कुछ लोगों से मंत्री पद वैसे ही छिटका जैसे हाथ में पकड़ा चाय का कप कई बार होठों तक नहीं पहुंचता.... क्योंकि एक विधायक राजेंद्र राणा यह कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में मूंगफली की तरह कैबिनेट रैंक बांटे गए हैं... क्योंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हलकों को मंत्रियों की नहीं, विकास की जरूरत है..। शायद मुख्यमंत्री धरातल को जानने के लिए ही सरकार को गांव की ओर ले जा रहे हैं।

यह उस दुर्लभ राज्य की बात है जहां कांग्रेस सत्ता में है। इस सबके बीच ऐसा प्रतीत होता है कि विचारों, दृष्टियों और अपेक्षाओं की इतनी विविधता में सुरक्षित रास्ता यही होगा कि स्थानीय व्यक्ति के बजाय सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से कहा जाए कि उनमें से कोई राज्यसभा पहुंचे। हाथी के पैर में सबका पैर। प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से ही चर्चा की जाएगी कि करना क्या है। यदि प्रियंका गांधी उच्च सदन में जाती हैं तो साफ माना जाएगा कि वह चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहती हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अखिल भारतीय समिति ही निर्णय लेगी।

लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। युद्ध से पहले मनोबल ऊंचा रखना परम कर्तव्य होता है। किंतु 'यदि कार्यकर्ता ही घर बैठ गया तो चुनाव कौन लड़ेगा'... यह पंक्ति उस कांग्रेस का परिचय है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर धरातल की वास्तविकता से संपर्क ध्वस्त हो चुका है। इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस ने अपना स्वर्णकाल कब देखा यह कहना कठिन है, किंतु पीवी नरसिंहराव का समय कुछ ऐसा समय था जब कार्यकर्ता तक पहुंच थी। अब तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के बांसगांव में उन महावीर प्रसाद के लिए भी टिकट मांगती है जिनके देहांत को दस वर्ष हो चुके हैं, ऐसा दावा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किया है। मनमोहन सरकार के कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र के स्थाई प्रतिनिधि रहे हरदीप पुरी भाजपा में आए, मंत्री बने। सैन्य प्रमुख जैसे संवेदनशील पद पर रहे जनरल वीके सिंह भाजपा में आए, मंत्री बने। गृह सचिव रहे आरके सिंह भाजपा में आए। इन सब लोगों ने कांग्रेस की कार्यशैली को क्रमशः विदेश नीति, सेना और गृह के संदर्भ में बहुत अंदर तक देखा है। उसके बाद बाहर से ही नहीं, राजनीतिक दलों विशेष रूप से कांग्रेस से भी कई लोग भाजपा में आए हैं। ऐसी चर्चा है कि इस बार भी भाजपा की एक समिति भाजपा से बाहर के टैलेंट यानी प्रतिभाओं पर नजर रखे हुए है। और ऐसी प्रतिभाएं राज्यों से भी भाजपा के काम की हो सकती हैं। ऐसे में धरातल से कांग्रेस का संपर्क कटना, विधायक प्राथमिकता बैठकों में कतिपय लोगों का न जाना, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा का कांग्रेस की बैठकों को शोकसभाएं बताना कांग्रेस के हित में नहीं है। कांग्रेस के लिए आवश्यक है कि वह अपने भीतरी गणित और रसायन पर ध्यान दे।

शिमला में मंगलवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू (दाएं) से भेंट करने पहुंचीं प्रतिभा सिंह। जागरण आर्काइव

अपनी ही सरकार पर खीझ उतारना सही है या गलत, ये वही जानें, किंतु संख्याबल अनुमति नहीं देता कि विधायकों के बयान सार्थक होंगे। यह केवल क्रोध की अभिव्यक्ति है या फिर कतिपय पंछियों की उड़ान के संकेत हैं, यह समय ही बताएगा। गुरुवार से कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक शिमला में हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी इसमें आएंगे। श्रीराम मंदिर पर घोर अनिश्चय की शिकार रही कांग्रेस ने अब यह क्षेत्र चुना है जहां वह प्रयास कर रही है।

भाजपा विपक्ष में है। महत्वाकांक्षाएं सबकी हैं, किंतु बाहर ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता। भाजपा वाले इसे अनुशासन बताते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर नियमित हिमाचल आ रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा हमीरपुर, मंडी और शिमला के बाद तीन फरवरी से धर्मशाला आ रहे हैं। धर्मशाला के जोरावर सिंह स्टेडियम में उनका अभिनंदन होगा, जनसभा होगी। भाजपा से जुड़े लोग फरवरी और आधे मार्च को 'बाहरी मेधाओं' के स्वागत के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं।

****

2023 में गूगल की कुल आय 307 अरब डालर रही

सैन फ्रांसिस्को: गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट की पूरे कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान कुल आय 307 अरब डालर रही है और 2022 के मुकाबले इसमें नौ प्रतिशत की वृद्धि रही है। अल्फाबेट के मुख्य वित्तीय अधिकारी रूथ पोराट ने बताया कि अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान कुल राजस्व 86.3 अरब डालर रहा है। गूगल ने 2023 के दौरान 12 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की है और इनको राहत पैकेज पर 2.1 अरब डालर की राशि खर्च की गई है। (आइएएनएस)

अगले कुछ वर्षों में छोटे शहरों में लक्जरी वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसको देखते हुए हम छोटे शहरों में विस्तार की योजना बना रहे हैं।
— संतोष अय्यर, प्रबंध निदेशक, मर्सिडीज-बेंज इंडिया

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलोग्राम	डालर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
71,752.11 ▲ 612.21	21,725.70 ▲ 203.60	₹ 63,350 ▲ ₹50	₹76,700 बदलाव नहीं	₹ 83.04 ▼ ₹0.06	$ 82.12

भारत को पांच ट्रिलियन डालर की आर्थिकी बनाने में सक्षम होगा अंतरिम बजट

बजट 2024-25

राजीव कुमार • नई दिल्ली

एक फरवरी यानी आज पेश होने वाला अंतरिम बजट देश के विकास को दिशा देने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट सत्र आरंभ होने से पहले मीडिया के संबोधन में इसके साफ संकेत दिए। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरिम बजट ऐसे विकास का दिशा-निर्देशक होगा जो हमें अगले तीन साल से भी कम समय में पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम होगा। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.7 ट्रिलियन डालर का है। यानी हमें हर साल अपनी अर्थव्यवस्था में 0.45 ट्रिलियन डालर जोड़ने होंगे। यह दिशा-निर्देशक देश के सर्वांगीण विकास के लिए होंगे जिसमें गरीब, महिला, किसान, युवा व मध्यम वर्ग सभी शामिल होंगे।

अंतरिम बजट में गरीबों के लिए चल रही सभी कल्याणकारी योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों को अधिक राशि मिलने से ग्रामीण खपत को भी समर्थन मिलेगा। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए सरकार लखपति दीदी जैसी या फिर उनके स्वरोजगार के लिए अलग से वित्तीय योजनाएं ला सकती है। टेक्नोलाजी में दुनिया को मात देने के लिए युवाओं को उच्चरूप से कुशल बनाना भी सरकार का लक्ष्य होगा और इस काम के लिए भी बजट में दिशा-निर्देश जारी हो सकते हैं। सरकार भारत को दुनिया का मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है और बजट में इसे लेकर भी सरकार की मंशा दिखेगी। उम्मीद है कि निर्यात व मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ नए दिशा-निर्देश जारी करेगी। वैश्विक कारोबार में कमी को देखते हुए निर्यात प्रोत्साहन के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं।

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश के विकास को दिशा देने वाला बजट
- गरीब, महिला, किसान, युवा व मध्यम वर्ग समेत सभी के लिए घोषणाएं संभव

50 हजार रुपये की अतिरिक्त मानक कटौती की घोषणा संभव है नई कर प्रणाली में

3.7 ट्रिलियन डालर है अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का कुल आकार

अंतरिम बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले बुधवार को नई दिल्ली में अधिकारियों की अपनी टीम के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी तथा भागवत कराड़ • प्रेट्र

इन क्षेत्रों के लिए भी घोषणा होने की संभावना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) को सरकार सर्विस सेक्टर के लिए प्रमुख चुनौती मान रही है। इससे निपटने और एआइ के सकारात्मक परिणाम के सृजन के लिए सरकार नई तकनीक के साथ ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर जैसे सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इन सबके अलावा जिंदगी को और सरल बनाने के लिए स्वास्थ्य बीमा, स्कूल, भूमि उपलब्धता जैसे सेक्टर के लिए भी निर्देश आ सकते हैं। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स के दायरे को विस्तार देना चाहती है। इस काम के लिए इनकम टैक्स की नई प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा सकता है। हो सकता है अंतरिम बजट में नई टैक्स प्रणाली में मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) में 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल जाए। इससे आठ लाख तक की आय इनकम टैक्स से मुक्त हो जाएगी।

आर्थिकी में मजबूती के लिए इन्फ्रा खर्च का ध्यान रखे केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि सरकार को अंतरिम बजट में पूंजीगत खर्च पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि निजी क्षेत्र का पूंजीगत निवेश अपेक्षाकृत कमजोर रहा है और भारतीय आर्थिकी में मजबूती बनाए रखने के लिए इसकी भरपाई जरूरी है।

राजीव कुमार ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पूंजीगत व्यय में वृद्धि से इन्फ्रास्ट्रक्चर की बेहतर गुणवत्ता के परिणाम सामने आ रहे हैं और भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि और प्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ने से वित्त मंत्री राजकोषीय समेकन लक्ष्य भी हासिल कर लेंगी। कुमार के अनुसार, अंतरिम बजट का विषय निवेश या राजकोषीय समेकन पर केंद्रित रहेगा।

राजीव कुमार।

राजीव कुमार ने कहा कि आगे चलकर निजी निवेश भी बढ़ेगा और इससे सरकार पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने का दबाव कम होगा। पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने इन्फ्रा विकास पर आवंटन को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया था। देश के मौजूदा व्यापक आर्थिक हालातों को देखते हुए कुमार ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

एक नजर में

तीन से पांच फरवरी तक बंद रहेगा ई-फाइलिंग पोर्टल

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि तीन फरवरी को दोपहर दो बजे से पांच फरवरी को सुबह छह बजे के दौरान आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने वाले ई-फाइलिंग पोर्टल की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। विभाग ने कहा कि रखरखाव के चलते इस अवधि के दौरान ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। विभाग ने एक्स पोस्ट पर कहा कि सभी करदाताओं इसी के अनुसार अपनी योजना तैयार करें। (प्रेट्र)

भारत में लैपटाप संयंत्र लगाएगी विस्ट्रान कार्प

बेंगलुरु: ताइवानी कंपनी विस्ट्रान कार्प भारत में लैपटाप मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र लगाएगी। 1,500 करोड़ रुपये की लागत वाला यह संयंत्र कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में विस्ट्रान कार्प और कर्नाटक सरकार के बीच गैर-बाध्यकारी समझौता हो गया है। कर्नाटक सरकार ने एक बयान में कहा कि इस संयंत्र से करीब तीन हजार नौकरियां सृजित होंगी। (रायटर)

खुले बाजार में सरकार ने की 71 लाख टन गेहूं की बिक्री

नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को बताया कि खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत अब कर कम मूल्य पर 71.01 लाख टन गेहूं और 1.62 लाख टन गेहूं की बिक्री की जा चुकी है। गेहूं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश पाने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष जून में ओएमएसएस की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत बिक्री के लिए 101.5 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल का आवंटन किया जा चुका है। (प्रेट्र)

चालू सीजन में चीनी उत्पादन में 10% की कमी का अनुमान

नई दिल्ली: चीनी मिलों के उद्योग संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने चालू सीजन में चीनी उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी का अनुमान जताया है। इस्मा का कहना है कि सितंबर 2024 में समाप्त होने वाले चालू विपणन वर्ष में 330.5 लाख टन चीनी की उत्पादन हो सकता है। इस्मा का कहना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन में कमी के कारण कुल चीनी उत्पादन घट सकता है। (प्रेट्र)

पांच प्रतिशत तक सस्ते हो सकते हैं मोबाइल फोन

सरकार ने मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े उपकरणों पर आयात शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: अंतरिम बजट से ठीक एक दिन पहले बुधवार को सरकार ने मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कई कंपोनेंट्स यानी उपकरणों पर आयात शुल्क में पांच प्रतिशत की कटौती की घोषणा की। सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में भारत में निर्मित मोबाइल फोन की लागत तीन से पांच प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है। इससे मोबाइल फोन की कीमत में भी इतनी ही कमी आ सकती है। घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन की निर्माण लागत कम होने से मोबाइल फोन के आयात की गुंजाइश कम हो जाएगी। साथ ही विदेशी कंपनियां भी भारत में मोबाइल बनाने के लिए और अधिक आकर्षित होंगी।

चीन, वियतनाम जैसे देशों में निर्माण लागत भारत के मुकाबले अब भी कम है। इससे विदेशी कंपनियां उन देशों में निर्माण करने के लिए आकर्षित होती हैं। हालांकि, सरकार के इस फैसले से मोबाइल उपकरण निर्माण इकोसिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस कदम से आयातित उपकरण सस्ता होने पर घरेलू निर्माण के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। वित्त मंत्रालय ने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े बैट्री कवर, मेन लेंस, बैक कवर, एंटिना, सिम शाकेट व अन्य मैकेनिकल उत्पादों के आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत तक करने का फैसला किया है। मोबाइल फोन से जुड़ी रिसर्च कंपनी काउंटरपाइंट के निदेशक तरुण पाठक ने बताया कि आयात शुल्क में कमी से फोन निर्माण लागत में 3-5 प्रतिशत की कमी तो आएगी, लेकिन निर्माता कंपनी इसका कितना फायदा ग्राहकों को देती है, यह उन पर निर्भर करेगा। पुराना स्टाक खत्म होने के बाद कंपनियां मोबाइल फोन की कीमत कम कर सकती है। अभी 10 हजार रुपये से कम कीमत वाले फोन की बिक्री पहले के मुकाबले कम हो गई है और कीमत में कमी से इनकी बिक्री बढ़ सकती है।

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पोस्ट में कहा कि सरकार के इस कदम से मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा।

- सरकार के इस कदम से घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को मिलेगा प्रोत्साहन
- चीन और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबले के लिए लिया गया फैसला

राजस्व के लिहाज से शीर्ष कंपनी रही एपल

नई दिल्ली, प्रेट्र: कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान राजस्व के लिहाज से आइफोन निर्माता कंपनी एपल भारतीय बाजार में पहली बार शीर्ष पर रही है। वहीं, संख्या के लिहाज से सैमसंग शीर्ष पर रही है। काउंटरपाइंट रिसर्च की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के दौरान भारत में स्मार्टफोन की थोक बिक्री 15.2 करोड़ इकाई पर स्थिर रही है। बीते वर्ष भारतीय बाजार में सैमसंग, वीवो और ओप्पो की हिस्सेदारी बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, बीते वर्ष एपल ने भारत में एक करोड़ इकाई की बिक्री का आंकड़ा भी पार किया है।

10 हजार रुपये से कम मूल्य वाले फोन की बढ़ सकती है बिक्री

13.9 अरब डालर के फोन का निर्यात हुआ भारत से पिछले वर्ष

भारत में बिकने वाले 98 प्रतिशत फोन मेड इन इंडिया

वर्तमान में भारत में बिकने वाले 98 प्रतिशत फोन मेड इन इंडिया हैं। भारत में एक अरब से अधिक लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन निर्माण व निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार ने वर्ष 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद से मोबाइल फोन का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 13.9 अरब डालर के फोन का निर्यात किया था।

ज्यादा शुल्क से बढ़ रही थी मैन्यूफैक्चरिंग लागत

इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्रू ने बताया कि कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क अधिक होने से घरेलू स्तर पर बनने वाले फोन की लागत अधिक हो रही थी। इससे कंपनियां फोन की कीमत बढ़ा सकती थी। ऐसा होने पर सस्ते मोबाइल फोन का आयात बढ़ सकता था जिससे घरेलू फोन निर्माण पर प्रतिकूल असर पड़ता। इसलिए फोन निर्माता कंपनियों की तरफ से कंपोनेंट्स के आयात शुल्क में कटौती की मांग की जा रही थी।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में एक मार्च से जमा करने पर रोक

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने बुधवार को कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) 29 फरवरी के बाद यानी एक मार्च से अपने खातों में ग्राहकों से जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा। इसके अलावा पीपीबीएल से जुड़े प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वालेट और फास्टैग टाप-अप पर भी रोक लगाई गई है। आरबीआइ ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सिस्टम की व्यापक आडिट रिपोर्ट और बाहरी आडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद यह कार्रवाई की है। आरबीआइ की इस कार्रवाई पर पीपीबीएल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

आरबीआइ ने एक बयान में कहा कि पीपीबीएल एक मार्च से किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वालेट, फास्टैग, नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) आदि में कोई भी जमा, क्रेडिट लेनदेन या टापअप नहीं कर सकेगा। हालांकि, इनमें किसी भी प्रकार का ब्याज, कैशबैक या रिफंड जमा हो सकेगा। ग्राहक इनमें जमा अपनी राशि की निकासी या इसका इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध कर सकेंगे। आरबीआइ के इस फैसले का पेटीएम की यूपीआइ सेवाओं पर कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा आरबीआइ ने पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पीपीबीएल के नोडल खातों को भी समाप्त कर दिया है। इससे पहले मार्च 2022 में आरबीआइ ने तुरंत प्रभाव से पीपीबीएल को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। पीपीबीएल में वन97 कम्युनिकेशंस की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन पीपीबीएल को वन97 कम्युनिकेशंस की सब्सिडियरी के बजाए एसोसिएट कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- पीपीबीएल से जुड़े वालेट और फास्टैग टाप-अप पर भी रोक लगाई गई
- आरबीआइ के फैसले का पेटीएम की यूपीआइ सेवाओं पर नहीं होगा असर

2023 के दौरान भारत में सोने की मांग तीन प्रतिशत घटी

मुंबई, प्रेट्र: कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान देश में सोने की मांग वार्षिक आधार पर तीन प्रतिशत घटकर 747.5 टन रही है, जो 2022 में 774.1 टन थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि यदि कीमतें स्थिर रहती हैं और बहुत अधिक अस्थिर नहीं होती हैं तो 2024 में देश में सोने की मांग बढ़कर 800-900 टन के बीच रह सकती है।

डब्ल्यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2023 के दौरान सोने की मांग बढ़ती कीमतों से काफी प्रभावित रही है। हालांकि, इस दौरान उपभोक्ता की रुचि अधिक रही लेकिन व्यापार धारणा पिछड़ गई। अक्टूबर में नवरात्र के दौरान कीमत में सुधार ने उपभोक्ताओं को प्रेरित किया, जिससे नवंबर में दीवाली के दौरान बिक्री को बढ़ावा मिला। डब्ल्यूजीसी इंडिया के सीईओ सोमासुंदरम पीआर ने कहा कि दिसंबर में मूल्य बढ़ने से सोने की मांग एक बार फिर कम हो गई। इसका नतीजा यह रहा है कि अक्टूबर-दिसंबर 2023 में सोने की कुल मांग नौ प्रतिशत घटी है।

इसी तरह पूरे 2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर भी सोने की मांग पांच प्रतिशत घटकर 4,448.4 टन रही है, जो 2022 के दौरान 4,699 टन रही थी। डब्ल्यूजीसी का कहना है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से लगातार निकासी के चलते वैश्विक स्तर पर सोने की मांग घटी है।

डब्ल्यूजीसी ने कहा- बढ़ती कीमतों का दिखा मांग पर असर, वैश्विक स्तर पर मांग पांच प्रतिशत घटकर 4,448.4 टन रही

बजट से पहले 612 अंक बढ़ा सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र: एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में मजबूत खरीदारी की बदौलत अंतरिम बजट से एक दिन पहले घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को 612.21 अंक की वृद्धि के साथ 71,752.11 अंक पर जाकर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 203.60 अंक उछलकर 21,725.70 के स्तर पर जाकर बंद हुआ।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अंतरिम बजट से पहले भारतीय बाजारों में सकारात्मक माहौल का असर दिखा है। हालांकि, उम्मीदें कम हैं। बाजार को कर राजस्व में बढ़ोतरी के कारण राजकोषीय घाटे में कमी रहने की उम्मीद है। नायर ने कहा कि इस समय निवेशक निचले स्तर पर खरीदारी की रणनीति अपना रहे हैं। 10 वर्षीय अमेरिकी बांड यील्ड में नरमी का भी घरेलू बाजारों में लाभ मिल रहा है।

जनवरी में दूसरी बार सबसे अधिक रहा जीएसटी संग्रह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जनवरी माह का जीएसटी संग्रह 1,72,129 करोड़ रुपये रहा, जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 और अब तक का दूसरा सबसे अधिक संग्रह है। इससे पहले अप्रैल 2023 में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था। जनवरी 2023 के मुकाबले इसमें 10.4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि रही है। चालू वित्त वर्ष में यह तीसरा मौका है जब जीएसटी संग्रह 1.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में कुल जीएसटी संग्रह 16.69 लाख करोड़ रहा है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 14.96 लाख करोड़ से 11 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष में सभी 10 महीने के दौरान जीएसटी संग्रह 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। जीएसटी संग्रह में लगातार बढ़ोतरी खपत में तेजी को दर्शाता है क्योंकि जीएसटी संग्रह सीधे तौर पर वस्तु की बिक्री से जुड़ा है। वस्तु की बिक्री अधिक होने पर ही जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी होती है। जीएसटी संग्रह में राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है। यह 31 जनवरी को शाम पांच बजे तक का आंकड़ा है और कुल संग्रह में वृद्धि संभव है।

दिसंबर में 3.8 प्रतिशत रही प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर : दिसंबर 2023 के दौरान आठ प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की विकास दर 3.8 प्रतिशत रही है और यह 14 महीने का निचला स्तर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने कच्चे तेल, बिजली, स्टील और सीमेंट जैसे क्षेत्रों का प्रदर्शन कमजोर रहा है। दिसंबर 2022 में आठ प्रमुख क्षेत्रों की विकास दर 8.3 प्रतिशत थी। अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान इन क्षेत्रों की विकास दर 8.1 प्रतिशत पर स्थिर रही है।

1.72 लाख करोड़ से अधिक रहा जीएसटी संग्रह जनवरी 2024 के दौरान

1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था सबसे अधिक कर संग्रह अप्रैल 2023 में

1.50 लाख करोड़ से अधिक रहा संग्रह चालू वित्त वर्ष में अब तक हर महीने

बजट लक्ष्य के 55 प्रतिशत पर पहुंचा वित्तीय घाटा

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान सरकार को कुल 20,71,939 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई जो बजट अनुमान का 76.3 प्रतिशत है। इस में 17,29,931 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में प्राप्त हुए। अप्रैल-दिसंबर के दौरान सरकार का कुल व्यय 30,54,217 करोड़ रुपये रहा है जो बजट अनुमान का 67.8 प्रतिशत है। पहले नौ महीनों में राजकोषीय घाटा 9.82 लाख करोड़ रहा है जो बजट अनुमान का 55 प्रतिशत है। सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटा 17.86 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया है।

डिजिटल पेमेंट में 10.94 प्रतिशत की वृद्धि

मुंबई, प्रेट्र : देश में डिजिटल भुगतान में सितंबर 2023 से पहले के एक साल में 10.94 प्रतिशत की वृद्धि रही है। आनलाइन लेनदेन मापने वाले आरबीआइ सूचकांक से यह जानकारी सामने आई है। आरबीआइ का डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर 2023 के अंत में 418.77 पर था, जबकि सितंबर 2022 में यह 377.46 था। वहीं, मार्च 2023 में यह सूचकांक 395.57 पर था।

राष्ट्रीय फलक

फास्टैग के लिए केवाईसी की समय सीमा बढ़ा सकती है एनएचएआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) फास्टैग के लिए केवाईसी की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा सकती है। इससे पहले 15 जनवरी को एनएचएआइ ने कहा था कि बैंक अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी 2024 के बाद बंद कर देंगे, भले ही उनमें वैध राशि मौजूद हो। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि 1.27 करोड़ में से केवल सात लाख मल्टीपल फास्टैग बंद किए गए हैं। इसलिए, हम इस समय सीमा को एक महीने और बढ़ा रहे हैं।

इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए एनएचएआइ ने एक वाहन, एक फास्टैग पहल लागू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल या एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने को रोकना है। एनएचएआइ ने कहा था कि फास्टैग का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप फास्टैग की केवाईसी पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। असुविधा से बचने के लिए नवीनतम फास्टैग का केवाईसी पूरा होना जरूरी है।

- अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी से बंद करने की बात कही थी
- 41.27 करोड़ में से केवल सात लाख मल्टीपल फास्टैग बंद किए गए हैं

केन-बेतवा लिंक परियोजना की निविदा शर्तों को लेकर कंपनियों को आपत्ति, रुका है काम

राज्य ब्यूरो, भोपाल

- कंपनियों की मांग, निर्माण सामग्री की रायल्टी बढ़ने पर उसकी भरपाई सरकार करे, समाधान निकालने आज भोपाल में बैठक

केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखना चाहती है, पर अब तक टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है। पिछले वर्ष दौधन बांध निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया था, किंतु इच्छुक कंपनियों द्वारा शर्तों को लेकर आपत्तियां जताने के कारण टेंडर प्रक्रिया की तारीख बढ़ती गई। आपत्तियों के समाधान के लिए गुरुवार को भोपाल में मध्य प्रदेश, उप्र व केंद्र सरकार के अधिकारी बैठक करेंगे। उधर, मप्र के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों को बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमिपूजन फरवरी में किया जाएगा।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि टेंडर की शर्तों में व्यावहारिक कठिनाइयों को लेकर कंपनियों का तर्क है कि निर्माण सामग्री की रायल्टी बढ़ने पर उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाए। वहीं, वन विभाग को भूमि हस्तांतरित नहीं होने के कारण भी परियोजना प्रभावित हो रही है। बता दें, अब तक 11 कंपनियों ने टेंडर में रुचि दिखाते हुए इसकी शर्तों में कुछ बदलाव के अलावा तिथि बढ़ाने की बात कही है। इसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी), एस्कान इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड, दिलीप बिल्डकान, एसटीएन शामिल हैं। इच्छुक कंपनियों द्वारा उठाए गए विषयों पर उच्च स्तरीय बैठक में विचार किया जाएगा। बता दें, केन-बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। इससे मप्र और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा।

ये जिले होंगे लाभान्वित : परियोजना से मप्र के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया व रायसेन और उप्र के महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर जिले लाभान्वित होंगे।

इटावा में लाल सिग्नल से एक किमी आगे जाकर रुकी शिवगंगा एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, इटावा

- दिल्ली-हावड़ा रूट पर भरथना स्टेशन से पहले की घटना, दोनों लोको पायलट से पूछताछ

दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर इटावा में भरथना स्टेशन से पांच किलोमीटर पहले शिवगंगा एक्सप्रेस लाल सिग्नल पार (ओवरशूट) कर गई। ट्रेन की रफ्तार करीब 80 किमी प्रतिघंटा थी और सिग्नल से करीब एक किलोमीटर आगे जाकर रुकी। जिस समय घटना हुई, उसी लाइन पर स्टेशन में हमसफर एक्सप्रेस खड़ी थी। अधिकारियों ने दोनों लोको पायलट से पूछताछ की, साथ ही उनका मेडिकल कराया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। लापरवाही मिलने पर दोनों लोको पायलट पर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से दिल्ली जा रही शिवगंगा एक्सप्रेस (12599) बुधवार सुबह करीब नौ बजे 80 किमी प्रतिघंटा से चल रही थी। भरथना स्टेशन से पहले सिग्नल संख्या 507 लाल था। यहां ट्रेन को रुकना था, लेकिन ट्रेन सिग्नल पार कर करीब एक किमी दूर जाकर रुकी। भरथना स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल को सूचना दी। साथ ही ट्रेन को भरथना स्टेशन लाकर प्लेटफार्म नंबर चार पर रोका गया। दोनों लोको पायलट को ट्रेन से उतार लिया गया। इसके बाद टूंडला जंक्शन से आए दो लोको पायलट पहुंचे और शिवगंगा एक्सप्रेस को लेकर रवाना हो गए।

****

संघर्ष विराम प्रयासों के बीच गाजा में जंग जारी

इजरायल का उत्तरी गाजा में 15 हमास आतंकियों को मार गिराने का दावा

दक्षिणी गाजा में भीषण युद्ध, आतंकियों को निकालने को सुरंगों में डाले पानी

इजरायली हमले में 24 घंटे में 150 फलस्तीनियों ने गंवाई जान, 313 घायल

हमास से लड़ाई के दौरान बुधवार को गाजा पट्टी में इजरायली हमले के बाद उठता धुआं। एएफपी

यरुशलम, एपी: गाजा में संघर्ष विराम के नए प्रस्तावों पर हमास के विचार के बीच तनाव जारी है। लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। सबसे भीषण लड़ाई दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस में चल रही है। इजरायली सेना को यहां की सुरंगों में हमास कमांडरों के छिपे होने की आशंका है। इजरायली बल इन सुरंगों में पानी डालकर उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सेना ने दावा किया है कि उसने उत्तरी गाजा में मंगलवार को स्कूल में छिपे 15 आतंकियों को मार गिराया है।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि बीते 24 घंटे में इजरायली बलों के हमले में गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में 150 फलस्तीनियों ने जान गंवाई और 313 घायल हुए हैं। ताजा मौतों से इजरायल के हमले में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 26,900 हो गई है। वहीं, इजरायली सेना ने कहा, उसने मंगलवार को उत्तरी गाजा में 15 से अधिक हमास आतंकवादियों को मार गिराया और एक स्कूल में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। इसमें कहा गया है कि हवाई और जमीनी हमले में गाजा शहर में शती शरणार्थी शिविर के बाहरी इलाके में छिपे आतंकियों को निशाना बनाया, जो 1948 में इजरायल के निर्माण के आसपास हुए युद्ध के समय का है और एक घने शहरी पड़ोस जैसा दिखता है। सेना ने नवंबर के मध्य में कहा था कि शती पर उसका नियंत्रण है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि फलस्तीन में एक चौथाई आबादी भूख से मर रही है।

हाउती विद्रोहियों के जहाज-रोधी क्रूज मिसाइल को अमेरिका ने मार गिराया: ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों का लाल सागर में मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, 30 जनवरी को स्थानीय समय के अनुसार करीब 11:30 बजे यमन के हाउती-नियंत्रित क्षेत्रों से लाल सागर की ओर एक जहाज-रोधी क्रूज मिसाइल दागी गई, जिसे अमेरिका के यूएसएस ग्रेवली द्वारा मार गिराया गया।

इजरायल ने की यूएनआरडब्ल्यूए का अधिकार छीनने की मांग : इजरायल में 7 अक्टूबर को हुए हमास के आतंकी हमले में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के शामिल होने के आरोपों के बीच अब इजरायल ने एजेंसी का अधिकार छीनने की मांग की है। गौरतलब है कि इजरायल के आरोप के बाद नौ देशों ने एजेंसी को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी है। हालांकि आरोपों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इजरायल ने कहा कि एजेंसी के 12 कर्मचारियों ने हमास के हमले में उनका साथ दिया था। ये एजेंसी गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, जार्डन और लेबनान में 60 लाख लोगों की मदद कर रही है। इसका काम संघर्ष प्रभावित लोगों की मानवीय मदद करना, राहत का सामान पहुंचा आदि है। इजरायल के इन बेहद गंभीर आरोपों के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, फिनलैंड और स्विटजरलैंड यूएनआरडब्ल्यूए को फंड देना बंद करने की घोषणा की। इजरायल ने कहा कि वह गाजा में संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता एजेंसी को काम नहीं करने देगा। इजरायल ने कहा कि गाजा के पुर्ननिर्माण के लिए एजेंसी को सच में शांति और विकास के लिए समर्पित एजेंसियों से बदला जाना चाहिए। वहीं, यूएनआरडब्ल्यूए पर आरोप लगाए जाने की हमास ने निंदा की। उसने कहा, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को इजरायल के खतरों और दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। यूएनआरडब्ल्यूए के आयुक्त-जनरल फिलिप लाजारिनी ने कहा कि नौ देशों के फैसले से पूरे क्षेत्र में खासकर गाजा में उसके मानवीय कार्यों को काफी खतरा है।

गाजा-यूक्रेन क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं का नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन

स्टवान्गर्म, एपी : वर्ष 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए होने वाला नामांकन बुधवार को बंद हो गया। इसमें यूक्रेन और गाजा क्षेत्र में शांति के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं भी नामांकित की गई हैं। फ्री यूनिवर्सिटी एम्सटर्डम में शिक्षाविद् ने कहा है कि उन्होंने इजरायल और फलस्तीन में शांति प्रयासों के लिए पश्चिम एशिया के इकोपीस, वुमन वेज पीस और वुमन आफ द सन आफ पीस संस्थाओं को नामांकित किया है। वहीं नार्वे की सांसद इंगविल्ड वेट्रहस थोर्सविक ने कहा है कि उन्होंने फलस्तीनी वीडियो जर्नलिस्ट मोताज अजैजा को गाजा पर खबर के लिए नामांकित किया है। ज्ञात हो, इस पुरस्कार के लिए 300 के करीब नाम आमंत्रित किए जाते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान व उनकी पत्नी को तोशाखाना मामले में 14 वर्ष की सजा

- अदालत ने दोनों पर 10 साल तक सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर लगाई रोक
- जवाबदेही कोर्ट ने दोनों पर अलग-अलग 78.7 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया

इस्लामाबाद, प्रेट्र: पाकिस्तान में आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगातार दूसरे दिन कोर्ट से झटका लगा है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जवाबदेही कोर्ट ने बुधवार को इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की कठोर सजा सुनाई है। दोनों के 10 वर्ष तक कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर रोक लगा दी है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने इमरान खान को गोपनीय राजनयिक दस्तावेज लीक करने का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी।

जवाबदेही अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अदियाला जेल परिसर में मामले की सुनवाई की। जहां भ्रष्टाचार के अन्य मामले में वह पहले से ही तीन वर्ष की सजा काट रहे हैं। अदालत ने दोनों पर 78.7 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के संस्थापक इमरान पर पीएम रहने के दौरान विदेशी मेहमानों से प्राप्त तोशाखाना में जमा सरकारी उपहारों को रियायती दरों पर खरीद कर महंगे दाम पर बेचने का आरोप है। उनकी पत्नी बुशरा को भी सरकारी उपहारों से लाभ लेने का दोषी ठहराया गया है। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी ने अदियाला जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया। वहीं, पीटीआइ ने इसे कंगारू कोर्ट का फैसला बताते हुए कहा, इसका चुनाव में असर नहीं पड़ेगा। पार्टी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। उधर, इमरान ने अपने नामांकन पत्र के खारिज होने को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी। फाइल/एएफपी

इमरान व बुशरा के निकाह मामले में फैसला सुरक्षित : इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को इमरान और बुशरा के निकाह मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। बुशरा इमरान की तीसरी पत्नी हैं। बुशरा के पूर्व पति ने दोनों के निकाह को गैर-इस्लामिक बताते हुए चुनौती दी है। कहा, इमरान ने मुस्लिम महिला के तलाक के बाद तीन महीने के इद्दत के समय का इंतजार नहीं किया। उससे पहले ही निकाह कर लिया।

पाकिस्तान में पीटीआइ के नेता की गोली मारकर हत्या

पेशावर, प्रेट्र : पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के एक नेता की खैबर पख्तूनख्वा में रैली के दौरान बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात शख्स की ओर से की गई गोलीबारी में तीन अन्य समर्थक घायल हो गए। उम्मीदवार रेहान जैब खान बाजौर निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उनकी मौत की पुष्टि की है। वह पीटीआइ के सक्रिय नेता थे, हालांकि पार्टी के चुनाव में भाग न लेने के कोर्ट के आदेश के बाद वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर जांच अभियान शुरू कर दिया है। पख्तूनख्वा में यह घटना बलूचिस्तान प्रांत में हुए धमाके के एक दिन बाद हुई है। बलूचिस्तान में मंगलवार को उस समय धमाका हुआ था, जब पीटीआइ की रैली वहां से गुजर रही थी। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच घायल हुए थे। धमाका सिबी शहर के जिन्ना रोड पर हुआ था। देश में आठ फरवरी को आम चुनाव होने हैं। बलूचिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री ने कहा था कि चुनाव अपने तय समय पर होंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि यह धमाका चुनाव को लेकर प्रांतीय सरकार को हतोत्साहित करने का प्रयास था। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तलब की है।

मोदी की यूएई यात्रा से पहले जोरों पर तैयारियां

दुबई, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय समुदाय के एक विशाल कार्यक्रम के साथ ही हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए फरवरी के मध्य में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले हैं। खाड़ी देश में भारतीय मिशन के अधिकारी इसे लेकर तैयारियां कर रहे हैं।

मोदी 13 फरवरी को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम अहलान मोदी (हेलो मोदी) को संबोधित करने वाले हैं और 14 फरवरी को हिंदू मंदिर के समारोह में भाग लेने वाले हैं। स्वामीनारायण संस्था की ओर से कहा गया है कि धार्मिक परिसर का निर्माण पूरा होने के करीब है। महंत स्वामी महाराज और भारतीय प्रधानमंत्री 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। मोदी की यूएई यात्रा की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्वागत समारोह स्थल पर हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे।

एच-1बी वीजा में धोखाधड़ी रोकने को प्रणाली में बदलाव करेगा अमेरिका

- लाभार्थी केंद्रित चयन प्रक्रिया समेत अपनाएं जाएंगे कई उपाय
- वित्तीय वर्ष 2025 के लिए छह मार्च से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका ने धोखाधड़ी की आशंका दूर करने के लिए एच-1बी वीजा की वार्षिक लाटरी प्रणाली में बदलाव की घोषणा की है। लाभार्थी केंद्रित चयन प्रक्रिया समेत कई उपायों के जरिये वीजा प्रणाली की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। एच-1बी वीजा भारतीय आइटी पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए एच-1बी वीजा आवेदन प्रक्रिया छह मार्च से शुरू होगी, जो 22 मार्च तक चलेगी। इससे पहले अमेरकी ने एच-1बी वीजा के लिए घरेलू नवीनीकरण की सुविधा देते हुए 29 जनवरी से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।

एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है, जिसके जरिये अमेरिकी कंपनियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित विदेशी कर्मियों की नियुक्ति का अधिकार मिलता है। इसमें भारतीय और चीनी पेशेवरों की विशेष मांग रहती है। अमेरिकी नागरिकता

एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआइएस) ने मंगलवार को घोषणा की कि नई प्रणाली के तहत पंजीकरण के दौरान लाभार्थी केंद्रित चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे पहले कुछ लोगों द्वारा कई आवेदनों के जरिये लाभ लेने की कोशिश की जाती रही है। अब यदि कोई आवेदक विभिन्न कंपनियों में कई आवेदन करता है तो उसे अभ्यर्थी के पासपोर्ट नंबर के आधार पर एक आवेदन गिना जाएगा। पंजीकरण प्रणाली में गेमिंग को रोककर अभ्यर्थी के हितों की सुरक्षा की जाएगी, चाहे उसने जितने आवेदन किए हों।

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा की ओर से कहा गया है कि नए नियमों का उद्देश्य प्रणाली की अखंडता को मजबूत कर धोखाधड़ी की आशंका को दूर करना है। यूएससीआइएस के निदेशक यूआर एम जड्डू ने कहा कि हम सदैव सिस्टम में सुधार कर किसी भी खामी को रोकने के प्रयास में रहते हैं। हम पंजीकरण से लेकर विदेश विभाग की मंजूरी तक एच-1बी वीजा प्रक्रिया को पूरी तरह इलेक्ट्रानिक बना रहे हैं।

ट्रंप के जवाब में निक्की का 'मेक अमेरिका नार्मल अगेन' का नारा

- पूर्व राष्ट्रपति की ओर से निक्की हेली को बताया गया युद्ध फैलाने वाली नेता

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अभियान की सरगर्मी तेज होने के साथ आरोप-प्रत्यारोप भी बढ़ते जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी में प्रत्याशी बनने की होड़ में शामिल भारतवंशी निक्की हेली ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के जवाब में नया नारा 'मेक अमेरिका नार्मल अगेन' दिया है। वहीं, ट्रंप का अभियान चलाने वालों ने निक्की हेली को युद्ध फैलाने वाली नेता बताया। कहा, उनके विचार अमेरिका को हमेशा के लिए युद्ध में झोंकने वाले हैं।

अपने गृह राज्य दक्षिणी कैरोलिना में मंगलवार को आक्रामक अभियान चलाते हुए निक्की हेली ने अपनी टीम से कहा कि हमारा अभियान देश भर के उन लोगों के नोट्स और ईमेल से भर गया है जो अमेरिका को फिर से सामान्य बनाना चाहते हैं। दक्षिण कैरोलिना से दो बार गवर्नर रहीं हेली अपने गृह राज्य में ट्रंप से 30 से अधिक अंकों से पीछे चल रही हैं, जहां 23 फरवरी को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के लिए प्राथमिक चुनाव होना है। वह

निक्की हेली। फाइल फोटो

इसमें मजबूत प्रदर्शन करने को लेकर आश्वस्त हैं। कहा, वह 80 साल के जो बाइडन और ट्रंप दोनों को हराने में सक्षम हैं। वहीं, दूसरी ओर ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने कहा कि वास्तविकता यह है कि निक्की राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के पक्ष में मजबूत तक नहीं रख पा रही हैं। कहा, दरअसल वह एक युद्धोन्मादी नेता हैं। ट्रंप अब तक हुए दो राज्यों में रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव जीत चुके हैं।

भारतीय श्रमिक अगले सप्ताह से इजरायल पहुंचना होंगे शुरू

यरुशलम, प्रेट्र: हमास से संघर्ष के कारण इजरायल का निर्माण क्षेत्र श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है। अगले सप्ताह से भारत के दस हजार निर्माण श्रमिक इजरायल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इजरायल बिल्डर्स एसोसिएशन (आइबीए) ने बताया कि ये श्रमिक प्रति सप्ताह 700 से एक हजार श्रमिकों के जत्थे में पहुंचेंगे।

गाजा में हमास के साथ चार माह से जारी संघर्ष, फलस्तीनी श्रमिकों के प्रवेश पर पाबंदी और हजारों विदेशी श्रमिकों के चले जाने के कारण इजरायल का निर्माण उद्योग गहरे संकट में है। श्रमिकों की कमी के कारण इजरायल में कई परियोजनाएं अटक गई हैं। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए देश के निर्माण उद्योग में विदेशी श्रमिकों का कोटा 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है और गत माह इजरायल की सरकार ने भी भारत के 10 हजार श्रमिकों के आगमन को मंजूरी दे दी है।

मालदीव में महाभियोजक हुसैन शमीम पर हमला

- सड़क पर चाकू से किया हमलावरों ने वार, अस्पताल से छुट्टी
- एमडीपी ने हमले के लिए मुइज्जू प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया

माले, एएनआइ: मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) सरकार में नियुक्त महाभियोजक हुसैन शमीम पर दिनदहाड़े सड़क पर चाकू से हमले के बाद सत्तारूढ़ व विपक्षी दलों के बीच दोषारोपण का खेल शुरू हो गया है। दोनों पक्षों ने घटना को राजनीति प्रेरित बताया है।

हुसैन शमीम ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अल्लाह का शुक्र मनाते हुए कहा कि वह अपने परिवार के साथ घर पर हैं। शमीम पर सुबह माले की सड़क पर बाइक सवार अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया था। मुख्य विपक्षी दल एमडीपी ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही प्रशासन को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने इस हमले को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं, गृह मंत्री अली इहुसान ने उनके इस दावे की पुष्टि के लिए जानकारी साझा करने को कहा है।

पुनर्नियुक्ति असंवैधानिक : एमडीपी ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सरकार के तीन मंत्रियों की पुनर्नियुक्ति के खिलाफ संसद में प्रस्ताव जमा करके उसे असंवैधानिक करार दिया। नियुक्ति को संसद ने खारिज कर दिया था। सरकार ने पुनर्नियुक्ति पर विचार करने की अपील की। सांसद इवा अब्दुल्ला ने कहा कि यह नियुक्ति संसद की शक्तियों का उल्लंघन है।

नाशीद ने मालदीव छोड़ा : पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद अस्थाई रूप से मालदीव छोड़कर पश्चिमी अफ्रीका के घाना चले गए हैं। उन्होंने संसद को इसकी जानकारी दिए बगैर ही सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। 56 वर्षीय नाशीद मालदीव के पहले राष्ट्रपति हैं।

दुनिया में सर्वाधिक वेतन लेने वाले मस्क को कोर्ट का झटका

- अदालत ने कहा- कंपनी हित में नहीं है इतना अधिक वेतन

डोवर, एपी: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को अमेरिका की कोर्ट ने झटका दिया है। डेलावेयर के न्यायाधीश ने मंगलवार को अपने आदेश में माना कि मस्क अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी से 55 अरब डालर (तकरीबन 45,700 करोड़ रुपये) से अधिक का वेतन लेने के हकदार नहीं है। यह शेयरधारकों के लिए नुकसानदेह है। एक शेयरधारक द्वारा दायर मुकदमे में पांच साल बाद यह फैसला आया है।

डेलावेयर की अदालत में शेयरधारक के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि मस्क ने अपने वेतन पैकेज को प्रभावित किया। मस्क के वेतन पैकेज का निर्धारण करने वाले कंपनी के निदेशक स्वतंत्र नहीं है और उनके मस्क से गहरे संबंध हैं। इस कारण उन्होंने पैकेज की शर्तों पर अपनी मर्जी चलाई और भारी-भरकम पैकेज मंजूर कराया। मस्क के अधिवक्ताओं ने आरोपों को खारिज किया। हालांकि अदालत ने माना कि मस्क कंपनी से 55 अरब डालर से अधिक वेतन नहीं ले

मस्क के वेतन पैकेज को एक शेयरधारक ने दी थी चुनौती

सकते हैं। इस मामले में मस्क ने एक्स पोस्ट कर कहा, अपनी कंपनी डेलावेयर में कभी नहीं बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि कंपनी के मामलों पर शेयरधारक निर्णय लें तो मैं नेवादा अथवा टेक्सास में कंपनी बनाने का सुझाव देता हूं।

कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं मस्क : दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने माह की शुरुआत में टेस्ला के बोर्ड से कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 13 से 25 प्रतिशत करने को कहा था। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार, मस्क की संपत्ति 210 अरब डालर के पार निकल चुकी है।

चीन ने उड़ान पथ में किया बदलाव, ताइवान ने जताई नाराजगी

ताइपे, रायटर : ताइवान के नागरिक उड्डयन प्रशासन (सीएए) ने मंगलवार को ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा के करीब उड़ान मार्गों के चीन के एकतरफा बदलाव का विरोध किया है। दरअसल, चीन ने कहा है कि वह रूट डब्ल्यू122 और डब्ल्यू123 का पूर्व की ओर संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है, जो रूट एम503 को फुजियान प्रांत के फूजौ और जियामेन शहरों से जोड़ता है। चीन के नए उड़ान मार्ग एक फरवरी से लागू होने हैं। यह विमानन सुरक्षा की उपेक्षा करता है।

सीएए ने कहा कि यह निर्णय 2015 में ताइवान स्ट्रेट के दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति का उल्लंघन है। 2015 में चीन ने एकतरफा तौर पर एम503 मार्ग के संचालन की घोषणा की थी। हालांकि, ताइवान के साथ बातचीत के बाद चीन उस समय एम503 मार्ग को उसके मूल पथ से छह समुद्री मील पश्चिम में स्थानांतरित करने पर सहमत हुआ था।

चीनी हैकर्स के निशाने पर अमेरिका का बुनियादी ढांचा

- एफबीआइ डायरेक्टर ने इसे लेकर चिंता जताई है
- हमले का समय कब होगा यह चीन को तय करना है

वाशिंगटन, एपी : चीनी हैकर्स अमेरिकी मूलभूत सुविधाओं को निशाना बना रहे हैं। इसमें जलशोधन संयंत्र, बिजली ग्रिड, परिवहन सेवा सहित देश के अन्य महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधा प्रदान करने वाले क्षेत्र शामिल हैं। एफबीआइ के डायरेक्टर क्रिस रे इसे लेकर सांसदों को जानकारी देंगे। चीन पर हाउस सेलेक्ट कमेटी के समक्ष तैयार की गई टिप्पणियों की एक प्रति के अनुसार साइबर खतरे पर सार्वजनिक रूप से बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है।

चीन के हैकर्स अमेरिकी बुनियादी ढांचे पर तबाही मचाने और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में हैं। यह फैसला चीन को करना है कि हमला का समय कब होगा। ये टिप्पणियां माइक्रोसाफ्ट सहित अन्य साइबर सुरक्षा फर्मों के आकलन के अनुरूप हैं, जिन्होंने मई में कहा था कि राज्य समर्थित चीनी हैकर अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्षित कर रहे हैं और भविष्य के संकटों के दौरान अमेरिका और एशिया के बीच महत्वपूर्ण संचार के संभावित व्यवधान के लिए तकनीकी आधार तैयार कर सकते हैं।

रे ने कहा कि हर दिन वे सक्रिय रूप से हमारी आर्थिक सुरक्षा पर हमला कर रहे हैं। वे हमारे नवाचार और हमारे व्यक्तिगत और कार्पोरेट डेटा की चोरी में संलग्न हैं। विस्कान्सिन के रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक गैलाघेर की अध्यक्षता में समिति की स्थापना पिछले साल चीन का मुकाबला करने के लिए की गई थी। चीनी सरकार ने समिति की आलोचना करते हुए मांग की है कि इसके सदस्य अपने वैचारिक पूर्वाग्रह की मानसिकता को त्यागें।

अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-16 दक्षिण कोरिया में दुर्घटनाग्रस्त

सिओल, एपी: अमेरिका की वायु सेना का एक लड़ाकू विमान एफ-16 बुधवार को दक्षिण कोरिया में दक्षिण पश्चिमी तट के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे से पहले ही पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकल आया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच की जा रही है।

दो माह से भी कम समय में यह दूसरी दुर्घटना है। अमेरिका के आठवें फाइटर विंग के कमांडर कर्नल मैथ्यू सी. गेटके ने पायलट की बरामदगी के लिए कोरिया गणराज्य के बचाव बलों व अपने अन्य साथियों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि पायलट को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है। दो एफ-16 स्क्वाड्रन से बनी आठवीं फाइटर विंग का एक एफ-16 विमान दिसंबर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इससे पहले 29 नवंबर को जापान के तट पर प्रशिक्षण के दौरान अमेरिकी वायु सेना का आस्प्रे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी।

समुद्री डाकुओं पर लगाम के लिए भारत ने किए कड़े इंतजाम

- लाल सागर के पूर्व में दर्जनभर युद्धपोत तैनात किए गए हैं
- दो महीनों में 250 से अधिक जहाजों की जांच की गई है

नई दिल्ली, रायटर : भारत ने समुद्री लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाल सागर के पूर्व में कम से कम एक दर्जन युद्धपोत तैनात किए हैं। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि 250 से अधिक जहाजों की जांच की गई है। यह कार्रवाई ईरान समर्थित हाउती के हमलों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

भारत लाल सागर के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाली टास्क फोर्स में शामिल नहीं हुआ है और वहां उसका कोई युद्धपोत नहीं है। अधिकारियों ने कहा, वर्तमान में उसके पास अदन की खाड़ी में दो अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत और उत्तरी और पश्चिमी अरब सागर में 10 युद्धपोत हैं। साथ ही निगरानी विमान भी हैं। उन्होंने कहा, क्षेत्र में भारत की यह सबसे बड़ी तैनाती है। इस क्षेत्र में अमेरिका, फ्रांस और चीन सहित अन्य देशों की नौसैनिक उपस्थिति हैं, पर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारत की उपस्थिति सबसे बड़ी है। भारतीय सैन्य और रक्षा अधिकारियों ने कहा, विशेष कमांडो सहित नौसेना कर्मियों ने पिछले दो माह में 250 से अधिक जहाजों और छोटी नौकाओं की जांच की है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि छह साल की अनुपस्थिति के बाद समुद्री डकैती की घटनाएं फिर से लौट आई हैं। उन्होंने कहा, एक दिसंबर से भारतीय नौसेना द्वारा अपहरण, अपहरण के प्रयास की कम से कम 17 घटनाएं दर्ज की गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत की बढ़ती क्षमता, हितों और प्रतिष्ठा के कारण कठिन परिस्थितियों में मदद की जरूरत है। उन्होंने मंगलवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि जब आसपास के देश में बुरी चीजें हो रही हों और हम कहें कि मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है तो हमें जिम्मेदार देश नहीं माना जाएगा।

रूसी सेना को बदनाम करने पर संपत्ति जब्त करने के विधेयक को मंजूरी

मास्को, एपी: रूसी संसद के निचले सदन ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी दी है जो सेना के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में दोषी ठहराए गए लोगों से धन, कीमती सामान और अन्य संपत्ति जब्त करने की अनुमति देगा। ऐसा माना जा रहा है कि प्रस्तावित कानून में जब्त की जा सकने वाली संपत्तियों में अचल संपत्ति शामिल नहीं है। इसके जल्द ही ऊपरी सदन में पारित होने और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

ड्यूमा स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने कहा है कि नया कानून उन लोगों पर लागू होगा जो सार्वजनिक रूप से चरमपंथी गतिविधियों को उकसाने या ऐसे कार्यों का आह्वान करने के दोषी हैं। साथ ही सशस्त्र बलों को बदनाम करेंगे। फरवरी 2022 में मास्को द्वारा यूक्रेन में सेना भेजने के बाद असहमति पर व्यापक सरकारी कार्रवाई के हिस्से के रूप में अपनाए गए कानून के तहत सशस्त्र बलों को बदनाम करना एक आपराधिक अपराध है।

****

सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा बने

- कुआलालंपुर में राष्ट्रीय महल में आयोजित समारोह में ली शपथ

कुआलालंपुर, एपी : मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहोर के सुल्तान इब्राहिम बुधवार को देश के 17वें राजा बने। उन्होंने कुआलालंपुर में राष्ट्रीय महल में एक समारोह में पद की शपथ ली। सुल्तान इब्राहिम की संपत्ति में रियल एस्टेट, खनन से लेकर दूरसंचार और पाम तेल तक के कई उद्यम शामिल हैं। उनके पास 300 से अधिक लक्जरी कारों का संग्रह, जिसमें एडाल्फ हिटलर द्वारा कथित तौर पर उपहार में दी गई एक कार भी शामिल है। सुनहरे और नीले रंग की बोइंग 737 सहित निजी जेट का एक बेड़ा भी शामिल है। उनके परिवार के पास एक निजी सेना भी है।

1957 में मलेशिया को ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रणाली के तहत नौ जातीय मलय राज्य शासकों ने बारी-बारी से पांच साल के लिए राजा के रूप में कार्यभार संभाला है। मलेशिया में 13 राज्य हैं, लेकिन केवल नौ में शाही परिवार हैं। सुल्तान इब्राहिम ने अल-सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह का स्थान लिया है, जो राजा के रूप में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने गृह राज्य पहांग का नेतृत्व करने के लिए लौट रहे हैं।

कुआलालंपुर में बुधवार को मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहोर के सुल्तान इब्राहिम ने देश के 17वें राजा के रूप में पद ग्रहण किया। रायटर

अब नेपाल को बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा भारत

काठमांडू, प्रेट्र: नेपाल बंदरों के आतंक से परेशान हैं। ऐसे में बंदरों की आबादी को नियंत्रित करने का तरीका जानने के लिए नेपाली सांसद और चिकित्सकों को दल भारत का दौरा करेगा।

हाल ही में कृषि, सहकारी व प्राकृतिक संसाधन समिति के सदस्यों ने संसदीय बैठकों में बंदरों के आतंक का मुद्दा उठाया। इस दौरान बंदरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए जरूरी आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके बाद संसदीय दल व चिकित्सकों के दल ने भारत आने का निर्णय लिया। नेपाली दल की यात्रा का भारत सरकार ने समर्थन किया है। दस पशु चिकित्सकों व पांच वन रेंजरों के साथ समिति बंधियाकरण के माध्यम से बंदरों की आबादी को नियंत्रत करने का तरीका जानने के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा करेगी। साल 2016 में पहली बार हिमाचल प्रदेश ने बंदरों को नाशक जीव घोषित किया। इसके बाद बंदरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए उन्हें मारने की अनुमति मिल गई।

टेस्ट कैप के लिए रजत और सरफराज में टक्कर

विशाखापत्तनम में इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को मिलेगा पदार्पण का मौका शुक्रवार से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट

नई दिल्ली, जेएनएन : विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के विरुद्ध शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच अंतिम एकादश में जगह बनाने के लिए रजत पाटीदार और सरफराज खान के बीच कड़ा मुकाबला है। इनमें से किसी एक बल्लेबाज को यहां पदार्पण करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि भारतीय टीम प्रबंधन किसे यह मौका देता है। शुरुआती दो टेस्ट मैचों में विराट कोहली के बाहर रहने के बावजूद भारत ने रजत को मौका नहीं दिया और उन्होंने विशेषज्ञ विकेटकीपर केएस भरत को खिलाने का विकल्प चुना। लेकिन अब रवींद्र जडेजा और केएल राहुल के चोटिल होने के बाद भारतीय प्रबंधन को दूसरे टेस्ट में बल्लेबाज को पदार्पण कराने के लिए मजबूर होना पड़ा है। विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच में वापसी करेंगे और पाटीदार व सरफराज के पास अपनी छाप छोड़ने का यह सुनहरा मौका होगा।

मध्य प्रदेश के 30 वर्षीय रजत पाटीदार भारत के लिए पिछले साल दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे खेल चुके हैं और कई लोगों का मानना है कि उनका टेस्ट पदार्पण भी लगभग तय है, विशेषकर भारत ए की ओर से 111 और 151 रन की पारी खेलने के बाद। हालांकि सरफराज ने भी इंग्लैंड लायंस के विरुद्ध 161 रन की पारी खेली थी और मध्यक्रम में वह रजत को पछाड़ सकते हैं।

विशाखापत्तनम में अगर एक बार फिर स्पिन की मददगार पिच मिलती है तो संभावना है कि भारतीय पिचों पर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में आंकड़े देखते हुए सरफराज को पाटीदार पर तरजीह दी जा सकती है। सरफराज ने 45 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 69.85 की औसत से 3912 रन बनाए हैं और उनके नाम 14 शतक और 11 अर्धशतक हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर अविजित 301 रहा है। वहीं पाटीदार ने 55 मैचों में 45.97 की औसत से 4000 रन बनाए हैं, जिनमें उनके नाम 12 शतक और 22 अर्धशतक हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 196 रन है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय पिचों पर सरफराज को बड़ी पारियां खेलने की आदत है।

पाटीदार के पक्ष में एक बात जा सकती है वह है उन्होंने आइपीएल में खुद को साबित किया है। उन्होंने दिखाय है कि भले ही उनके पास अंततरराष्ट्रीय अनुभव की कमी हो, लेकिन आइपीएल में उन्होंने परिपक्वता और टेंपरामेंट दिखाया है। वहीं सरफराज आइपीएल में चमक बिखेरने में विफल रहे हैं। मध्यक्रम में राहुल भारत के अनुभवी बल्लेबाज थे और अब उनके बाहर होने से भारत को अनुभव की जरूरत है, जो पाटीदार के पक्ष में काम कर सकता है। पाटीदार को ही विराट के विकल्प के रूप में चुना गया था।

सरफराज • फाइल फोटो, प्रेट्र
रजत • फाइल फोटो, प्रेट्र

रजत और सरफराज में से किसी एक का चुनना एक कठिन विकल्प होगा। वे टीम को मजबूती प्रदान करने वाले खिलाड़ी हैं। वे शानदार खिलाड़ी हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरा मानना है कि इस तरह के विकेटों पर वे वास्तव में टीम को मजबूती प्रदान करेंगे। अगर हमें उनमें से सिर्फ एक को चुनना होगा, तो निश्चित रूप से यह कठिन होगा। यह निर्णय मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा द्वारा किया जाएगा। - **विक्रम राठौड़**, बल्लेबाजी कोच, भारत

गिल-श्रेयस के साथ धैर्य रखने की जरूरत

विशाखापत्तनम, प्रेट्र : भारत के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ने बुधवार को कहा कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के बीच उनके साथ धैर्य रखना होगा। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को सलाह दी कि वे यहां दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की आक्रामकता से समझदारी से निपटें। भारतीय बल्लेबाजी कोच ने कहा, हमारी टीम में ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जिन्होंने काफी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। इसलिए हमें उनके साथ थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। गिल, यशस्वी और श्रेयस अंतत: बड़ी पारियां खेलेंगे, मुझे इसका यकीन है। राठौड़ने कहा कि जज्बे के साथ खेलने और आक्रामक क्रिकेट खेलने के बीच अंतर है।

स्पिनरों के विरुद्ध भारतीय बल्लेबाजों ने किया स्वीप, रिवर्स स्वीप का अभ्यास

विशाखापत्तनम, प्रेट्र : भारत के मौजूदा दौर के बल्लेबाजों को स्वीप शाट के लिए नहीं जाना जाता है लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम के खिलाड़ियों ने नेट सत्र में जम कर इस शाट का अभ्यास किया। कप्तान रोहित शर्मा को छोड़कर किसी अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआती टेस्ट में स्वीप शाट का सहारा नहीं लिया था। वहीं, इंग्लिश बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के विरुद्ध जमकर स्वीप और रिवर्स स्वीप शाट का इस्तेमाल किया था। दोपहर में टीम की शुरुआती नेट सत्र में लय तलाश रहे शुभमन गिल को स्वीप और रिवर्स स्वीप दोनों का अभ्यास करते देखा गया। रजत पाटीदार भी स्वीप और रिवर्स स्वीप का अभ्यास करते देखे गए। टीम में पहली बार शामिल हुए सरफराज खान को भी बल्लेबाजी अभ्यास करते देखा गया। वह और पाटीदार दोनों स्लिप में कैच का अभ्यास भी कर रहे थे।

जैक लीच ने नहीं किया अभ्यास, खेलना संदिग्ध

विशाखापत्तनम, प्रेट्र : इंग्लैंड के सबसे अनुभवी स्पिनर जैक लीच हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान घुटने में लगी चोट से पूरी तरह से उबरने में विफल रहे हैं जिससे उनका शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में खेलना संदिग्ध है। लीच ने बुधवार को टीम के साथ अभ्यास भी नहीं किया। उन्हें मैदान के बाहर फिजियो से इलाज कराते देखा गया।

हैदराबाद टेस्ट के पहले दिन क्षेत्ररक्षण करते समय लीच के बाएं घुटने में चोट लग गई थी। घुटने के आसपास चोट लगने से हुई सूजन और दर्द के बावजूद उन्होंने हैदराबाद टेस्ट की पहली पारी में 26 और दूसरी पारी में 10 ओवर की गेंदबाजी की थी। उन्हें बुधवार को अभ्यास सत्र के दौरान लंगड़ाते हुए देखा गया। लीच अगर चोट से उबरने में विफल रहे तो टीम में उनकी जगह आफ स्पिनर शोएब बशीर को मौका मिल सकता है। वीजा संबंधी समस्या के कारण बशीर

हैदराबाद में क्षेत्ररक्षण करते समय इंग्लिश स्पिनर को लगी थी चोट, लीच की जगह बशीर को मिल सकता है अवसर

देर से भारत पहुंचे थे और हैदराबाद टेस्ट में पदार्पण नहीं कर सके थे।

टीम के उनके साथी खिलाड़ी जैक क्रावले ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, लीच काफी मजबूत इंसान है। आप उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते है। आप वास्तव में उसे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम देखेंगे कि वह कुछ दिनों में कैसा करते हैं। क्रावले को भरोसा है कि अगर बशीर को मौका दिया गया तो वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

क्रावले बोले, बैजबाल हमारे अंदर नैसर्गिक रूप से : क्रावले ने कहा कि अति आक्रामक होकर खेलने के 'बैजबाल' शैली अपनाने के बाद से उनके साथी बेहतर खिलाड़ी बन गए हैं क्योंकि यह समय लेकर खेलने की रणनीति की तुलना में उनके प्राकृतिक खेल के अनुकूल है। बैजबाल हमारे अंदर नैसर्गिक रूप से आता है।

एक नजर में

श्रीकांत-मंजूनाथ थाइलैंड मास्टर्स के दूसरे दौर में पहुंचे

बैंकाक : भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत ने बुधवार को चीनी ताइपे के वैंग जू वेई को सीधे गेम में हराकर थाइलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बनाई। दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी श्रीकांत ने पहले दौर के मुकाबले में वैंग को 45 मिनट में 22-20 21-19 से हराया। श्रीकांत दूसरे दौर में हमवतन मिथुन मंजूनाथ से भिड़ेंगे, जिन्होंने पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में हांगकांग के जेसन गुनावन को 21-17 21-8 से हराया। (प्रेट्र)

ओलिंपिक उद्घाटन समारोह में दर्शकों की संख्या घटाई

पेरिस : पेरिस ओलिंपिक के उद्घाटन समारोह में दर्शकों की संख्या को 6,00,000 से घटाकर अब 3,00,000 लाख कर दिया गया है। फ्रांस के गृहमंत्री गेराल्ड डर्मेनिन ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उद्घाटन समारोह 26 जुलाई को सीन नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा और यह पहला अवसर होगा जब स्टेडियम के बाहर इसका आयोजन किया जाएगा। (प्रेट्र)

अखिल ने जीता कांस्य पदक

काहिरा : पेरिस ओलिंपिक कोटा प्राप्त कर चुके अखिल श्योराण ने बुधवार को पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कांस्य पदक जीतकर अपने करियर में दूसरी बार विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीता। अखिल ने आठ खिलाड़ियों के 45 निशाने के फाइनल में 451.8 का स्कोर किया। चेक गणराज्य के अनुभवी जिरी प्रिविरत्स्की ने 462.9 अंक के साथ स्वर्ण जबकि दो बार के विश्व चैम्पियन फ्रांस के रोमेन औफ्रेरे ने रजत पदक जीता। भारतीय निशानेबाजों ने दो स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। (प्रेट्र)

जय शाह लगातार तीसरी बार चुने गए एसीसी के अध्यक्ष

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीसीसीआइ के सचिव जय शाह को बुधवार को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) का अध्यक्ष चुना गया। शाह के कार्यकाल के विस्तार का प्रस्ताव बाली में वार्षिक आम बैठक के दौरान श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने रखा और एसीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नामांकन का समर्थन किया।

शाह सबसे पहले जनवरी 2021 में इस पद पर चुने गए थे। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह ली थी। शाह के नेतृत्व में एसीसी ने 2022 में टी-20 प्रारूप और 2023 में वनडे प्रारूप में एशिया कप का सफल आयोजन किया। फिर से अध्यक्ष

जय शाह • फाइल फोटो, प्रेट्र

चुने जाने पर शाह ने कहा, मैं एसीसी बोर्ड का मुझ पर विश्वास बनाए रखने के लिए आभारी हूं। हमें खेल के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के साथ उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए जहां यह अब भी अपनी शुरुआती अवस्था में है। एसीसी पूरे एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अश्विन नंबर एक टेस्ट गेंदबाज, बुमराह चौथे स्थान पर पहुंचे

दुबई, प्रेट्र : भारत के सीनियर आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आइसीसी रैंकिंग में नंबर एक टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। बुधवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में अश्विन 853 रेटिंग अंक के साथ पहले नंबर पर हैं। अश्विन ने इंग्लैंड के विरुद्ध पहले टेस्ट में छह विकेट लिए थे, जबकि बुमराह ने भी छह विकेट चटकाए थे। शीर्ष 10 गेंदबाजों में इन दोनों के अलावा रवींद्र जडेजा तीसरे भारतीय हैं। वह टेस्ट रैंकिंग में छठे नंबर पर हैं।

टेस्ट आलराउंडरों में जडेजा शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। अक्षर पटेल इस सूची में छठे स्थान पर खिसक गए हैं। दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली छठे स्थान के साथ शीर्ष 10 में अकेले भारतीय हैं।

तेंदुलकर ने तीसरे मैच में बनाया था अपना पहला रन

क्रिकेट डायरी

मुंबई, प्रेट्र : सचिन तेंदुलकर ने अपने दोस्तों को 'जीवन का पहला मैच' देखने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ा क्योंकि दुनिया का सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद अगले मैच में भी सचिन शून्य पर आउट हुए और जब तीसरे मैच में उन्होंने एक रन बनाया तो उन्हें इसकी अहमियत पता चली।

सचिन ने बुधवार को इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के एक कार्यक्रम में कहा, अपने पहले मैच में मैंने साहित्य सहवास के अपने सभी मित्रों को बुलाया था। मैं अपनी कालोनी का मुख्य बल्लेबाज था। मेरे सभी मित्र आए और मैं पहली गेंद पर आउट हो गया जो काफी निराशाजनक था।

दूसरे मैच में भी सभी आए और मैं फिर आउट हो गया। लेकिन तीसरे मैच में मैंने कहा कि मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मैं उनका समय बर्बाद कर रहा हूं। मैंने सोचा मैं अकेला जाऊंगा। तेंदुलकर ने कहा कि तब उन्होंने एक रन बनाने की अहमियत समझी। मैं गया और मैंने एक रन बनाया। मुझे याद है कि मैंने पांच-छह गेंद खेली और एक रन बनाकर आउट हुआ। लेकिन कहीं मैं खुश था, मैंने एक रन बनाया था। मैं शिवाजी पार्क से बांद्रा वापस गया। बस का यह सफर सुखद था क्योंकि मैंने एक रन बनाया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक जड़ने वाले इस एकमात्र बल्लेबाज ने कहा, मैंने एक रन बनाने की अहमियत महसूस की क्योंकि बाद में सभी कहते थे कि एक रन आप पर भारी पड़ सकता है, आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं।

यह इतना बड़ा बदलाव था। शुरुआती दो मैच में मैंने शून्य बनाया और फिर एक रन बनाया और घर चला गया। उस एक रन ने मेरा मूड बदल दिया।

अस्पताल से लौटते मयंक अग्रवाल • प्रेट्र

मयंक अग्रवाल की हालत में सुधार, अस्पताल से मिली छुट्टी

अगरतला : कर्नाटक के रणजी कप्तान मयंक अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि वह अब ठीक हैं और वापसी के लिए तैयार हैं। मंगलवार को मयंक को नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में पाउच से संदिग्ध तरल पदार्थ पीने के बाद अगरतला के अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराया गया था और बुधवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मयंक के मैनेजर ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मयंक अग्रवाल ने एक्स पर अपनी फोटो साझा करते हुए लिखा, मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, प्यार। इस बीच, कर्नाटक टीम के मैनेजर रमेश राव ने कहा कि मैं कर्नाटक क्रिकेट संघ और त्रिपुरा क्रिकेट संघ को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इलाज के दौरान मयंक का समर्थन किया। मयंक अब पूरी तरह ठीक हैं और हम बेंगलुरु के लिए जल्द रवाना होंगे।

विष्णु ने लगातार दूसरी बार ओलिंपिक में बनाई जगह

खेल डायरी

एडिलेड, प्रेट्र : एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता विष्णु सरवनन लगातार दो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय सेलर (पाल नौकायन खिलाड़ी) बन गए हैं। विष्णु ने बुधवार को विश्व चैंपियनशिप के जरिये पेरिस ओलिंपिक का टिकट कटाया। मुंबई स्थित सेना नौकायन नोड में सूबेदार 24 साल के सरवनन ने यहां आइएलसीए-7 विश्व चैंपियनशिप में 152 प्रतिभागियों के बीच 26वें स्थान पर रहते हुए पेरिस के लिए क्वालीफाई किया। वह पेरिस 2024 खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय पाल नौकायन खिलाड़ी हैं।

सरवनन एशियाई देशों के खिलाड़ियों के बीच शीर्ष पर रहे।

विष्णु सरवनन • एक्स

उन्होंने एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सिंगापुर के खिलाड़ी को पछाड़ा। सरवनन का कुल स्कोर 174 रहा। मानक नियमों के अनुसार इसमें से 49 के उनके न्यूनतम स्कोर को हटा दिया गया जिससे उनका नेट स्कोर 125 रहा। विष्णु 2019 अंडर-21 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता हैं।

खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेताओं को दी ट्राफी

नई दिल्ली, जेएनएन : केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के समापन समारोह में विजेताओं को ट्राफी प्रदान कीं। यूथ गेम्स में महाराष्ट्र कुल 158 पदक (57 स्वर्ण, 48 रजत, 53 कांस्य) जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु और हरियाणा ने 98 पदक (38 स्वर्ण, 21 रजत, 39 कांस्य) और 103 पदक (35 स्वर्ण, 22 रजत, 46 कांस्य) जीतकर क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं की शक्ति का उपयोग करने और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखलाने के लिए मंच प्रदान करना चाहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पिछले 13 दिनों के दौरान हमने जो देखा है, उससे मुझे बेहद गर्व हो रहा है। खेल हमारे युवाओं की प्रतिभा, समर्पण और अदम्य भावना का गौरवशाली प्रमाण हैं। मैंने एथलेटिक कौशल, खेल भावना और सौहार्द का प्रदर्शन देखा है जिसने मुझे गहराई से प्रेरित किया है।

विजेताओं को ट्राफी देते अनुराग ठाकुर •

मंजू ने 10 किलोमीटर पैदल चाल में जीता स्वर्ण

जासं, चंडीगढ़ : पंजाब की मंजू रानी ने राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को 10 किलोमीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की 20 किमी स्पर्धा में मंगलवार को स्वर्ण जीतने के एक दिन बाद उन्होंने 10 किमी स्पर्धा में अपना दबदबा बनाया। उन्होंने 2024 ओलिंपिक खेलों में पहली बार शामिल मिक्स्ड रिले पैदल चाल की टीम में जगह बनाने का दावा मजबूत किया। मंजू ने 45 मिनट और 20 सेकंड के समय के साथ 10 किमी स्पर्धा का शीर्ष स्थान प्राप्त किया। गोवा के ओंकार विश्वकर्मा ने पुरुषों के 35 किमी स्पर्धा को दो घंटे 39 मिनट और 19 सेकंड के समय के साथ जीता। महिला वर्ग में उप्र की बंदना पटेल तीन घंटे 11 मिनट छह सेकेंड के साथ विजयी रहीं।

रसेल के दम से जीता अबुधाबी

आइएलटी-20

गत चैंपियन गल्फ जायंट्स को छह विकेट से हराया, रसेल ने दो विकेट के बाद खेली तूफानी पारी

नई दिल्ली, जेएनएन : कैरेबियाई आलराउंडर आंद्रे रसेल ने अपनी मसल पावर दिखाते हुए अबुधाबी नाइटराइडर्स को गत चैंपियन गल्फ जायंट्स पर शानदार जीत दिलाई। जायंट्स ने बुधवार को आइएलटी-20 मुकाबले में क्रिस लिन (65) की अर्धशतकीय पारी के दम पर 161 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसे नाइटराइडर्स की टीम ने 10 गेंद शेष रहते ही प्राप्त कर लिया। जी फाइव व एंड पिक्चर्स पर प्रसारित मुकाबले में रसेल ने दो विकेट लेने के साथ ही सिर्फ 13 गेंदों में 30 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने तीन छक्के जड़े। रसेल के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज माइकल काइल पेपर ने 59 रन की शानदार पारी खेली।

इससे पहले, नाइटराइडर्स के कप्तान सुनील नरेन ने टास जीतकर गेंदबाजी चुनी और उनका यह निर्णय सही भी साबित होता दिखा, जब पहले ही ओवर में डेविड विली ने जैमी स्मिथ को आउट कर पवेलियन भेजा। इसके बाद चौथे ओवर में गल्फ के कप्तान जेम्स विंस इमाद वसीम का शिकार बने। टीम का स्कोर तब केवल 21 रन था, लेकिन इसके बाद लिन और काक्स ने टीम को स्थिरता दी और 13वें ओवर तक टीम का स्कोर 100 के करीब पहुंचा दिया था। लिन ने 48 गेंदों की अपनी पारी में तीन छक्के और छह चौके जड़े। इसके अलावा उन्होंने जार्डन काक्स (21) के साथ तीसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी भी की।

राष्ट्रीय फलक

जमीन मामले में अमर्त्य सेन के खिलाफ विश्वभारती का बेदखली नोटिस खारिज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बीरभूम जिले की अदालत ने भूमि विवाद मामले में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के खिलाफ विश्वभारती विश्वविद्यालय का बेदखली नोटिस खारिज कर दिया।

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अमर्त्य सेन के खिलाफ नोटिस जारी कर आरोप लगाया था कि उन्होंने 13 डिसमिल जमीन पर अतिरिक्त कब्जा कर रखा है। इस नोटिस के खिलाफ अमर्त्य सेन ने जिला न्यायालय में अपील की थी। बता दें कि अमर्त्य सेन के बोलपुर स्थित घर प्रतीची की सीमा से लगी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पूर्व कुलपति विद्युत चक्रवर्ती ने अमर्त्य सेन के खिलाफ जमीन हड़पने की शिकायत की थी। विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि कुल 1.25 एकड़ जमीन अमर्त्य के दिवंगत पिता आशुतोष सेन को पट्टे पर दी गई थी। अमर्त्य सेन ने कथित तौर पर 13 डिसमिल जमीन हथिया ली। हालांकि, राज्य सरकार ने कहा, 1.38 एकड़ जमीन का म्यूटेशन अमर्त्य सेन के नाम पर है। माना जा रहा है कि जिला अदालत के फैसले को विश्वविद्यालय प्रबंधन हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है।

न्यायिक अधिकारियों की गरिमा व प्रतिष्ठा बनाए रखने की जरूरत

- सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में वकील को दोषी बताते हुए टिप्पणी की
- तीन माह की सजा को अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक घटाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के आपराधिक अवमानना के मामले में एक वकील गुलशन बाजवा को दोषी ठहराते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों की गरिमा व प्रतिष्ठा बनाए रखने और उन्हें प्रायोजित व निराधार आरोपों से बचाने की जरूरत है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील के माफीनामे को खारिज करने का सही फैसला किया क्योंकि इसमें गंभीरता का अभाव था। साथ ही माफीनामा देर से दायर किया गया था और यह सिर्फ एक दिखावटी कदम था। शीर्ष अदालत ने वकील की उम्र और कई बीमारियों से पीड़ित होने की बात पर गौर करते हुए हाई कोर्ट द्वारा वकील को दी गई तीन महीने के कारावास की सजा को बदलकर 'अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक' कर दिया। गुलशन बाजवा ने 17 अगस्त, 2006 को एक मामले में पेश होने के दौरान हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष एक वकील को कथित तौर पर धमकी दी थी। जब उन्हें नोटिस जारी किया गया तो वह पेश नहीं हुए। इसके बाद बाजवा ने इसी मामले में अर्जी दाखिल कर हाई

कोर्ट के जजों पर आरोप लगाए थे। शीर्ष अदालत दिल्ली हाई कोर्ट के 2006 के फैसले के विरुद्ध बाजवा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि अवमाननापूर्ण कृत्य के संबंध में माफी में पछतावा दिखना चाहिए और इसका इस्तेमाल अपने अपराध के दोष से बचने के लिए नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष और यहां तक कि इस अदालत के समक्ष भी वकील का आचरण कानूनी व्यवस्था की अनदेखी करने वाला रहा।

अजमेर में पुलिस ने दो बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार

जासं, जयपुर : राजस्थान के अजमेर जिले में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर किराये के मकान में रह रहे दो बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है।

दरगाह बाजार पुलिस थानाधिकारी नरेन्द्र सिंह के अनुसार, महमूद अख्तर और नाहिद हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। सिंह ने बताया कि आरोपितों ने नाहिद शेख एवं नादिया शेख नाम से फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा था। आधार कार्ड में पता बंगाल के 24 परगना जिले का लिखा था। ये अजमेर में कपड़े का कारोबार कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर एजेंट को 15 हजार रुपये देकर वह भारतीय सीमा में घुसे थे। नाहिद ने बताया कि बांग्लादेश और भारत की सीमा के बीच कई एजेंट रहते हैं।

उल्लेखनीय है कि देश में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। ज्यादातर लोग बंगाल के रास्ते देश के दाखिल होते हैं। इसके बाद अन्य राज्यों में चले जाते हैं।

आपरेशन से आंख की रोशनी गंवाने वाले बुजुर्ग को 21 साल बाद न्याय

- सुप्रीम कोर्ट का दो लाख हर्जाना सालाना 12 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का फैसला
- दो महीने में भुगतान नहीं होने पर 15 प्रतिशत की दर से डाक्टर को देना होगा ब्याज

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने बाईं आंख के गलत आपरेशन से रोशनी जाने के 21 साल बाद 84 साल के एक बुजुर्ग को दो लाख रुपये का हर्जाना सालाना 12 प्रतिशत के ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पीड़ित को यह भुगतान दो माह के अंदर किए जाने का निर्देश दिया है।

जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की खंडपीठ ने आपरेशन करने वाले डा.आरपी सिंह पर जुर्माना अदा कर देने की झूठी जानकारी देने पर भी पचास हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। सारी धनराशि दोषी चिकित्सक को पीड़ित को देनी है। वर्ष 2002-2003 में जैन की आंख के आपरेशन में भारी चूक के चलते उनको उस आंख से दिखना बंद हो गया। चिकित्सक को दोषी मानते हुए वर्ष 2008 में फरीदाबाद की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जैन को दो लाख रुपये का मुआवजा सालाना 12 प्रतिशत के ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। यह राशि शिकायत दर्ज कराने की तारीख से लेकर फैसला आने तक की तारीख तक देना था। मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

में पहुंचा जहां ब्याज 12 से छह प्रतिशत कर दिया गया। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दोषी डाक्टर को दो माह के भीतर दो लाख रुपये व अब तक का ब्याज 12 प्रतिशत की दर से देने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर ब्याज दर 15 प्रतिशत हो जाएगी। इससे पहले, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की एथिक्स कमेटी ने सिंह को दोषी मानते हुए उनका नाम छह माह के लिए इंडियन मेडिकल रजिस्टर से हटा दिया था।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पीएम अवार्ड के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 12 फरवरी कर दी है। यह जानकारी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने एक्स पोस्ट में दी है।

केंद्र सरकार देशभर में बेहतर कार्य करने वाले लोक सेवकों को सम्मानित करती है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज दिवस पर प्रदान किया जाता है। 2023 के पुरस्कार के लिए दो श्रेणियों के तहत जिलों के समग्र विकास में लोक सेवकों के योगदान को पुरस्कृत करने के लिए मानक संशोधित किए गए हैं। पहली श्रेणी 12 प्राथमिकता क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत जिलों के समग्र विकास को शामिल किया गया है। इस श्रेणी में 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दूसरी श्रेणी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों व जिलों के लिए नवाचार' है और इस श्रेणी में छह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों के तहत लोक सेवकों को एक ट्राफी, प्रशस्ति पत्र और सम्मानित जिले अथवा संगठन को 20 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

****

दैनिक जागरण

सप्तरंग

तकनीक की दुनिया का

गुरुवार, 1 फरवरी, 2024

आज इंटरनेट के बिना रोजमर्रा का जीवन जहां कठिन होता जा रहा है, वहीं साइबर हमलों की आशंका भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वयं व स्वजनों के डाटा और डिवाइस को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इंटरनेट सुरक्षा नियमों को जानना बहुत आवश्यक हो गया है। कुछ ऐसे ही आनलाइन सुरक्षा उपायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र....

इंटरनेट से जुड़े जोखिम

- आइडेंटिटी थेफ्ट
- फेक वेबसाइट
- डाटा सेंध
- भ्रामक कंटेंट और जानकारी
- फिशिंग और ईमेल स्कैम
- आनलाइन और रोमांस स्कैम
- बुलिंग
- मालवेयर और वायरस
- गलत प्राइवेसी सेटिंग

सुरक्षित इंटरनेट दिवस (6 फरवरी)

आभासी दुनिया में सुरक्षा का सवाल

इंटरनेट आज की शैक्षणिक, व्यक्तिगत और पेशेवर जरूरतों का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इंटरनेट की दखल को इस तरह समझें कि आज कोई भी बच्चा बोलने और बात करना सीखने के पहले मोबाइल स्क्रीन को चलाना सीख जाता है। स्मार्ट डिवाइसेज और इंटरनेट के साथ जीवन की हो रही शुरुआत पढ़ाई, गेमिंग के आकर्षण से होते हुए कब हमें आभासी दुनिया का स्थायी उपयोगकर्ता बना देती है, हमें पता भी नहीं चलता। यह माध्यम हमारी जानकारियों, सूचनाओं, मनोरंजन, खरीदारी जैसे रोजमर्रा के कार्यों के लिए वन-स्टाप साल्यूशन बन गया है। आज 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स की संख्या के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश बन चुका है। इंटरनेट पर बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए आभासी दुनिया की सुरक्षा चिंताओं, साइबर खतरों के मद्देनजर हर किसी को अपने स्तर पर जागरूक होने की जरूरत है।

क्यों जरूरी है इंटरनेट सुरक्षा: इंटरनेट पर गतिविधियों और ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाए रखने की पहल को ही इंटरनेट सिक्योरिटी कहा जाता है। यह कंप्यूटर और साइबर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें ब्राउजर सिक्योरिटी, आनलाइन बर्ताव और नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे जोखिमों पर विशेष नजर होती है। हम प्रतिदिन घंटों आनलाइन गतिविधियों में बिताते हैं। इस दौरान हैकिंग (कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल अकाउंट या वेबसाइट का अनधिकृत एक्सेस), वायरस या मैलिसियस साफ्टवेयर और आइडेंटिटी थेफ्ट (निजी और वित्तीय जानकारियों में सेंध) जैसे खतरों को लेकर सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। व्यक्तिगत और संस्थागत तरीके से लागू होने वाले बचाव उपाय इंटरनेट सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं।

एआइ के दौर में साइबर की नई चुनौती: आनलाइन जोखिम से निपटने में वायरस प्रोटेक्शन साफ्टवेयर जैसे पारंपरिक बचाव उपाय एआइ के इस युग में कितने कारगर हैं, यह प्रश्न लगातार चिंताजनक होता जा रहा है। एआइ और साइबर सुरक्षा दोनों ही विषयों में नए टापिक प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, जिन पर निरंतर शोध और विकास की जरूरत है। हैलुसिनेशन एक ऐसी चुनौती है, जहां एआइ सिस्टम अवांछित या अशुद्ध परिणाम या जानकारी पेश करके बड़े पैमानों पर आम लोगों को भ्रमित कर सकता है। जटिल अल्गोरिदम और ट्रेनिंग डाटा में छेड़-छाड़ करके इस समस्या को और भी गंभीर बनाया जा सकता है। इस तरह की हेराफेरी से बौद्धिक संपदा में भी सेंध का जोखिम पहले से अधिक बढ़ गया है।

आनलाइन सुरक्षित रहने के तरीके

1. सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन : जब सार्वजनिक स्थान पर वाइ-फाइ कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, तो इसकी सिक्योरिटी पर आपका सीधा नियंत्रण नहीं होता। ऐसे में पब्लिक वाइ-फाइ में पर्सनल ट्रांजैक्शन, आनलाइन बैंकिंग या आनलाइन शापिंग से बचना चाहिए।

2. मल्टी फैक्टर आथेंटिकेशन : यह यूजर सत्यापन की ऐसी विधि है, जहां आनलाइन अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूजर को कोड आदि से वेरिफाई करना होता है। इसमें अकाउंट को वेरिफाइ करने के लिए फोन और ईमेल पर कोड भेजा जाता है। साथ ही फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमीट्रिक जानकारियों से भी अकाउंट का सत्यापन किया जाता है।

3. मजबूत पासवर्ड : एक ही पासवर्ड का अलग-अलग वेबसाइट पर प्रयोग कर आप खुद को खतरे में डालते हैं। इससे बचने के लिए लोअर, अपर केस, सिंबल और नंबर के साथ कठिन पासवर्ड तैयार करना चाहिए। मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग कर सकते हैं।

4. आपरेटिंग सिस्टम व साफ्टवेयर अपडेट : अपने उत्पादों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए डेवलपर लगातार नए खतरों को भांपते और सिक्योरिटी पैचेज जारी करते रहते हैं। आपरेटिंग सिस्टम और साफ्टवेयर के नवीनतम वर्जन का प्रयोग करने से आपको नए सिक्योरिटी पैचेज की सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ ही पेमेंट, हेल्थ या अन्य संवेदनशील जानकारियां इससे सुरक्षित रहती हैं।

5. संदिग्ध वेबसाइट और लिंक : कोई भी वेबसाइट, खासकर ई-कामर्स साइट पर एसएसएल/सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को जरूर देखें। यूआरएल में HTTP के बजाय हमेशा https को और एड्रेस बार में पैडलाक आइकन को अवश्य देखें। इसी तरह यदि किसी ईमेल या मैसेज में प्राप्त लिंक या अटैचमेंट को लेकर आश्वस्त नहीं है या वह संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, तो उस पर क्लिक करने से बचना चाहिए।

ई-किडनैपिंग से रहें सचेत

डा. प्रमोद दामले, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ

आजकल साइबर अपराधी लोगों को अलग-अलग तरीकों से अपने जाल में फंसा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड फ्राड, अवैध डिजिटल लोन, इनकम टैक्स रिफंड फ्राड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, जाब स्कैम और सेक्सटार्सन जैसे साइबर अपराधों की खबरें आए दिन चर्चा में रहती हैं। हाल में एक अलग तरह के अपराध साइबर किडनैपिंग की चर्चा रही। वर्चुअल किडनैपिंग या ई-किडनैपिंग में साइबर अपराधी यूजर की संवेदनशील जानकारियों में सेंध लगाकर फिरौती मांगने लगते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आभासी अपहरण इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होने लगता है कि पीड़ित के परिवार अपराधियों के सामने घुटने टेक देते हैं। पहला कारण है कि साइबर अपराधी के पास यूजर की सभी डिजिटल जानकारियां चली जाती हैं, जिसके बदले में वह गुमराह करने की कोशिश करता है। कई बार तो एआइ साफ्टवेयर के प्रयोग से आवाज और चेहरे में बदलाव कर दिया जाता है, जिससे सही और गलत के बीच भ्रम पैदा हो जाता है। स्वजनों को भ्रमित करने के लिए अपराधी अलग-अलग कुचक्र रचते हैं। धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें स्वप्न और वास्तविकता में जो फर्क है, इसे उसी तरह देखना चाहिए। किसी की कोई भी बात सच मान लेने से पहले उसके अलग-अलग पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। इसके अलावा, अगर कहीं कोई जल्दबाजी कर रहा है या उसकी बातों से झूठ का अंदेशा हो रहा है, तो उस पर सहजता से विश्वास करने से बचना चाहिए। साथ ही, इसकी पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। साइबर दुनिया के अपराधों से बचाव का सबसे बड़ा उपाय आपकी सतर्कता ही है।

वियरेबल टेक

वियरेबल टेक्नोलाजी हर दिन के साथ बदलती जा रही है। हेल्थ मानिटरिंग के लिए स्मार्टवाच की जगह अब स्मार्ट रिंग आ गई हैं, जो स्वास्थ्य गतिविधियों पर नजर रखती है। जानें कैसे कर सकते हैं इसका उपयोग...

स्मार्ट रिंग स्मार्टवाच का विकल्प!

आमतौर पर लोग अंगूठी को फैशन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन सोचिए यह रिंग स्मार्ट हो जाए तो। दरअसल, स्मार्टवाच की तरह ही अब स्मार्ट रिंग्स का दौर भी आ चुका है। इसमें लगभग वे सभी फिटनेस फीचर्स मिलते हैं, जो एक स्मार्टवाच में होते हैं। यह डिवाइस वियरेबल्स टेक की दुनिया बदल सकती है। हालांकि, यह डिवाइस कुछ वर्षों से हमारे बीच में मौजूद है। हाल ही में नाइज, बोट, अमेजफिट भारतीय बाजार में स्मार्ट रिंग लेकर आई हैं। सैमसंग ने भी गैलेक्सी रिंग का टीजर जारी किया है। देखा जाए, तो आने वाले दिनों में कई टेक कंपनियां स्मार्ट रिंग लाने की तैयारी में हैं।

स्मार्ट रिंग क्या है: छोटी अंगूठी की तरह दिखने वाला यह डिवाइस स्वास्थ्य की निगरानी कर सकता है। यह स्मार्टफोन जैसे अन्य स्मार्ट डिवाइस से कनेक्ट होकर काम करता है। यह वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकाल, जैसे-एनएफसी और ब्लूटूथ का उपयोग करता है। डिवाइस एडवांस सेंसर से लैस हैं, जो हृदय गति, ब्लड आक्सीजन लेवल, स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप्स के साथ-साथ स्ट्रेस लेवल आदि को भी मानिटर करता है। यहां डाटा को कनेक्टेड स्मार्टफोन एप पर देखा जा सकता है। कुछ स्मार्ट रिंग्स जेस्चर कंट्रोल और नोटिफिकेशन जैसी सुविधाओं के साथ आती है। उदाहरण के लिए अंगुली का एक हल्का झटका स्मार्टफोन की ब्राइटनेस कम करने या फिर प्लेलिस्ट को क्यू करने जैसे काम में मदद करता है। साथ ही, काल या मैसेज आता है, तो अंगुली पर हल्की आवाज बता देगी।

स्मार्ट रिंग क्या कर सकता है : सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह निरंतर स्वास्थ्य की निगरानी कर सकती है। हाल ही में भारतीय बाजार में लांच हुई बोट स्मार्ट रिंग स्मार्ट टच कंट्रोल के साथ आती है। इसमें स्वाइप नेविगेशन फीचर है। इससे म्यूजिक प्ले और पाज कर सकते हैं, ट्रैक बदल सकते हैं। इससे तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। बोट स्मार्ट रिंग हार्ट रेट मानिटर, एसपीओ2 सेंसर और बाडी टेंपरेचर मानिटर से लैस है। नाइज लूना रिंग में ट्रैकिंग के लिए एक पीपीजी सेंसर और 3-एक्सिस एक्सेलेरोमीटर की सुविधा है। कुछ स्मार्ट रिंग कांटैक्टलेस पेमेंट की सुविधा से लैस है। इसमें भुगतान करने के लिए टर्मिनल पर बस अपना हाथ घुमाना होता है। कुछ का स्मार्ट होम कंट्रोल जैसे कि लाइट बंद करने, थर्मोस्टेट को समायोजित करने, दरवाजा खोलने आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है।

नुकसान क्या हैं : अभी स्मार्ट रिंग डिस्प्ले नहीं है। इसलिए डिवाइस के साथ इंटरैक्शन भी सीमित है। स्मार्ट रिंग्स का उपयोग स्टैंडअलोन गैजेट के बजाय स्मार्टफोन के पूरक डिवाइस के रूप में किया जाता है। आनलाइन आर्डर करते समय सही फिट पाना भी चुनौती हो सकता है, क्योंकि अंगूठियों का आपकी अंगुली के सटीक आकार से मेल खाना जरूरी है। कंपनियां खरीदारी से पहले साइजिंग किट प्रदान करके समस्या कम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे खरीदारी में समय लगने के साथ परेशानी बढ़ जाती है। साथ ही, सही फिट की कोई गारंटी नहीं होती है।

-संतोष आनंद

वर्ग पहेली - 2531

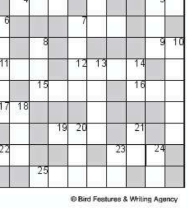

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं

2. सहन करने वाला (5)। 4. विपत्ति, आफत (3)। 5. देर, विलंब, एकफल (2)। 7. बंदर, मर्कट (3)। 9. शोरबा, स्वाद (2)। 11. दया, उपकार (3)। 12. रोकने का भाव (2,2)। 15. संगम, मिलन (4)। 16. उचित, सही (3)। 17. प्राण, जीवन, ताकत, बल (2)। 19. त्रेता एवं कलयुग के बीच का काल (3)। 22. गिलौरी, बीड़ा (2)। 23. पाचन की क्रिया करने वाला (3)। 25. एक फूलदार प्रसिद्ध वृक्ष (5)।

ऊपर से नीचे

1. सूर्य, दिनकर (2)। 2. हमेशा, सर्वदा (2)। 3. नया, नवल (3)। 5. बिना घर का (3)। 6. पेटी, बेल्ट (5)। 7. वायु का प्रकोप, एक प्रकार का रोग (2,2)। 8. अंधकार, अज्ञान (3)। 10. साधना का सहज मार्ग (5)। 13. दुर्बल (4)। 14. आनंद (2)। 18. सोच-विचार करना (3)। 20. शुरुआत (3)। 21. विचार करने का भाव (2)। 23. निकट, नजदीक (2)। 24. चित्र, नाट्य (2)।

कल का हल

स		ओ	पा	र		प	रा	थी	न
मा	ल	न		ज				र	
रो		ल		नी	म		का	ज	ल
ह					हा				च
		ओ	थ	म	रा		पा	ल	क
स	म	र्थ		र	ज	नी	श		
मा				घ					ओ
ज	ह	र		ट	न		श		व
	मा				ज		री	क्ष	स
क	म	नी	य		र	का	ब		र

जागरण सुडोकू-2531

8		2		3		6		5
				5			9	
9		5	4		7		2	
7			6	1		4		2
		6					1	
4				7				6
2	9		5			7	4	
		4			3		6	
6	8		1		4	5		9

कल का हल

3	1	5	7	6	4	2	8	9
6	9	8	1	5	2	3	4	7
7	4	2	8	9	3	5	6	1
8	6	3	9	4	7	1	2	5
4	2	7	5	8	1	6	9	3
1	5	9	3	2	6	4	7	8
2	3	1	6	7	9	8	5	4
5	7	4	2	3	8	9	1	6
9	8	6	4	1	5	7	3	2

आज का भविष्यफल- 01 फरवरी, 2024 गुरुवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : माघ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी। आज का राहुकाल : दोपहर 01 बजकर 30 मिनट से 03 : 00 बजे तक। दिशाशूल : दक्षिण। विशेष : मंगल उदय, बुध मकर राशि में। आज की भद्रा : दोपहर 02 बजकर 04 मिनट से 02 फरवरी को प्रात : 03 बजकर 04 मिनट तक।

कल 02 फरवरी, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : पश्चिम।
कल का पर्व एवं त्योहार : कालाष्टमी।
भद्रा : प्रात : 03 बजकर 04 मिनट तक।
विक्रम संवत 2080 शके 1945 उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु माघ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तत्पश्चात अष्टमी स्वाती नक्षत्र तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र सूल योग तत्पश्चात गंडयोग तुला में चंद्रमा।

- मेष : रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी।
- वृष : जीविका में प्रयास सार्थक होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- मिथुन : शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। सम्मान में वृद्धि होगी।
- कर्क : आर्थिक प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी।
- सिंह : पुरुषार्थ सार्थक होगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा।
- कन्या : आर्थिक प्रगति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।
- तुला : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होगा।
- वृश्चिक : कर्मक्षेत्र में बाधा आएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- धनु : शिक्षा में प्रयास सार्थक होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।
- मकर : महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी।
- कुंभ : आर्थिक मामलों में सुधार होगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।
- मीन : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। मन अशांत रहेगा।

राष्ट्रीय फलक

अजीत पवार से जुड़े 25 हजार करोड़ के घोटाला मामले में क्लोजर रिपोर्ट

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाला मामले में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। यह घोटाला 25 हजार करोड़ रुपये का है। वर्ष 2020 के बाद से यह दूसरी रिपोर्ट है।

ईओडब्ल्यू ने कहा है कि उसकी दूसरी जांच के दौरान भी कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया। लगभग डेढ़ साल पहले जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि वह मामले की दोबारा जांच कर रही है। ईओडब्ल्यू ने सितंबर 2020 में पहली क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। कोर्ट इस मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। 2019 में पवार और बैंक के पूर्व पदाधिकारियों सहित 70 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। यह घोटाला जिला और सहकारी बैंकों द्वारा मानदंडों का पालन किए बिना चीनी सहकारी समितियों, कताई मिलों और अन्य संस्थाओं को हजारों करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने से संबंधित है।

आइआइटी कानपुर में अब पीजी छात्र नहीं होंगे बर्खास्त

जासं, कानपुर

- संस्थान की ओर से प्रस्ताव पर अंतिम आदेश आने का इंतजार
- पीजी छात्रों ने कहा-यह नीति लागू होने से तनाव का स्तर भी घटेगा

आइआइटी कानपुर में एक माह में तीन आत्महत्याओं के बाद उच्चाधिकारियों ने स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रों को बर्खास्त न करने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब आइआइटी प्रशासन की ओर से प्रस्ताव पर अंतिम आदेश आने का इंतजार है। इससे आइआइटी में पीजी छात्रों के लिए 'शैक्षणिक रिकार्ड के आधार पर बर्खास्तगी नहीं' की नीति (नो टर्मिनेशन पालिसी) लागू हो जाएगी। अब तक यह नीति स्नातक छात्रों पर ही लागू है। पीजी छात्रों का कहना है कि यह नीति लागू होने से तनाव का स्तर भी घटेगा।

स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने संस्थान में तीन आत्महत्याओं के बाद धरना प्रदर्शन कर बर्खास्तगी नीति का विरोध किया था। डीन एकेडमिक्स प्रो. शलभ का कहना है कि सैद्धांतिक रूप से पीजी स्तर पर नो-टर्मिनेशन नीति लागू करने पर सहमति बनी है। इसमें किसी विद्यार्थी को शैक्षणिक रिकार्ड के आधार पर बर्खास्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ स्नातकोत्तर में ही नहीं, शोध छात्रों के शैक्षणिक कार्यभार को घटाते हुए छह पाठ्यक्रम को चार किया गया है। संस्थान छात्रों पर शैक्षणिक कार्य पूरा करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं देगा। संस्थान की ओर से पांच सदस्यीय समीक्षा समिति गठित कर छात्रों की समस्याओं को सुनने के बाद तुरंत हल करने की जिम्मेदारी दी गई है।

आइआइटी कानपुर। फाइल

बरात से भागे दूल्हे को पकड़ कर पुलिस ने करवाए फेरे

जासं, फतेहपुर : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बरात में डांस करने के दौरान विवाद के कारण बात इतनी बिगड़ गई कि दूल्हा कुछ बरातियों के साथ रात में ही गांव लौट गया। कन्या पक्ष की सूचना पर पुलिस रात में ही दूल्हे को उसके गांव से वापस लाई और शादी कराई।

ढकौली गांव से मंगलवार को बिंदकी कोतवाली के फरीदपुर मोड़ पर अक्शा मैरिज लान में बरात आई थी। अगवानी के दौरान नाचने के दौरान वर और वधू पक्ष में हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। बरातियों के साथ मारपीट से गुस्सा दूल्हे ने शादी से इन्कार कर दिया और कुछ बरातियों के साथ गांव लौट गया। दुल्हन के पिता ने जोनिहां पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी। चौकी इंचार्ज आलोक तिवारी विवाह स्थल पहुंचे और दोनों पक्ष के लोगों से बात की। उसके बाद दूल्हे को गांव से रात में ही वापस लाकर सभी रस्में संपन्न कराईं। बिंदकी कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार के मुताबिक दोनों पक्षों में समझौता कराकर विवाह संपन्न करा दिया गया।

मणिशंकर की बेटी के खिलाफ उतरी आरडब्ल्यूए सोसायटी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- मणिशंकर अय्यर की बेटी ने राम मंदिर निर्माण के विरोध में तीन दिन का उपवास रखा था
- सोसायटी ने नोटिस देकर मांगा जवाब, जवाब नहीं देने पर सोसायटी से निकालने की चेतावनी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी द्वारा राम मंदिर के विरोध में तीन दिन का उपवास रखने पर आरडब्ल्यूए सोसायटी उनके विरोध में उतर आई हैं। सोसायटी ने नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि यदि सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो उनको सोसायटी से निकाल दिया जाएगा। वह अपने राम मंदिर का अपमान सहन नहीं करेंगे।

मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर दिल्ली के जंगपुरा में रहती हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध किया। कहा कि वह मुस्लिमों के साथ अन्याय होता नहीं देख सकती। उनका समर्थन करते हुए राम मंदिर निर्माण के विरोध में तीन दिन का उपवास रख रही हैं। आरोप है कि कांग्रेस नेता की बेटी ने सनातन के खिलाफ अपशब्द सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रसारित किए थे, जिसके चलते उनकी सोसायटी की आरडब्ल्यूए विरोध में उतर आई हैं। सोसायटी के अध्यक्ष डा. कपिल कक्कड़ सहित व अन्य पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेता व उनकी बेटी को नोटिस भेजकर कहा कि वह सार्वजनिक रूप से अपने बयान के लिए माफी मांगें नहीं तो सोसायटी छोड़ कर जाएं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है और इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष डा. कपिल कक्कड़ ने कहा कि नोटिस का जवाब आने के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा और यदि जवाब नहीं आता हैं तो कांग्रेस नेता की बेटी को सोसायटी में नहीं रहने दिया जाएगा।

केरल में नाबालिग पोती से दुष्कर्म में 111 साल की सजा

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल की एक अदालत ने बुधवार को नाबालिग पोती से दुष्कर्म के मामले में 62 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 111 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि सजाएं एक साथ चलने के कारण दोषी को 30 साल जेल में काटने होंगे। कोर्ट ने दोषी पर 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दिसंबर 2021 में क्रिसमस की छुट्टियों में बालिका दादा के घर घूमने आई थी। इस दौरान वारदात को अंजाम दिया गया।

देश में कोविड के सब वैरिएंट जेएन1 के 2100 मामले दर्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में अब तक कोविड-19 के सब वैरिएंट जेएन1 व उसके वंशावली के 2,100 मामले दर्ज किए गए हैं। भारतीय एसएआरएस-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के अनुसार, अब तक देश में 245 मामले जेएन 1.11 और शेष मामले जेएन1 की उप-वंशावली के पाए गए हैं। गत माह केंद्र ने देश में नए वैरिएंट का पता लगने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगातार निगरानी बनाए रखने को कहा था।

थानेदार को हटवाने के लिए बजरंग दल पदाधिकारी ने कराए थे गोवध

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

- बजरंग दल के जिला प्रमुख सहित आरोपित चार गिरफ्तार
- गोवध के बाद समर्थकों के साथ खुद भी करता था धरना-प्रदर्शन

उप्र के मुरादाबाद जिले में थानेदार को हटवाने के लिए बजरंग दल के जिला प्रमुख ने ही दो बार गोवध करवाया। पुलिस पर आरोप लगाते हुए खुद समर्थकों के साथ धरना-प्रदर्शन किया। आरोपितों ने ही घटना के बाद गाय काटने का वीडियो बनाकर अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। पुलिस ने मुख्य आरोपित बजरंग दल के जिला प्रमुख समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि छजलैट में 16 जनवरी को गोवंशीय के अवशेष मिले थे। 28 जनवरी की रात जंगल में फिर गोवध की घटना हुई। इसका वीडियो बनाकर जिलाधिकारी को एक्स पर भेजकर कार्रवाई की मांग की गई। इस पर जांच के लिए टीम गठित की गई। पुलिस ने जांच के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में बताया कि रसूलपुर छज्जूपुर निवासी सुमित विश्नोई उर्फ मोनू बजरंग दल का जिला प्रमुख है। कुछ दिन पहले वह अपने साथी रमन और राजीव के साथ मिला था। कहा, छजलैट थाना प्रभारी को हटवाने के लिए गोवध की घटनाएं करनी हैं। दो हजार रुपये भी दिए। इसके बाद शहाबुद्दीन ने साथी नईम को रुपये देकर गोवंशीय पशु के अवशेष कांवड़ पथ पर रखवाए थे। इसके बाद सुमित ने थानेदार को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। कार्रवाई नहीं होने पर दोबारा साजिश रची। 28 जनवरी की रात शहाबुद्दीन ने जमशेद के साथ मिलकर गाय चोरी की और जंगल में उसे काट दिया। सुमित और उसके साथियों ने गाय काटते हुए वीडियो बनाया। इसके बाद उसे उच्च अधिकारियों के एक्स अकाउंट में ट्वीट करते हुए शिकायत की। जांच में आरोपितों से मिलीभगत में दारोगा नरेन्द्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आरोपित जमशेद व नईम फरार है।

बीएसएफ ने पंजाब में सीमा पर दबोचे चार तस्कर, पाकिस्तान से मंगवाते थे हेरोइन

जागरण संवाददाता, अमृतसर

सीमा पार से आए ड्रोन से गिराया सामान उठाने पहुंचे थे, दो फरार

बीएसएफ ने पाकिस्तान से नशीला पदार्थ व हथियार मंगवाने वाले चार तस्करों को पकड़ा है। उनके कब्जे से पिस्तौल, हेरोइन, आइस ड्रग (क्रिस्टल मेथएंफेटामाइन) सहित ड्रग मनी व स्कूटर बरामद किया गया है। मामले की जांच नारकोटिक्स ब्यूरो को सौंपी गई है।

जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए तस्कर पाकिस्तान में बैठे तस्कर राणा व उसके भाई साहा के संपर्क में थे और उन्हीं से नशीला पदार्थ व हथियार मंगवाते थे। बताते हैं कि बीएसएफ व खुफिया एजेंसियां इस पर नजर रखे हुए थीं कि सीमा पार से हेरोइन व ड्रोन को लेने कौन आ रहा है। बुधवार को सीमावर्ती क्षेत्र में एक ड्रोन की गतिविधि हुई। कुछ देर बाद चार लोग उक्त ड्रोन की ओर जाते दिखे। जवानों ने घेराबंदी करके उन्हें दबोच लिया। तलाशी में उनसे एक पिस्तौल, चार कारतूस, 4.369 किलोग्राम हेरोइन, 968 ग्राम मादक पदार्थ आइस, 70 हजार 140 रुपये ड्रग मनी और एक स्कूटर बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि उनके दो साथी और हैं, जो फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने स्वीकारा है कि उनका संपर्क सीमा पार के कुख्यात तस्कर राणा व उसके भाई और साहा से है। इनकी काल डिटेल से पता चला है कि ये लोग राणा व साहा से वीडियो काल के माध्यम से बातचीत करते थे। इस बीच, तरनतारन के भिखीविंड बीएसएफ जवानों ने मंगलवार रात एक ड्रोन गिरा दिया। एसएसपी अश्विनी कपूर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

तस्करों से बरामद, हेरोइन, पिस्टल व आईसी। सौ. बीएसएफ

सजा से बचने को इत्र कारोबारी ने 23 किलो सोने पर छोड़ा दावा

जासं, कानपुर

- पीयूष जैन के घर और कारोबारी स्थलों से बरामद हुए थे 196 करोड़ रुपये और 23 किलो सोना
- कारोबारी ने अपील वापस लेकर अदालत में दी अर्जी, अभियोजन सात को दाखिल करेगा जवाब

करीब तीन साल पहले घर और कारोबारी स्थलों से बरामद 23 किलो सोने पर कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने दावा छोड़ दिया है। सजा से बचने के लिए उन्होंने यह पैंतरा अपनाया है। सोने पर दावे वाली अपील भी उन्होंने वापस ले ली। अदालत में अर्जी देकर इस मामले में राहत देने की गुहार लगाई है। अभियोजन अब सात फरवरी को इस पर अपना जवाब दाखिल करेगा।

महानिदेशालय जीएसटी इंटेलीजेंस अहमदाबाद की टीम ने गुजरात में पान मसाला लदा ट्रक पकड़ा था, इसमें कर चोरी उजागर हुई थी। टीम ने पान मसाला कारोबारी और ट्रांसपोर्टर के यहां छानबीन की। 21 दिसंबर, 2021 को पीयूष जैन के कानपुर में आनंदपुरी व कन्नौज स्थित घर व कारोबारी स्थलों पर छापे मारे। वहां से 196 करोड़ रुपये की नकदी और 23 किलो सोना पकड़ा गया था। 27 दिसंबर 2021 को पीयूष को जेल भेज दिया गया। आठ माह बाद उन्हें जमानत मिली थी। सोना बरामदगी में पीयूष पर कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दाखिल किया गया था। विदेशी मार्का सोना बरामद होने से लखनऊ के एडिशनल कमिश्नर कस्टम ने नौ अप्रैल, 2023 को 30 लाख रुपये पीयूष जैन और 30 लाख रुपये उसकी फर्म ओडोकैम पर जुर्माना लगाया था। पीयूष ने जुर्माना जमा कर दिया। इसके बाद लखनऊ में कस्टम कमिश्नर के यहां सोने पर दावा करते हुए गलत तरीके से जब्त करने की बात कही थी। विशेष लोक अभियोजक अंबरीष टंडन ने बताया कि पीयूष जैन ने 12 दिसंबर, 2023 को चीफ कमिश्नर कस्टम के यहां प्रार्थनापत्र देकर सोने पर दावा छोड़ते हुए मुकदमा न चलाए जाने की अर्जी दी है।

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 1 फरवरी, 2024
आजकल
14
www.jagran.com

अंतरिक्ष से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ कोलंबिया शटल यान

2003 में आज ही 'स्पेस शटल कोलंबिया' अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह पहला अंतरिक्ष यान था जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें सवार पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित सभी सात की मृत्यु हो गई।

हेवलेट पैकर्ड ने पेश किया दुनिया का पहला पाकेट कैलकुलेटर

1972 में आज ही के दिन अमेरिकी कंपनी हेवलेट पैकर्ड ने दुनिया का पहला हाथ में आसानी से पकड़ में आने वाला कैलकुलेटर एचपी-35 पेश किया था। इसकी कीमत उस समय 395 डालर थी। 35 बटन वाला यह कैलकुलेटर जल्दी ही पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया।

50 वर्ष की उम्र के बाद एके हंगल ने की थी सिनेमा में शुरुआत

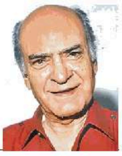

प्रसिद्ध अभिनेता एके हंगल का जन्म 1914 में आज ही के दिन सियालकोट (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। बचपन से ही अभिनय में रुचि लेने लगे। बड़े होकर दर्जी बने। साथ ही थिएटर से भी जुड़े रहे। 1966 में 52 वर्ष की उम्र में तीसरी कसम फिल्म से बालीवुड में अपनी शुरुआत की। 1975 में शोले में उनके द्वारा निभाया गया रहीम चाचा का किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी कुछ अन्य यादगार फिल्मों में नमक हराम, बावर्ची, छिपा रुस्तम और गुड्डी शामिल हैं। 26 अगस्त, 2012 को उनका निधन हो गया।

लगातार पढ़ते रहने से मृत्यु का जोखिम होता है कम

स्कूल या विश्वविद्यालय में बिताया गया प्रत्येक वर्ष जीवन प्रत्याशा में सुधार कर सकता है, शोध लैंसेट में प्रकाशित

एनटीएनयू के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन, लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित हुआ शोध

59 देशों के डाटा की पहचान की, 600 से अधिक लेखों से एकत्र किए 10,000 से अधिक बिंदुओं को किया शामिल

अच्छे जीवन के लिए शिक्षा जरूरी। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र: लैंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, स्कूल या विश्वविद्यालय में बिताया गया हर साल जीवन प्रत्याशा में सुधार कर सकता है, जबकि शैक्षणिक संस्थान में न जाना धूम्रपान या भारी शराब पीने जितना ही बुरा हो सकता है। शोध में 59 देशों के डाटा की पहचान की गई और 600 से अधिक प्रकाशित लेखों से एकत्र किए गए 10,000 से अधिक डाटा बिंदुओं को शामिल किया गया। उन्होंने पाया कि शिक्षा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के साथ मृत्यु का जोखिम 2 प्रतिशत कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने प्राथमिक विद्यालय के छह साल पूरे कर लिए, उनमें मृत्यु का जोखिम औसतन 13 प्रतिशत कम था। नार्वेजियन यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी (एनटीएनयू) के शोधकर्ताओं सहित टीम ने पाया कि शिक्षा उम्र, लिंग, स्थान और सामाजिक और जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना जीवन बचाती है। उन्होंने पाया कि शिक्षा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के साथ मृत्यु का जोखिम 2 प्रतिशत कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने प्राथमिक विद्यालय के छह साल पूरे कर लिए, उनमें मृत्यु का जोखिम औसतन 13 प्रतिशत कम था। माध्यमिक विद्यालय से स्नातक होने के बाद मरने का जोखिम लगभग 25 प्रतिशत कम हो गया और 18 साल की शिक्षा ने जोखिम को 34 प्रतिशत कम कर दिया। सह लेखक टेर्जे एंड्रियास ईकेमो ने कहा, 'शिक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण है, न केवल स्वास्थ्य पर लाभों के लिए, बल्कि इसकी मात्रा निर्धारित करने में सक्षम होना अहम विकास है।''

18 साल तक शिक्षा की तुलना आदर्श मात्रा में सब्जियां खाने जैसा

- अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने शिक्षा के प्रभावों की तुलना अन्य जोखिम कारकों जैसे कि स्वस्थ आहार, धूम्रपान और बहुत अधिक शराब पीने से भी की। उन्होंने पाया कि स्वास्थ्य परिणाम समान हैं। उदाहरण के लिए, 18 साल की शिक्षा के लाभ की तुलना आदर्श मात्रा में सब्जियां खाने से की जा सकती है।
- शोधकर्ताओं ने कहा कि स्कूल न जाना उतना ही बुरा है जितना कि प्रति दिन पांच या अधिक मादक पेय पीना या दस साल तक प्रति दिन दस सिगरेट पीना।
- शोधकर्ताओं ने कहा कि जहां शिक्षा के लाभ युवा लोगों के लिए सबसे अधिक हैं, वहीं 50 और यहां तक कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अभी भी शिक्षा के सुरक्षात्मक प्रभावों से लाभान्वित होते हैं।
- नार्वेजियन यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी (एनटीएनयू) के शोधकर्ताओं सहित टीम ने पाया कि शिक्षा उम्र, लिंग, स्थान और सामाजिक और जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना जीवन बचाती है। माध्यमिक विद्यालय से स्नातक होने के बाद मरने का जोखिम लगभग 25 प्रतिशत कम हो गया और 18 साल की शिक्षा ने जोखिम को 34 प्रतिशत कम कर दिया।
- शोधकर्ताओं ने शिक्षा के प्रभावों की तुलना अन्य जोखिम कारकों जैसे कि स्वस्थ आहार, धूम्रपान और बहुत अधिक शराब पीने से भी की और उन्होंने पाया कि स्वास्थ्य परिणाम समान हैं।

दुर्लभ रेड हैंडफिश पर जलवायु परिवर्तन का असर

आस्ट्रेलिया के तस्मानिया स्टेट में स्थित समुद्र में तैरती लुप्तप्राय प्रजाति की रेड हैंडफिश। समुद्र के बढ़ते तापमान, मानवजनित आवास परिवर्तनों और प्रदूषण के कारण रेड हैंडफिश के जीवन पर संकट लगातार गहरा रहा है। तस्मानिया यूनिवर्सिटी के समुद्री और अंटार्कटिक स्टडीज सेंटर ने जारी रिपोर्ट में कहा है कि समुद्र से पच्चीस से अधिक दुर्लभ मछलियों को संरक्षित किया जा रहा है। सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में खतरों के प्रति भी आगाह किया है। एएफपी

इधर-उधर की

इटली में दिया गया कुत्तों के डीएनए परीक्षण का आदेश

रोम, एजेंसी: सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों के मल से फैल रही गंदगी से निजात पाने के लिए उत्तरी इतालवी प्रांत में अधिकारियों ने अनोखी तरकीब निकाली है। प्रशासन ने कुत्ते के मालिकों को अपने पालतू जानवरों के डीएनए का नमूना देने का आदेश दिया है। सरकार 40 हजार कुत्तों के लिए एक डाटाबेस स्थापित कर रही है। 10 हजार कुत्तों का पंजीकरण हो चुका है। इसके तहत छोड़े गए मल का आनुवंशिक रूप से परीक्षण कर कुत्ते और मालिक का पता लगाया जाएगा और मालिक पर 50 से 500 यूरो तक जुर्माना लगाया जाएगा। बोल्जानो शहर में कुत्तों के मल से फैल रही गंदगी के बाद यह निर्णय लिया गया।

कुत्तों से फैल रही गंदगी को देखते हुए उठाया कदम ● इंटरनेट मीडिया

अवसादरोधी दवा केटामाइन से मस्तिष्क में मिले सूक्ष्म परिवर्तन

अमित तिवारी, मेरठ

मानव मस्तिष्क पर कोलंबिया विश्वविद्यालय में लंबे समय से शोध कर रहे न्यूरोसाइंटिटिस प्रोफेसर राजू तोमर ने अवसादरोधी दवा केटामाइन के असर पर नए निष्कर्ष निकाले हैं। मानसिक रोगियों पर इस दवा के संतुलित मात्रा में प्रयोग करने पर जहां डोपामिन बढ़ने से उनकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, वहीं मेटाबोलिज्म भी ठीक रहेगा। हालांकि, लिंक बिगड़ने से व्यक्ति पर स्क्रिजनोफ्रेरिया का भी रिस्क मिला।

यह शोध जर्नल सेल रिपोर्ट्स के ताजा अंक में प्रकाशित हुआ है। मेरठ निवासी राजू तोमर कोलंबिया विश्वविद्यालय में न्यूरोसाइंसटिस्ट हैं। उन्होंने चूहों के मस्तिष्क पर दस दिनों तक केटामाइन दवा का प्रयोग कर निष्कर्ष निकाला कि डोपामाइन प्रणाली में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों बदलाव हुए। मस्तिष्क के श्रवण और दृश्य सूचना संसाधन यानी विजुअल इन्फार्मेशन प्रोसेसिंग के बीच असंतुलन का रिस्क दिखा।

- **डोपामिन की मात्रा बढ़ने से निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, वहीं असंतुलन से मरीज में स्क्रिजनोफ्रेरिया का भी खतरा**

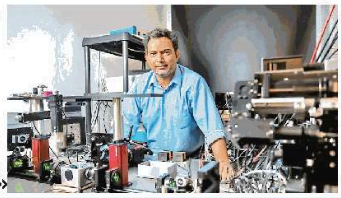

कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला में प्रोफेसर राजू तोमर। सौ. स्वयं

केटामाइन की तय डोज लंबे समय तक लेने से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सकारात्मक एवं नकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा। मस्तिष्क के कई क्षेत्रों में डोपामिन की मात्रा बढ़ने से सोचने, निर्णय लेने एवं प्रसन्न रहने से जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। हालांकि कुछ नुकसान भी दिखे हैं।
-प्रोफेसर राजू तोमर, न्यूरोसाइंटिस्ट

विश्वभर में मिली प्रशंसा व पहचान

प्रो तोमर ने मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र में केटामाइन द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म परिवर्तनों की व्यवस्थित जांच यानी उच्च रेज्यूलेशन मस्तिष्क इमेजिंग के लिए नए उपकरण विकसित किया। 100 टेराबाइट डेटा विश्लेषण के लिए उन्नत विधि अपनाई। दवाइयों के कारण मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन असमान मिले, जो विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। प्रोफेसर तोमर के शोध को अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ ने समर्थन दिया है। एल्टमेट्रिक वेबसाइट ने समान क्षेत्र के शोध लेखों में इसे शीर्ष एक प्रतिशत और 2.5 करोड़ से अधिक अनुसंधान लेखों में शीर्ष पांच प्रतिशत में स्थान दिया है।

हाई डोज केटामइन है जानलेवा

केटामाइन अवसाद में त्वरित राहत के लिए दर्द निवारक अथवा एनेस्थेटिक की तरह लिया जाता है। हाल में अमेरिका की चर्चित फ्रेंड्स सीरीज के स्टार कलाकार मैथ्यू पेरी का निधन केटामाइन के हाइडोज और उसके बाद डूबने से हुई। केटामाइन का प्रयोग सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी से जुड़ा है। केटामाइन को लेकर किया गया प्रोफेसर राजू तोमर का शोध मस्तिष्क पर अवसादरोधी दवा के जटिल प्रभाव को समझने और न्यूरोलाजिकल विकारों के लिए प्रभावी उपचार विकसित करने में सहायक होगा।

शाकाहार से जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली होती है मजबूत

अनुसंधान

शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया है कि शाकाहार से जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। यानी व्यक्ति जिस प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ पैदा हुआ है उसे बढ़ावा मिलता है। दूसरी ओर, यह यह भी पाया कि कीटोजेनिक आहार यानी कम कार्बोहाइड्रेट और अधिक बसा वाले खाद्य पदार्थ भी समय के साथ विकसित प्रतिरक्षा प्रणाली में तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। जो बाह्य संक्रमण पर वैक्सीनेशन की तरह बचाव करता है।

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ ने जांच में पाया कि इससे आंत माइक्रोबायोम में भी बदलाव हुआ। शोधकर्ताओं का यह निष्कर्ष नेचर मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। शोध दल ने अध्ययन के लिए दो सप्ताह तक 20 प्रतिभागियों में विभिन्न जैविक प्रतिक्रयाओं की निगरानी की। उन्होंने प्रतिभागियों को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया। जिन्हें वीगन (शाकाहार) और कीटो आहार दिया गया। शोध दल ने माइक्रोबायोम में बदलाव के साथ शरीर में जैवरासायनिक सेल्युलर, मेटाबोलिक और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया। शोध दल ने पाया कि कीटो आहार ने रक्त में प्रोटीन, रक्त प्लाज्मा और मस्तिष्क और अस्थि मज्जा को शाकाहार की तुलना में अधिक प्रभावित किया। शोध दल ने कहा कि हालांकि इसमें अभी और अध्ययन की जरूरत है। अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि ये आहार प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसा प्रभाव डालते हैं। जिसमें स्वास्थ्य में सुधार के लिए आहार में बदलाव शामिल है, विशेष रूप से कैंसर या सूजन की स्थिति जैसी बीमारियों के संदर्भ में। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

बीना का रोल निभाने से पहले यह लाइनें याद करती हैं रसिका

मिर्जापुर वेब सीरीज में गृहणी बीना के रोल में हैं रसिका। (इंस्टाग्राम) @rasikadugal

कई बार सराहना प्रेरणा का भी काम कर जाती है। अभिनेत्री रसिका दुग्गल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उन्हें मिर्जापुर में उनके रोल के लिए सराहना मिली। उस दौरान रसिका के बारे में कही गई कुछ लाइनें उन्हें इतनी याद रह गई कि उसकी वजह से उनकी परफार्मेंस में बदलाव आ गया। मिर्जापुर 3 की शूटिंग रसिका पूरी कर चुकी हैं। इस शो में वह गृहणी बीना त्रिपाठी की भूमिका में हैं। वह कहती हैं कि मैंने इस रोल के लिए कभी कोई खास तैयारी नहीं की थी। ना इसके लिए तैयारी की जा सकती थी, क्योंकि मिर्जापुर का हर पात्र समय के साथ बदल रहा है। इस शो के सीजन के बीच का जो सफर रहा है, वह बदलाव से भरा था। कलाकारों को भी उसके अनुसार खुद को ढालना पड़ रहा था। बीना का पात्र बहुत ही दिलचस्प रहा है। यह बात सच है कि अगले सीजन की शूटिंग पर लौटने से पहले कई बार लगता है कि कहीं मैं बीना को भूल तो नहीं गई। इसके लिए मैं शो की लेखकों की टीम को श्रेय देना चाहूंगी, क्योंकि बीना को हर बार समझने में उनके लेखन ने मेरी मदद की है। एक बार शो के लेखक पुनीत कृष्ण ने मुझे कहा था कि आपने बीना का रोल पूरी गरिमा के साथ निभाया है। तब से हर सीजन से पहले मैं उनकी उस सराहना को याद करती हूं कि इस रोल को पूरी गरिमा के साथ निभाना है।

केवल अभिनय करने ही नहीं आया था : अभिषेक बनर्जी

स्त्री 2 में फिर जना की भूमिका में होंगे अभिषेक। (इंस्टाग्राम) @nowitsabhi

अभिनय की दुनिया ऐसी है, जहां जरूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आसानी से मिल ही जाए। ऐसे में कई कलाकार हैं, जो अभिनय के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाकर रखते हैं। स्त्री फिल्म और पाताल लोक वेब सीरीज में अभिनय के अलग रंग दिखा चुके अभिनेता अभिषक बनर्जी अभिनेता के साथ कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यही वजह है कि वह अलग तरह के रोल में खुद को आजमाने का जोखिम ले पाते हैं? इस पर अभिषेक कहते हैं कि कास्टिंग डायरेक्शन करना भी उतना ही जोखिम भरा काम है, जितना अभिनय। जब मैंने शुरुआत की थी, तो कोई मुझे जानता नहीं था। मुझ पर लोग संदेह करते थे कि यह नया लड़का क्या कलाकार ढूंढकर ला पाएगा। लेकिन मैं साबित करता गया। यह इसलिए हो पाया, क्योंकि मुझे सिनेमा से प्यार है। कास्टिंग छोड़कर मुझे फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए, तो भी मैं हर जगह काम कर लूंगा। मैं फिल्म इंडस्ट्री में केवल अभिनय करने ही नहीं आया था। अभिनेता तो बनना ही था लेकिन मैं फिल्म के हर डिपार्टमेंट में योगदान देना चाहता हूं।

पति रोहित की नई भूमिका को लेकर उत्साहित हैं मानसी

अभिनय के साथ कंटेंट निर्माण में भी सक्रिय रहेंगी मानसी (इंस्टाग्राम)@ manasijoshiroy

अजय देवगन, सनी देओल और रणदीप हुडा समेत हिंदी सिनेमा में ऐसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने अभिनय के साथ-साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाया है। शूटआउट एट लोखंडवाला, काबिल और मुंबई सागा फिल्मों के अभिनेता रोहित राय भी निर्देशन में कदम रखने के लिए तैयार हैं। वह अपने निर्देशन की पारी एक वेब सीरीज से शुरू करेंगे। उनकी इन नई पारी को लेकर उनकी पत्नी तथा अभिनेत्री मानसी जोशी भी काफी उत्साहित हैं। मानसी का कहना है, 'जल्द ही आप उन्हें निर्देशक की नई भूमिका में देखेंगे। हम जल्द ही एक ऐसे प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाले हैं, जिसे मैं प्रोड्यूस करूंगी और रोहित उसका निर्देशन करेंगे। मैं रोहित के इस नई पारी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। मुझे पता है कि वह कैमरे से सामने जितने बेहतरीन कलाकार हैं, कैमरे के पीछे भी उतने ही बेहतर काम करते हैं। इसके बाद हम एक फिल्म भी बनाने वाले हैं, बातें फिल्म और शो दोनों को लेकर चल रही हैं। पहले शो बनाएंगे, फिर देखते हैं कि फिल्म का क्या होता है? रही बात रोहित की तो उनके प्रयोग चालू रहेंगे, आप उन्हें नई-नई भूमिकाओं में देखते रहेंगे।'

नो एंट्री की सीक्वल में होगी तीन नए सितारों की एंट्री

साल 2005 में प्रदर्शित सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान अभिनीत फिल्म नो एंट्री की सीक्वल की चर्चा सिनेमाई गलियारों में पिछले काफी समय से चल रही है। फिल्म के निर्देशक अनीस बज्मी ने तो साल 2019 में प्रदर्शित फिल्म पागलपंती के प्रमोशन के दौरान कह दिया था कि नो एंट्री की सीक्वल की कहानी तैयार है। हालांकि, उसके बाद फिल्म में बदलाव से जुड़ी कई खबरें सामने आई, लेकिन अब तक इस फिल्म की शूटिंग नहीं शुरु हो पाई है। दैनिक जागरण से बातचीत में अनीस ने बताया था कि वह सलमान खान की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिना सलमान के नो एंट्री की सीक्वल नहीं बन सकती है। हालांकि, सलमान ने अभी तक इस फिल्म के लिए अपनी डेट्स नहीं उपलब्ध कराई है। अब खबरें हैं कि अनीस ने इस फिल्म के लिए अभिनेता वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ से बात की है। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर और अनीस बीते करीब छह महीनों से लगातार इस फिल्म को लेकर इन तीनों अभिनेताओं से बातचीत कर रहे हैं। तीनों को फिल्म की पटकथा पसंद आई है और उन्होंने फिल्म के लिए अपनी स्वीकृति भी दे दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो दिसंबर से इस फिल्म की शूटिंग शुरु हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अनीस सीक्वल फिल्म में मूल फिल्म के कितने कलाकारों को वापस लाते हैं और कितने नए चेहरे शामिल करते हैं।

इस फिल्म में पहली बार एक साथ आ सकते हैं अर्जुन और वरुण। फाइल

एनिमल के सीक्वल एनिमल पार्क के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एनिमल की सफलता को देखते हुए मेकर्स कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते।

अगले साल होगी एनिमल पार्क की शूटिंग

रश्मिका मंदाना के पात्र की कहानी भी आगे बढ़ेगी एनिमल पार्क में ● मिडडे आर्काइव

अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म एनिमल की सफलता ने इसके मेकर्स और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा पर यकीनन दबाव बढ़ाया है। ऐसे में इस फिल्म के सीक्वल पर काम पूरी तैयारी के बाद अगले साल ही शुरू हो पाएगा। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार फरवरी से एनिमल पार्क की कहानी का लेखन शुरू होगा। जबकि फिल्म की शूटिंग अगले साल ही शुरू हो पाएगी। संदीप अगले कुछ महीनों तक प्रभास के साथ अपनी फिल्म स्पिरिट की शूटिंग में व्यस्त रहेंगे। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार जब एनिमल फिल्म लिखी जा रही थी तभी एनिमल पार्क का एक खाका भी तैयार कर लिया गया था। जैसा कि पहला पार्ट रणबीर कपूर के किरदार रणविजय और उसके हमशक्ल पात्र पर समाप्त किया गया था। ऐसे में दूसरा पार्ट उन्हीं दोनों किरदार के आसपास घूमेगा। वहीं फिल्म के नायक रणविजय और उसकी पत्नी गीतांजलि के बीच के झगड़ों को समेटते हुए कहानी आगे बढ़ेगी। साथ ही रणविजय के साथ उसके बेटे का रिश्ता भी दिखाया जाएगा। अगले साल शूटिंग करने के लिए रणबीर भी तैयार होंगे तब तक वह नितेश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म रामायण की शूटिंग भी पूरी कर लेंगे।

जल्द ही मुंबई में शुरू होगी वार 2 फिल्म की शूटिंग

साल 2019 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में रही सिद्धार्थ आनंद निर्देशित वार का अंत कुछ इस तरह से हुआ था कि उसके बाद से ही फिल्म के सीक्वल की चर्चा होने लगी थी। वार में अभिनेता रितिक रोशन और टाइगर श्राफ मुख्य भूमिकाओं में थे। अब करीब पांच साल बाद इसकी सीक्वल फिल्म वार 2 की शूटिंग शुरू होने जा रही है। सीक्वल फिल्म का न सिर्फ निर्देशक बदला है, बल्कि इसमें कुछ नए चेहरे दिखाई देंगे। निर्माता आदित्य चोपड़ा की स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में से एक वार 2 का निर्देशन अयान मुखर्जी करेंगे। फिल्म में दक्षिण भारतीय अभिनेता जूनियर एनटीआर के खलनायक तथा कियारा आडवाणी के मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में होने की खबरें हैं। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म की शूटिंग फरवरी के दूसरे सप्ताह से मुंबई में शुरू हो जाएगी। जिसके लिए एक विशाल सेट स्थापित किया जा रहा है। निर्देशक अयान ने करीब दो महीने पहले ही शूटिंग के लिए आवश्यक स्थानों का चुनाव कर लिया था। फिल्म के कलाकारों ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। वार की तरह वार 2 को भी देश के साथ-साथ कुछ विदेशी स्थानों पर शूट किया जाएगा। अयान ने इसके लिए विदेशी स्थानों का चुनाव भी कर लिया है। सिद्धार्थ के निर्देशन में बनी वार ने तो टिकट खिड़की पर काफी अच्छा प्रभाव छोड़ा था, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अयान भी वार 2 के जरिये वैसा ही जादू बिखेर पाने में कामयाब होते हैं या नहीं?

वार 2 में खलनायक बनेंगे जूनियर एनटीआर ● मिडडे

अब जिम्मी शेरगिल बने मिस्टर सक्सेना

निर्देशक और कलाकार अगर किसी प्रोजेक्ट पर एकदूसरे के साथ सहज हो जाएं और काम अच्छा निकलकर आ जाए, तो उनके साथ काम करने के मौके बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है चूना वेब सीरीज के निर्देशक पुष्पेंद्रनाथ मिश्रा और अभिनेता जिम्मी शेरगिल के साथ। चूना वेब सीरीज के बाद पुष्पेंद्र ने जिम्मी के साथ एक और शो की शूटिंग पूरी कर ली है। इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, 'जिस शो पर हम काम कर रहे हैं, उसका नाम मिस्टर सक्सेना है। फिलहाल उसकी एडिटिंग पर काम चल रहा है। फिल्म की शूटिंग लगभग 80 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। इस कहानी का निर्माण चूना वेब सीरीज की ही टीम ने किया है। इस स्पोर्ट्स ड्रामा कामेडी शो में जिम्मी शीर्षक भूमिका में होंगे। इस काल्पनिक कहानी में खेल बैकग्राउंड में होगा, जबकि रिश्ते केंद्र में होंगे। भाई-बहनों के रिश्तों की कहानी है।' यह सीरीज किस प्लेटफार्म पर आएगी, यह फिलहाल शो की टीम ने तय नहीं किया है।

डिजिटल प्लेटफार्म पर लगातार काम कर रहे हैं जिम्मी ● मिडडे आर्काइव

विभाजन के दौर में ले जाएगी फिल्म

फिल्म मिलन होगा कब जाने के निर्देशक हैं आकाशादित्य लामा ● स्वयं

साल 1947 में हुए भारत-पाकिस्तान विभाजन की घटना को पृष्ठभूमि में रखते हुए हिंदी सिनेमा में अर्थ, पिंजर और गदर जैसी कई फिल्में बनी है। सभी में फिल्मकारों ने उस दौर के अलग-अलग दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। फिल्म तौबा तेरा जलवा के निर्देशक आकाशादित्य लामा ने भी इस पृष्ठभूमि पर फिल्म मिलन होगा कब जाने बनाई है जो कि मूल रूप से एक प्रेम कहानी हैं। इस फिल्म के बारे में आकाशादित्य बताते हैं, 'मेरी अगली पीरियड ड्रामा फिल्म में बंगाल की कहानी दिखाई गई है, जो दर्शकों को विभाजन के दौर में ले जाएगी। मूलतः यह फिल्म एक प्रेम कथा है, जिसके इर्द-गिर्द काफी घटनाएं घट रही होती हैं। मैं इस फिल्म का लेखक और निर्देशक होने के साथ निर्माता भी हूं। फिल्म में ओंकार दास माणिकपुरी, आदित्य लखिया, देबोलीना भट्टाचार्जी और अनिल रस्तोगी जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में है।'

****